₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अक्टूबर 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-12988, POSTAL REG. NO. :- PT-35

राजनीति के चाणक्य

नीतीश

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

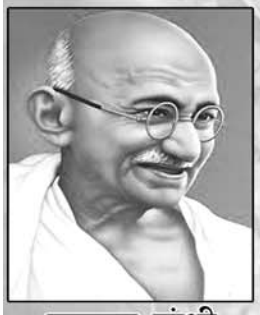

महात्मा गांधी
02 अक्टूबर 1869

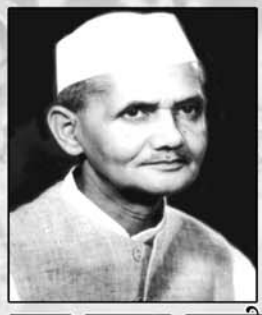

लाल बहादूर शास्त्री
02 अक्टूबर 1904

अभिजीत सावंत
07 अक्टूबर 1981

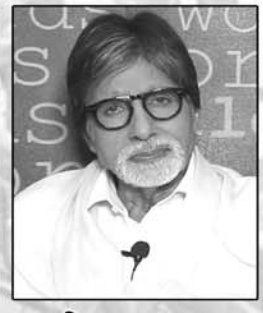

अमिताभ बच्चन
11 अक्टूबर 1942

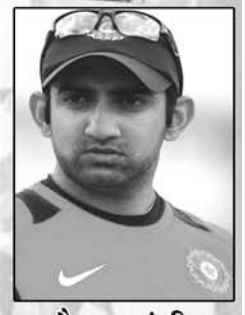

गौतम गंभीर
14 अक्टूबर 1981

स्व०एपीजे कलाम
15 अक्टूबर 1931

नवीन पटनायक
16 अक्टूबर 1946

हेमा मालिनी
16 अक्टूबर 1948

अनिल कुंबले
17 अक्टूबर 1970

वृंदा करात
17 अक्टूबर 1947

सनी देवल
19 अक्टूबर 1956

नवजोत सिंह सिद्धू
20 अक्टूबर 1963

वीरेन्द्र सहवाग
20 अक्टूबर 1978

कादर खान
22 अक्टूबर 1932

परिनीति चोपड़ा
22 अक्टूबर 1988

सुनील भारती मित्तल
23 अक्टूबर 1957

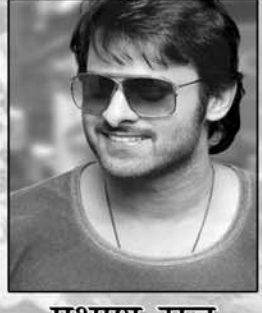

प्रभाश राजू
23 अक्टूबर 1979

रवीना टंडन
26 अक्टूबर 1974

अनुराधा पौडवाल
27 अक्टूबर 1954

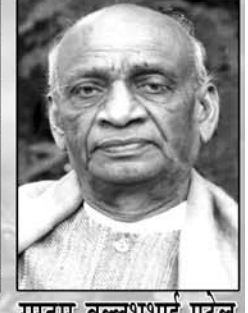

सरदार वल्लभभाई पटेल
31 अक्टूबर 1875

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कांग्रेस का गठन गुलाम भारत में अंग्रेजों के हाथों हुआ था और भीषण संघर्ष एवं बलिदान के बाद भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था और पंडित जवाहर लाल नेहरू कूटनीति एवं राजनीति और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावनात्मक शिकस्त देते हुए प्रथम प्रधनमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए थे और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपनी हुकूमत को चलाती आयी है लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद एवं संकुचित मानसिकता की वजह से धीरे - धीरे कांग्रेस टूटती गई और कई राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होने और कांग्रेस की नीतियों का विरोध चरम पर आ गया तथा 1974 में ऐसा आन्दोलन हुआ जिसके बाद से कांग्रेस की स्थिति इतनी लाचार हो गयी की उसे सरकार से हांथ धोना पड़ा। जनसंघ के साथ - साथ कई दल ने कांग्रेस के वजूद को नेस्तनाबूत करने की नियत से जनता के बीच ऐसा माहौल बना दिया की देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका तो बिहार लालू की पार्टी जनता दल ने (अब राजद है) देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी पार्टी को अटल बिहारी बाजपेयी की गठबंधन ने इस लायक बना दिया की 2004 से 2014 तक यूपीए बनाकर कांग्रेस से शासन किया लेकिन 2014 में मोदी सरकार (एनडीए) ने कांग्रेस को इतना लाचार बना दिया कि वह अपने बूते 60 सीट का आंकड़ा नहीं पार कर सकी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व ऐसा गठबंधन बनाया है जिसने कांग्रेस को इस लायक बना दिया है

अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है

कांग्रेस

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

अपने घर में आग लगाना और दूसरे घर को बचाना यह काम कोई सन्यासी कर सकता है या फिर सनकी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है भारतीय राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व। 2004 से 2014 तक 10 साल गठबंधन की सरकार चलाने वाली कांग्रेस खुद ही अपने घर में आग लगा चुकी है तथा 2014 से 2024 तक दूसरे के चक्कर में सत्ता तो दूर मजूबत विपक्ष भी नहीं बन पा रही है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति देश में क्षेत्रीय दल की तरह बनी जा रही है और इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। 1947 से लेकर 1995 तक सत्ता के केन्द्र में रहने वाली कांग्रेस को भारत के अन्य राज्यों में सक्रिय राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां ही आंख दिखा रही है और वह खुद उनके सामने वैशाखी के सहारे है जैसा बनती जा रही है। एक तरफ नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रचंड प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद पीएम मटेरियल है के बजाय किसको पीएम मटेरियल बनाया जाये पर विचार करने में ही कन्फ्यूज है। बिहार में नीतीश - लालू आंख दिखा रहे हैं, उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में केजरीवाल तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का अपना जलवा है वैसे में मजबूत विपक्ष लायक भी सीट पर लड़ने नहीं देना चाहते हैं नये इंडिया गठबंधन के लोग। देश की आजादी के वक्त कांग्रेस का वजूद जहां 100 प्रतिशत था वह आज 10प्रतिशत में सिमट गया है। पूर्व के कालखंड में किये गये कार्य के कारण राहुल गाँधी एवं प्रियंका गांधी को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रस के समय किए गये भ्रष्टाचार एवं धर्म की कूटनीति पर मोदी की सरकार हावि होती जा रही है तथा कांग्रेस से अलग होकर बनी छोटी-छोटी पार्टियां ही कांग्रेस की राजनीतिक कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 1980 में पार्टी बनी भाजपा को 1984 में भाजपा की महज 02 सीट हासिल हुई थी जिसपर कांग्रेस उपहास करता था जबकि 1974 के आन्दोलन सफल होने के बाद 1977 में इंदिरा गांधी के विरोधी कई दलों ने एकजुट होकर दल बनायी जिसमें जनसंघ एवं भारतीय लोकदल कांग्रेस जैसी कई पार्टियां पहले ही चुनाव में 295 सीट पर जीत दर्ज की लेकिन 2 साल में ही ही इंदिरा गाँधी की आंधी में जनता पार्टी टूट गई और बड़े-बड़े नेताओं ने अपना-अपना दल का गठन बना लिया लेकिन कोई चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं आये। कांग्रेस को 1952 में 401 में से 364 सीटें, सन् 1957 में 403 में से 371 सीटें हासिल की और इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 543 सीटों में 415 सीट पर जीत दर्ज की लेकिन इसके बाद धीरे - धीरे राजीव गांधी ने कमान संभाली लेकिन दल के भीतर के विभिषण के प्रहार के कारण तथा बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस धीरे-धीरे जनता के बीच अपना जनाधार को कमजोर करने में खुद ही हिस्सेदार बन गयी और राजीव गाँधी की हत्या के बाद कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों ने डंसना शुरू किया। एक तरफ कांग्रेस जहां कमजोर होती जा रही थी तो दूसरी तरफ आरएसएस एवं भाजपा का जधानाधार बढ़ने लगा और जब लालकृष्ण आडवाणी एवं अटल बिहारी वाजपेयी ने राम मंदिर के निमार्ण (धर्म की राजनीति) को लेकर जनता के बीच जाने लगे तो कांग्रेस कमजोर से लाचार होने लगी। एक तरफ राष्ट्रीय पटल पर भाजपा का जनाधार बढ़ने लगा तो दूसरी तरफ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की सरकार को धीरे-धीरे उखाड़कर फेकने लगी और जब भाजपा के नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने गठबंधन राजनीति को महत्व दिया तो उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व विहिन होने लगा और कांग्रेस के भीतर ही कई विचारधारा काम करने लगा। अकेले दम पर देश की राजनीति करने वाली कांग्रेस पिछले 30 वर्ष में न सिर्फ कमजोर हुई बल्कि भीतरघात की वजह से लाचार हो गयी है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार की वजह से अन्य पार्टियां कांग्रेस को सीट शेयरिंग में मजबूर कर रही हैं। कांग्रेस बिहार हो या यूपी अगर 120 सीट में से 20 सीट पर अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या वह पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? राहुल गाँधी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस का स्कोप बढ़ा है लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपना नेता मानने के बजाय चुनाव में किसी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती है, वैसे में कांग्रेस अगर 26 दलों से सीट पर उनके - उनके राज्यों में समझौता कर लेती है तो 2024 के चुनाव में सरकार बनाना तो दूर मजबूत विपक्ष बन जाये यह भी चुनौती है। कांग्रेस को जितना खतरा भाजपा से है उससे कहीं ज्यादा अपने घटक दल से है। राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में कांग्रेस के भीतर खुद काफी कलह है जिसके कारण से भाजपा की सरकार हार के बाद भी 2018 में मध्यप्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो गयी। 1984 में 543 लोकसभा सीट में 415 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 2024 के चुनाव में कितने सीट पर उनके घटक दल चुनाव लड़ने देते हैं, यह देखना शेष है। कांग्रेस खुद ही चुनाव के पहले भाजपा एवं अपने गठबंधन के सामने हथियार डाल चुकी है।

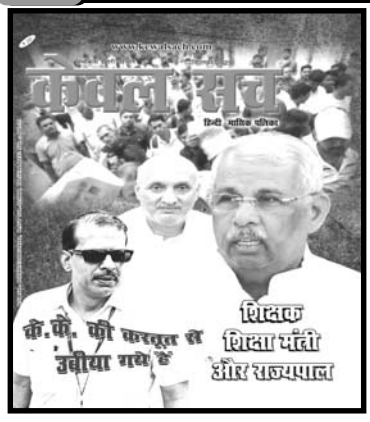

सितम्बर 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

व्यापार

संपादक जी,

वर्त्तमान समय में धर्म एवं राजनीति के साथ-साथ कथावाचक भी धर्म के व्यापार में शामिल होते जा रहे हैं। सितम्बर 2023 अंक का संपादकीय ''कथावाचक एवं कवियों का बढ़ता व्यापार'' में आपने आज का सच एवं धर्म के साथ साहित्य को भी आईना दिखाने का काम किया है। कथावाचक एवं कवियों को राष्ट्रवाद एवं सनातन संस्कृति के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाने में काफी सहयोग मिल रहा है और सरकारी खजाने में टैक्स भी जमा नहीं कराते तथा भावनाओं का व्यापार करने में कामयाब हो रहे हैं।

✦ **रमेश सिंह, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

विशेष सत्र

ब्रजेश जी,

नये संसद भवन में कार्य प्रारंभ हो गया यह सुखद सदेश है। सितम्बर 2023 अंक में सिद्धांत मोहन की खबर ''संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार कौन-कौन से बिल लाने वाली है?'' में बहुत सटीक एवं उपयोगी जानकारी मिली है। न्यायालय एवं पत्रकारिता से संबधित बिल पास भी होगा जिससे न्यायालय में दलालों पर नकेल कसा जायेगा तथा आरएनआई को भी निबंधन रद्द करने का अधिकार होगा। केवल सच पत्रिका अपने नाम के अनुरूप खबर भी लिखती है सबूत के साथ। सही खबर है।

✦ **मनोहर लाल वर्णवाल, टावर चौक, मुंगेर**

सनातन

मिश्रा जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को पढ़ता हूं। सितम्बर 2023 अंक में अमित कुमार की खबर ''सनातन की दोगली उत्पत्ति'' में राजनीति का दोगलापन पर काफी कटाक्षपूर्ण खबरों को पूर्ण बेबाकी के साथ लिखा है। देश के भीतर धार्मिक उन्माद भड़काने वाले तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि ने सनातन धर्म को वायरस कहकर अपमानित कर दिया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में स्वत: संज्ञान नहीं लिया लेकिन नुपूर शर्मा के मामले में अविलंब सक्रिय हो गयी। दमदार एवं राजनीति का बखिया उखेड़ने वाला खबर है।

✦ **किसलय शर्मा, कटहल मोड़, राँची**

अफवाह या हकीकत

मिश्रा जी,

सितंबर 2023 अंक में अमित कुमार की खबर ''**इंडिया बनेगा भारत, अफवाह या हकीकत**'' में देश का नाम इंडिया और भारत के विषय में विस्तार के साथ पाठकों को समझाने का सराहनीय प्रयास है। संविधान के तथ्यों को भी आलेख में विशेष स्थान दिया गया है। राजनीतिक एवं कानूनी विषय को भी देश के नाम के विषय में लिखा गया है। खबर काफी जानकारीप्रद एवं पठनीय और संग्रहणीय है। केवल सच, पत्रिका का आलेख बहुत ही सटीक है और इस अंक का सभी खबर बेजोड़ है। केवल सच को रंगीन पृष्ठ में प्रकाशित करवाया जाये।

✦ **रौशन पाठक, गाँधी नगर, नई दिल्ली**

प्रभार

संपादक जी,

राँची का नये एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। सितम्बर अंक में पत्रकार ओमप्रकाश की सभी खबरों को पढ़कर बहुत सारी जानकारी मिली। झारखंड के अपराध के साथ राजनीति से जुड़ी खबरो को भी प्राथमिकता से प्रकाशित करने से इसके पाठक बढ़ेंगे। बिहार एवं देश के कई राज्यों की राजनीतिक खबर भी पठनीय है। राँची के डीडीसी दिनेश यादव का साक्षात्कार भी बढ़िया है। इस अंक का कानूनी सलाह भी जानकारीप्रद है। केवल सच की खबर पाठकों को खूब भाती है क्योंकि इसकी भाषा काफी सरल है।

✦ **महेश मुंडा, गाड़ी गांव, खेलगाव, राँची**

करतूत

संपादक जी,

बिहार में शिक्षा विभाग मे अपर मुख्य सचिव के के पाठक के सक्रियता की वजह से पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग चर्चा के केन्द्र में हैं। सितम्बर 2023 अंक में शशि रंजन सिंह की खबर ''के के की करतूत से उबीया गये हैं, शिक्षक, शिक्षामंत्री और राज्यपाल'' में शिक्षा विभाग के भीतर का सच को उजागर करके सटीक जानकारी पाठक एवं विभाग को भी दिया है। के के पाठक के कारण कई आईएएस की भी परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसी खबर को प्रत्येक अंक में स्थान दिया जाये ताकि देश की जनता को सच सबूत के साथ पता हो।

✦ **प्रमोद सहाय, इंदिरा नगर, पोस्टल पार्क, पटना**

अन्दर के पन्नों में

27

40

पटरी टूटने से नॉर्थ इस्ट एक्सप्रेस.....70

84

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 209, | माह:- अक्टूबर 2023, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505/8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानन्द राय 9905250798

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

वित्त संपादक

कामोद कुमार कंचन 8971844318

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

बिरेन्द्र सिंह 7050383816

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक
राजीव कुमार 9431369995, 7280999339

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

झारखण्ड सहायक संपादक
ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक
अजय कुमार 8409103023, 6203723995

संयुक्त संपादक
शशि भूषण 7061052578, 9905643374

विशेष प्रतिनिधि
भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

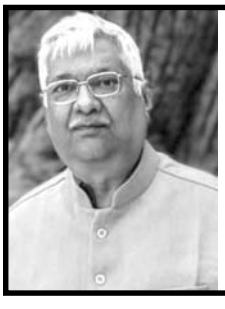

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

राजनीति के चाणक्य नीतीश पहले ही भांप ली थी अतिपिछड़ों की ताकत

● अमित कुमार

'नाम-धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन?' ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो आज की सियासत में एकदम फिट बैठती हैं। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी शायद यही कह रही हैं कि बीजेपी से लड़ना हो तो मत गहो मौन, बताओ कि तुम जाति हो कौन? ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आकड़ें जारी कर दिए हैं। क्या जाती किसी व्यक्ति की ताकत हो सकती है? बिहार में आयी जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद शायद इस प्रश्न का उत्तर होगा; हां। बता दें कि 27 फरवरी 2020 को एनडीए की सरकार में बिहार विधानसभा से जाति आधारित गणना का प्रस्ताव पारित हुआ। करीब 3 साल बाद 7 जनवरी 2023 से जातीय सर्वे का काम शुरू हुआ और 9 महीने बाद आज बिहार में कौन जाति के लोग हैं? हिंदू-मुसलमानों की संख्या कितनी है? अगड़े-पिछड़े कितने हैं? ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, तेली, बनिया सब की आबादी वाली ताकत इस रिपोर्ट के आने के बाद सामने आ गई है। जातीय रिपोर्ट में आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं की आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। बिहार में सर्वण महज साढ़े दस फिसदी के आसपास हैं। आसान भाषा में बिहार में आबादी की एबीसीडी को समझा जा सकता है। बिहार में जातीय हिस्से का पूरा हिस्सा आंकड़ों के साथ है कि कितने हिंदू, कितने मुसलमान, तो इसका जवाब बेहद आसान होगा। सनद् रहे कि लोकसभा चुनाव 2024 का काउंडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष को इंडिया गठबंधन के पहले एकजुट करने वाले सीएम नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव में लड़ाई आमने-सामने की है, लिहाजा सीएम नीतीश कुमार चुनावी विसात बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। गौरतलब हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिये। बता दें कि इस खबर के माध्यम से आसान भाषा में न केवल बिहार में आबादी की एबीसीडी को समझेंगे, बल्कि इस खबर में जातीय गणना की रिपोर्ट के साइडइफेक्ट भी जानेंगे।

सबसे पहले समझना होगा कि बिहार में हिंदू-मुसलमान कितने हैं? तो बता दें कि हिंदुओं की आबादी 81.99 फिसदी है। इस हिसाब से उनकी जनसंख्या 10 करोड़ 71 लाख 92 हजार 958 है तो वही इस्लाम धर्म के मानने वालों की आबादी 17.70 फिसदी है। इसके हिसाब से मुसलमानों की जनसंख्या बिहार में 2 करोड़ 31 लाख 49 हजार 925 है। ईसाई धर्म 0.05 प्रतिशत है, आबादी 75 हजार 238 है। सिख धर्म 0.011 प्रतिशत है, आबादी 14 हजार 753 है। बौद्ध धर्म 0.0851 प्रतिशत है, आबादी 1 लाख 11 हजार 201 है। जैन धर्म 0.0096 प्रतिशत है। आबादी 12 हजार 523 है। अन्य धर्म 0.1274 प्रतिशत है, आबादी 1 लाख 66

जातिगत आंकड़ों ने खींच दी 2024 के समर की रूपरेखा

हजार 566 है। वहीं, कोई धर्म नहीं 0.0016 प्रतिशत है, आबादी के लिहाज से 2 हजार 146 है। मतलब नई जनगणना रिपोर्ट यह बताती है कि बिहार में हिंदुओं की आबादी घटी है जबकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। पहले मुसलमान की आबादी 16.9 फिसदी थी, जो बढ़कर 17.70 फिसदी हो गयी। वही दूसरे किसी धर्म की आबादी 1 फिसदी से भी कम है। अब जातीय गणना की एक रिपोर्ट पर गौर करे, जिससें बिहार की आबादी की जातीय हिस्सेदारी पता चलेगी। बिहार में पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी 27. 12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52% है। इस हिसाब से बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ है। इस आंकड़े को देखकर समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। अब इन आंकड़ों के मुताबिक यादव 14.26%, कुशवाहा 4.2%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, बनिया 2. 3%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.6%, बढ़ई 1.45%, नोनिया 1.9%, नाई 1.59% है। बिहार में हिस्सेदारी के हिसाब से यादवों की संख्या 14% से ज्यादा है जबकि बिहार कुल सर्वणों की संख्या 10. 56% है। इनमें ब्राह्मण-राजपूत तो 4% भी नहीं है। भूमिहार करीब 3% के आसपास है और कायस्थों की आबादी आधे फिसदी से थोड़ा ज्यादा है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट तो जारी हो गई है लेकिन इस रिपोर्ट से किसे क्या फायदा होगा, यह सवाल सबसे जरूरी है। इस रिपोर्ट के बाद जो लाभ होगा उसमें पहला तो यह कि आरक्षण का लाभ देने में सहूलियत होगी। नए आंकड़ों से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का सही पता चल पाएगा। नई योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करने में सहुलियत होगी। वही जातीय जनगणना से फायदे की दलिलों को समझने के बाद अब इसके साइडइफेक्ट भी जान लेना जरूरी है। जो साइडइफेक्ट हो सकते हैं उनमें पहला कि समाजिक तानाबाना को नुकसान हो सकता है। जाति, वोट बैंक के सेंटर में होगी। राजनीतिक पार्टियां ज्यादा संख्या वाली जाति को लुभाने की कोशिश करेंगे। कम तादाद वाली जातियों में जनसंख्या बढ़ाने की होड़ मच सकती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट का असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा।

जातीय जनगणना एक नजर में

यादव	:	14.2666 प्रतिशत
कुर्मी	:	2.8785 प्रतिशत
कुशवाहा	:	4.2120 प्रतिशत
ब्राह्मण	:	3.6575 प्रतिशत
भूमिहार	:	2.8683 प्रतिशत
राजपूत	:	3.4505 प्रतिशत
मुसहर	:	3.0872 प्रतिशत
मल्लाह	:	2.6086 प्रतिशत
बनिया	:	2.3155 प्रतिशत
कायस्थ	:	0.60 प्रतिशत
वर्ग के हिसाब से		
अति पिछड़ा वर्ग	:	36.01 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	:	27.12 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	19.6518 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	1.6824 प्रतिशत
सवर्ण	:	15.5224 प्रतिशत
धर्म से जुड़े आंकड़े		
हिंदू	:	81.9 प्रतिशत
मुसलमान	:	17.7 प्रतिशत
ईसाई	:	0.0576 प्रतिशत
सिख	:	0.0113 प्रतिशत
बौद्ध	:	0.0851 प्रतिशत
जैन	:	0.0096 प्रतिशत
बिहार की कुल जनसंख्या		**: 13 करोड़ 07 लाख, 25 हजार 310**

बताते चले कि 2 अक्टूबर को जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। बहरहाल, जातीय जनगणना हो चुकी और इसके आंकड़े भी अब पब्लिक डोमेन में हैं। सत्ताधारी महागठबंधन जातीय जनगणना के आंकड़े को जारी कर जहां अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं भाजपा अब बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जातीय जनगणना में झोल करने के भी आरोप लगा दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जातीय जनगणना चुनावी फायदे के लिए कराया गया है-एक तरह से बिहार का जातीय समीकरण मुस्लिम+यादव बनाम ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, कुशवाहा, कायस्थ और मुसहर की लड़ाई में बदलता जा रहा है। इस तरह अति पिछड़ा वर्ग और दलितों के पास सत्ता की चाबी रहने वाली है, तो एक नजर सभी दलों या गठबंधनों को होने वाले नफा नुकसान पर भी डाल लेते

एमवाई समीकरण

हैं। सबसे पहले सत्ताधारी गठबंधन यानी महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में राजद, जेडीयू और कांग्रेस के अलावा वामदल शामिल हैं। राजद के वोट बैंक की बात करें तो यादव और मुस्लिम इसका सबसे बड़ा आधार है। राजपूतों का एक वर्ग भी राजद को वोट देता आया है। जेडीयू वैसे तो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है पर मुस्लिमों को लुभाने में यह कभी पीछे नहीं रही। इसका कोर आधार वोट बैंक कुर्मी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कुशवाहा वोट बैंक जेडीयू से खिसक गया है और बिहार में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में यह प्रमाणित भी हो चुका है। कांग्रेस की बात करें तो पहले उसका वोट बैंक सवर्णों के अलावा दलितों और मुस्लिमों का हुआ करता था पर अब वह बीते जमाने की बात हो गई है। बिहार में कांग्रेस शुद्ध रूप से राजद और जेडीयू के वोट बैंक पर निर्भर है। कम्युनिस्ट पार्टी का

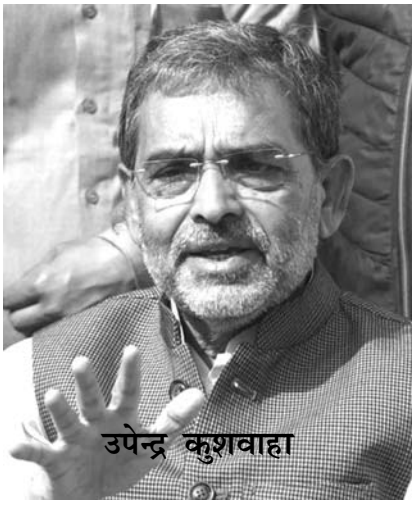

उपेन्द्र कुशवाहा

जातिगत आधार पर कोई वोट बैंक नहीं है लेकिन सभी वर्गों में एक छोटा तबका वाम दलों से नजदीकी रखता है। कुल मिलाकर महागठबंधन का वोट बैंक 17 प्रतिशत मुसलमान, 14 प्रतिशत यादवों के अलावा 2 प्रतिशत कुर्मी होते हैं। यह बिहार की कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत होता है। अब बात करते हैं एनडीए के वोट बैंक की। एनडीए में मुख्य दल भाजपा के अलावा लोजपा के दोनों धड़े, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल हैं। भाजपा पहले सवर्णों और बनियों की पार्टी कही जाती थी पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछड़े वर्ग में इसका आधार बहुत बढ़ा है। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आने और सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कुशवाहा वोट बैंक भी एनडीए की ओर आया है। प्रतिशत में देखें तो कुशवाहा 4 प्रतिशत, ब्राह्मण 3 प्रतिशत, भूमिहार 2 प्रतिशत, बनिया 2 प्रतिशत, मुसहर 3 प्रतिशत और कायस्थ 0.6 प्रतिशत सॉलिड रूप से एनडीए के साथ हैं। इसके अलावा राजपूतों में से एक धड़ा एनडीए को वोट देता आया है। वर्गों के हिसाब से देखें तो 36.01 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग, दलित 19 प्रतिशत, वनवासी समुदाय का 1 प्रतिशत और सवर्ण 15 प्रतिशत भाजपा और एनडीए के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। महागठबंधन के पास यादव, कुर्मी और मुसलमानों का ठोस वोटबैंक है तो एनडीए के पास टुकड़ों में वोट बंटे हुए हैं। स्थानीय स्तर पर या फिर उम्मीदवार के हिसाब से महागठबंधन एनडीए के वोटबैंक में सेंध लगा सकता है, लेकिन एनडीए उम्मीदवार के स्तर पर भी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि यादव और मुसलमान राजद छोड़कर कहीं नहीं वोट करने वाले तो कुर्मी भी नीतीश कुमार को लेकर निष्ठावान हैं। महागठबंधन के साथ एक दिक्कत यह है कि यादव जहां जाएंगे, बाकी पिछड़े दल उससे किनारा कर लेंगे। लालू प्रसाद यादव का 'एमवाई' समीकरण अब बिहार में जिताउ समीकरण नहीं रहा, जब तक कि दूसरे वर्गों का थोड़ा बहुत अंशदान राजद को नहीं मिल जाता। यही कारण है कि राजद 2005 के बाद से अब तक सत्ता से दूर ही रही है।

गौरतलब है कि जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्स-रे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देनी है। सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। ये बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कहीं। इसके दो दिन पहले एक प्रेस

सम्राट चौधरी

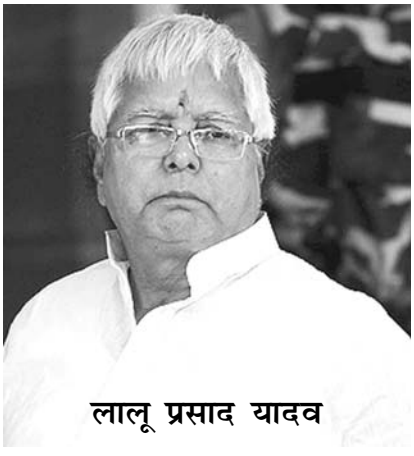
लालू प्रसाद यादव

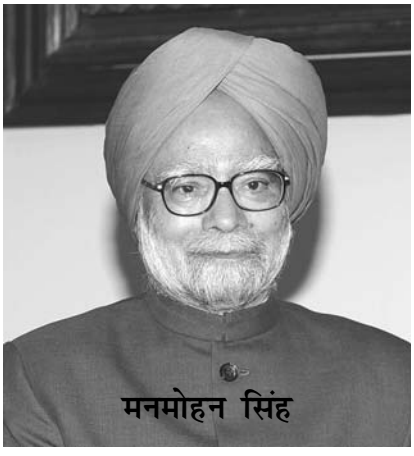
मनमोहन सिंह

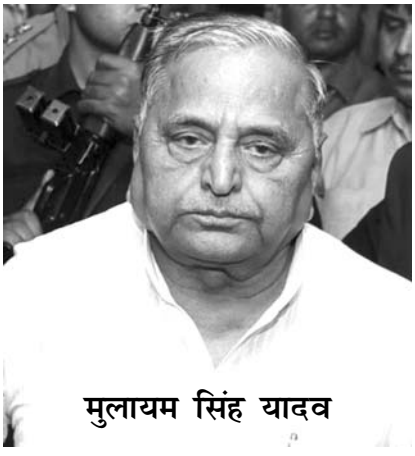
मुलायम सिंह यादव

कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को भी लाभ मिलना चाहिए। साथ ही 2010 में यूपीए सरकार के महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा शामिल नहीं करने पर खेद भी जताया। राहुल के बयान से साफ हो गया था कि विपक्षी दल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे। इसके ठीक 6 दिन बाद बिहार सरकार ने जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी कर दी। इसके साथ ही बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। इससे पहले देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक न ही देश के स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े जारी हुए थे। हालांकि 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता कांशीराम ने की। तब भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देशभर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इसके लिए 4 हजार 389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? एसइसीसी का डेटा 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रॉसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती, तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेटा में 46 लाख कास्ट, सब कास्ट हैं। इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। 2016 में जातियों को छोड़कर एसइसीसी का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ, लिहाजा इस वजह से कभी मीटिंग ही नहीं हुई। इसलिए जनगणना में जुटाए जातियों के आंकड़े जस के तस पड़े हैं, यानी जारी ही नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4,147 थी, एसइसीसी-2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई हैं। चूंकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन हैं। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। इसमें केंद्र सरकार को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस यानी ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि 2021 की जनगणना में ही ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सही-सही स्थिति सामने आ सके। इस याचिका में केंद्र सरकार से अदर बैकवर्ड

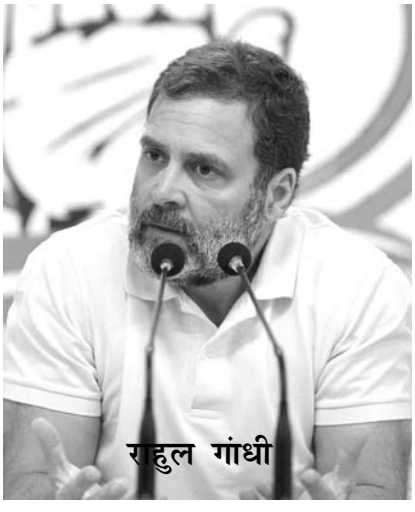
राहुल गांधी

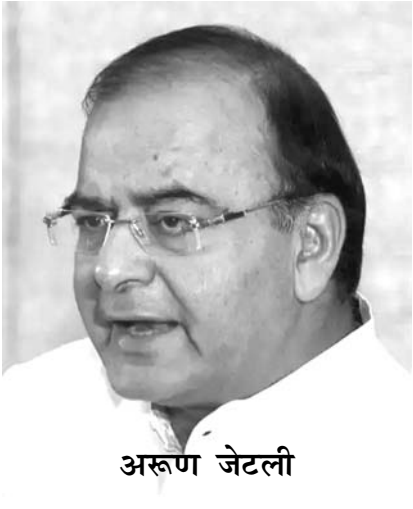
अरूण जेटली

क्लासेस यानी ओबीसीएस पर एसइसीसी-2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अब सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उद्धव सरकार की पिटीशन पर केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में 3 प्रमुख बातें कही थीं, जिनमें :-

1. यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए।
2. जाति आधारित जनगणना कराना व्यावहारिक नहीं है।
3. प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है।

बहरहाल, मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। आरजेडी व जेडीयू ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबर्दस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में निचले ओबीसी को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए बीजेपी ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है, जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। दिगर बात है कि बीजेपी का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल-2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रहीं क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमती का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं, इसके

अलावा बीजेपी का परंपरागत हिन्दू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। वही मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ओबीसी वोट को नाराज होने से बचाना बड़ी चुनौती है। कई सर्वे इशारा करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी जातियों में तेजी से पैठ बढ़ाई है। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो 10 साल में दोगुने हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 के 42% वोटों से घटकर 27% रह गया। जाति के अधार पर जनगणना की बात संवेदनशील मामला है। हमारे देश में अभी तक का इतिहास रहा है कि अगर इस तरह की जनगणना होती है तो उसी आधार पर आरक्षण की और दूसरी चीजों की मांग होने लगेगी। ये संख्या के आधार पर होगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने लगेगी। कांग्रेस और बीजेपी जैसे मुख्य राजनीति दलों की एक दुविधा है। वो पिछड़े, अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से बीजेपी भी इससे बचना चाहती है।

सनद् रहे कि ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 की जनगणना का है। इसके बाद 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में जाति जनगणना की मांग से सियासी बवाल मच सकता है। 100 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। किसी भी राज्य में उनकी आबादी 45% से कम नहीं है। कुछ राज्यों में यह 60% से भी अधिक है। जातीय जनगणना होती है तो असली आंकड़ा सामने आएगा। इसके आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना होगा। साथ ही पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27% आरक्षण को उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी तेज होगी। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात ये है कि पुराने समय से ये माना जाता था कि कांग्रेस जाति को सम्मान के भाव से नहीं देखती है। कांग्रेस को लगता था कि जाति से समाज बिखरता है, जुड़ता नहीं है। 2008 से 2010 के बीच जब महिला आरक्षण

का बिल आया था तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, लेकिन इसमें ओबीसी को अलग से आरक्षण देने के समर्थन में नहीं थी। चूंकि अब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं रह गई है, अब I.N.D.I.A. अलायंस हो गया है और इस अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हैं और ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत मुखर हैं। यानी कांग्रेस अब राजद, सपा, जेडीयू और डीएमके के स्वर में बोलने लगी है। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कांग्रेस के अंदर इसे लेकर बहुत डिस्कशन हुआ है। महिला आरक्षण में बहस के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे थे वो सरकार के खिलाफ उकसाने वाली भाषा थी! इसके राजनीतिक मायने हैं। महिला आरक्षण का गुणा भाग 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। कांग्रेस और विपक्ष का आकलन है कि पिछड़े वर्ग का 4 से 5 प्रतिशत मतदाता भी शिफ्ट हो जाता है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है।

गौरतलब हो कि जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गदगद हैं, लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों ने पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डलवाया है। डाका डालने वाले पिछड़े मुसलमान हैं। बिहार में गत् 33 वर्ष से पिछड़ों के नाम पर राजनीति हो रही है। चारा घोटाले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दोनों अपने को सामाजिक न्याय का मसीहा बता रहे हैं। जाति गणना की रिपोर्ट सामने लाकर ये दोनों दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में पिछड़ों को राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में उचित अधिकार मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट को गहराई से पढ़ने पर यह सच सामने आ रहा है कि अब बिहार में पिछड़ों के अधिकारों पर मुसलमानों ने सेंध लगा दी है। मुसलमानों की आबादी बिहार में बढ़ी है। 2011 की जनगणना में बिहार में हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। अब बिहार में करीब 82 फीसदी हिंदू और 17.7 प्रतिशत मुसलमान हैं। मुसलमानों में यह बढ़ोतरी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति की श्रेणी में हुई है। मुस्लिम समुदाय में अगड़े (असरफ) की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 5 प्रतिशत थी, जो घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई है। अगड़ी जातियों में शेख, सैय्यद और पठान आते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या शेख की है। बिहार में 3.82 प्रतिशत शेख, 0.75 प्रतिशत पठान और 0.23 प्रतिशत सैय्यद हैं। बिहार में पिछड़ों की आबादी 27.12 प्रतिशत है। इसमें मुस्लिम पिछड़ों की संख्या 6.60 प्रतिशत है। मुस्लिम पिछड़ों में अंसारी और सुरजापुरी की संख्या सबसे अधिक है। अंसारी 3.55 प्रतिशत और सुरजापुरी 1.87 प्रतिशत हैं। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत है। इसमें 4.60 प्रतिशत मुस्लिम हैं। अत्यंत पिछड़ा में धुनिया और राईन की संख्या लगभग 2.9 प्रतिशत है। 19.65 प्रतिशत अनुसूचित जाति में 1.7 प्रतिशत मुस्लिम हैं। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या की बढ़ोतरी विशेषकर इन्हीं दो वर्ग पिछड़ा और अति पिछड़ा में हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो समानता की दुहाई देने वाले मुस्लिम समुदाय में भी जबरदस्त विषमता है। सरकारी सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ भी यही लेते हैं। बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों में मुस्लिम समुदाय अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ों में भी सबसे अधिक लाभ इन्हें मिलता है। सनद् रहे कि बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जातिगत जनगणना ने एक सियासी मौका दे दिया है। ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लंबे समय से जुटे हैं। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब हुए थे। अब लोकसभा चुनाव में वह और मजबूती के साथ उतरते दिखाई देंगे। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के पांच विधायकों ने जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में 19 मुसलमान विधायक चुनाव जीते थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के मुस्लिम विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आरजेडी से 8 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे, जबकि पार्टी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। आरजेडी हमेशा से यादव और मुसलमानों की सियासत करती रही है, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। यादवों की तुलना में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद विधायकों की संख्या बहुत ही कम है। यादव समुदाय की आबादी 14 फीसदी है और विधायक 52 हैं। इस तरह से यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व 21 फीसदी से ज्यादा है। वहीं, मुसलमानों की आबादी 17.70 फीसदी है, लेकिन विधायक 19 हैं। इस तरह मुस्लिमों का

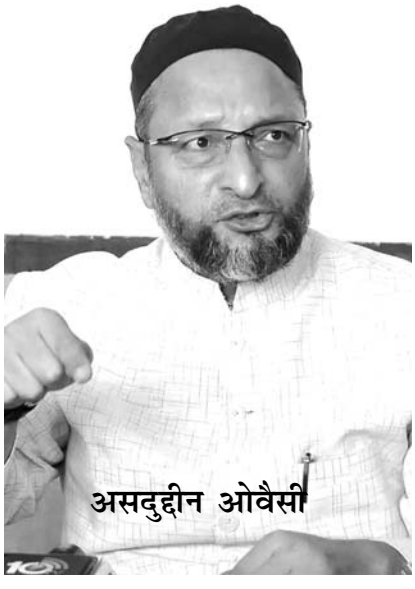
असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम के टिकट पर जीते मुस्लिम विधायक

प्रतिनिधित्व सिर्फ एक फीसदी है। ऐसे में ओवैसी को आरजेडी की मुस्लिम सियासत पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। इसी बहाने वह अपनी सियासत को नई बुलंदी दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी हमेशा से मुसलमानों की नुमाइंदगी को एक बड़ा मुद्दा भी बनाती रही है, महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक। वह कहते रहे हैं कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि राज्य में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व एक फीसदी ही है। हालांकि बिहार में ओवैसी की निशाने पर शुरू से ही लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस पार्टी रही हैं। बिहार की मौजूदा सियासत में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ हैं। ऐसे में महागठबंधन में मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवैसी उसमें सेंधमारी के लिए हरसंभव कोशिश में जुटे हैं। माना जाता है कि मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों से मुसलमान मायूस हैं और वो भरोसेमंद विकल्पों की तलाश में हैं। ऐसे में औवैसी मुस्लिमों को एक सियासी विकल्प देने का दावा करते हैं और उनके जुड़े मुद्दो को धार देने के साथ-साथ उनके प्रतिनिधित्व को उठा सकते हैं। ओवैसी अपनी रैलियों में जोर देकर कहते रहे हैं कि मुस्लिमों को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी जरूरी है। जैसे चरण सिंह ने जाटों के लिए मुलायम सिंह और लालू यादव ने यादवों के लिए और मायावती ने जाटवों के लिए बनाई अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए औवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मजलिस ने शिक्षण संस्थानों से लेकर तमाम विकास किए हैं। इसके अलावा मुस्लिम राजनीति को भी खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह बिहार और यूपी में भी ओवैसी मुस्लिम राजनीति को स्थापित करने की कवायद में हैं। इसीलिए मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ संसद से सोशल मीडिया तक रखते हैं। दरअसल बिहार में ओवैसी की पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में वह एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। जबकि अगले ही विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कमाल कर दिया। इस चुनाव में ओवैसी ने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें 16 मुसलमान थे। पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की। एआईएमआईएम के जो विधायक चुनाव जीते, वह सभी मुसलमान थे। राज्य में यह ओवैसी का सबसे शानदार प्रदर्शन था। बड़ी बात यह है कि ओवैसी ने सभी 5 सीटें सीमांचल इलाके की जीती, जहां मुस्लिमों की अच्छी खांसी आबादी है। खास बात यह रही कि ओवैसी ने इस चुनाव में वह सीटें जीती, जिनपर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार जीत रहे थे, यानी ओवैसी ने महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. पर डबल अटैक करेंगे। एक तो पहले ही वह महागठबंधन में सेंधमारी कर चुके हैं, दूसरी बात यह है कि वह इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं हैं। ओवैसी हमेशा से कहते रहे हैं कि राज्य में मुसलमानों की जितनी आबादी है, उनको उसी हिसाब से नेतृत्व मिलना चाहिए। अगर प्रतिनिधित्व की तुलना की जाए तो यादव, मुसलमानों पर भारी पड़ते हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 52 यादव और 19 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में 14 यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व 21 फीसदी और 18 फीसदी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व एक फीसदी से कुछ ज्यादा है।

बहरहाल, मुसलमानों को आरक्षण बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के विचारों के विपरीत है। बाबा साहब का कहना था कि आरक्षण कभी भी मजहब आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार के जाति आधारित जनगणना पर ध्यान दिया जाए तो 96 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को पिछड़े और अति पिछड़े का दर्जा देकर हिंदू समाज के वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉ. संजय जायसवाल के अनुसार आज बिहार में सिर्फ कहने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। वास्तविकता यह है कि 96 प्रतिशत अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दे दिया गया है। जायसवाल ने कहा कि शेखौरा, कुलहड़िया, शेरशाहबादी, ठकुराई जैसी अनेक जातियां या तो विदेश से आई हैं या फिर अगड़े समाज से कन्वर्जन करके अस्तित्व में आई हैं। इन सभी को अति पिछड़ा का दर्जा देकर संपूर्ण हिंदू पिछड़ा समाज के साथ हकमारी की गई है। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ईसाई आबादी घटी है, जबकि ईसाइयों द्वारा कन्वर्जन के समाचार लगातार सुर्खियों में रहते हैं। सरकार के हिसाब से बिहार में मात्र 75,238 ईसाई हैं। जबकि गत सरकारी जनगणना में ईसाई समुदाय की आबादी 2 लाख थी। फिर 75 हजार कैसे हो गई? ईसाई समुदाय ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को मिला कर ईसाई आबादी 10 लाख से ऊपर हैं। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि क्या पूरे बिहार में केवल 75 हजार 238 ईसाई हैं या बिहार सरकार ने इस मत को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है? बिहार

संजय जायसवाल

नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव

सरकार के अल्पसंख्यक आयोग में अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से ईसाई समुदाय पहले से गुस्से में है। बिहार सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को बिहार के कार्यकारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने पटना में जारी किया। इसके अनुसार बिहार में 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 160 परिवार हैं। इसमें पिछड़े वर्ग की आबादी 27. 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। खास बात यह है कि इस जातीय गणना के आंकड़े में आम जनता को कोई रुचि नहीं है। वही जातीय गणना कराने पर 500 करोड़ रुपए की बर्बादी की गई। इस रुपए से फैक्ट्री लगवा देते तो बिहार से पलायन रुकता। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। कहीं न कहीं इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होगी। हम लोग देश को भारतीय नजरिए से देखते हैं, वहां जातीय नजरिया अपनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जातीय द्वेष को बढ़ावा मिलेगा, जो कहीं से उचित नहीं है। हालांकि जातीय जनगणना की इस रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई है कि पूरे बिहार में यादव बिरादरी की संख्या सबसे ज्यादा है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से अब तक यही माना जा रहा था कि यादव बिरादरी की संख्या वहां अधिक है, लेकिन उसका कोई वैधानिक प्रमाण नहीं था। अब इस रिपोर्ट के बाद वैधानिक रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में 14% आबादी यादव बिरादरी की है, जो सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब हर चुनाव में तेजस्वी यादव का ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बल्कि अन्य दलों के नेता भी उन्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करेंगे। अब बिहार देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, जिसने जातिगत जनगणना कराकर रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दांव खेल दिया है, जो शायद लोकसभा चुनाव में अन्य मुद्दों के साथ यह भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। उधर नीतीश कुमार की इस रिपोर्ट के बाद बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, भाजपा में खलबली मची हुई है। किसी न किसी बहाने से भाजपा इस सर्वे रिपोर्ट में खोट निकालने की कोशिश कर रही है। जबकि जाति आधारित जनगणना करने को लेकर जब बिहार की तत्कालीन सरकार ने 2019-20 में विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया था, तो उसका समर्थन बीजेपी ने भी किया था। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे। आज इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद बीजेपी के नेताओं का कहना है कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां हैं। कुछ नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया है कि सवर्ण जातियों की जनसंख्या ठीक से नहीं दर्शाई गई है। ऐसे आरोप लगाने वाले नेताओं का कहना है कि 2022 में विकिपीडिया ने बिहार में सवर्ण जातियों की जनसंख्या 22% के आसपास बताई थी। जबकि इस बार घटकर वह लगभग 15% हो गई है। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों की है। इनकी आबादी 36% के आसपास बताई गई है। जबकि ओबीसी की आबादी 27% के आसपास है। जबकि मुस्लिम की आबादी 17 प्रतिशत बताई गई है। राजनीति में वर्षों से एक नारा बड़े ही जोर-शोर से उठाया जाता रहा है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे में अब अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग भी उस नारे को मजबूती से बुलंद करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सवाल यह है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों में ऐसा नेता है कौन, जो अपने हक और अपने भागीदारी की बात को राज्य की जनता के सामने मजबूती से पेश करेगा। बहरहाल इस सर्वे के बाद तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बिहार में और अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे। वैसे भी बिहार में जातिगत आधार पर वोटिंग होने का सिलसिला काफी पुराना है। लाख दावे किए जाएं कि चुनाव फेयर होना चाहिए, लेकिन बिहार, शायद देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर आज भी जातिगत समीकरणों के आधार पर वोटिंग करने का एक पैटर्न बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाता रहा है कि बिहार में वह मुस्लिम+यादव के समीकरण के बलबूते एक लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज होते रहे। आज भी विधानसभा में राजद, अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका यादव+मुस्लिम समीकरण का मजबूत होना ही है। ऐसे में इस सर्वे के बाद एक बात की जानकारी पूरे देश को हो गई कि बिहार में सिर्फ यादव और मुस्लिम समीकरण को ही तेजस्वी यादव ने अगर साध लिया तो पूरे 27% के साथ बिहार में वह सबसे ऊपर हो जायेंगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति के वोटो का 10-12% समर्थन उन्हें मिल गया तो फिर बिहार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से

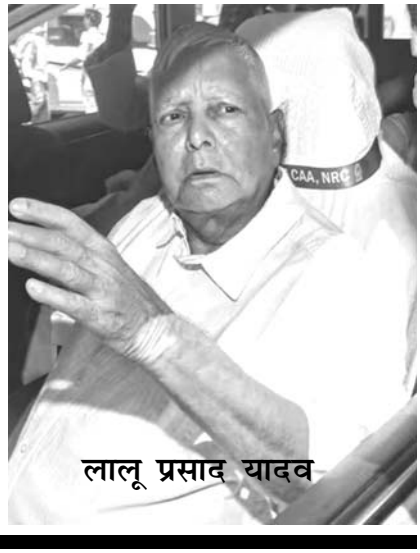

लालू प्रसाद यादव

जातीय गणना की रिपोर्ट पर जदयू सांसद हुए बागी

बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद सियासी बयानबाजी जोरो पर है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किले बढ़ा दी है। बताते चले कि अब तक उनके गठबंधन दलों के कुछ नेता इस आंकड़े पर सवाल उठा रहे थे किन्तु अब उनकी पार्टी जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब हो कि सुनील कुमार पिंटू ने रिपोर्ट आने के बाद बयान दिया था कि तेली, साहू समाज की तादाद 2.81% बताई गई है, यह पूरी तरह से गलत है। इससे कई गुना ज्यादा तेली साहू समाज के लोग बिहार में रहते हैं। पूरे बिहार में तेली साहू समाज की गणना फिर से कराई जाए। वही जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के इस बयान के बाद पार्टी के वो नेता जो मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाते हैं और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने पिंटू पर जमकर बरसा। और तो और उन्होंने भाजपा पर इशारा करते हुए उन्हें यहां तक कह डाला कि वह कहां से गाइड हो रहे हैं यह पता है, जहां से आए वहीं जाने का विचार है उनका। संजय झा ने कहा कि जातीय जनगणना में ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन, वह जाति आधारित गणना पर प्रश्न चिन्ह् लगा रहे हैं वह कहां से गाइड हो रहे हैं यह मुझे पता है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जहां से गाइड हो रहे हैं वहीं से जातीय गणना का सर्वे कर लें। जब जनगणना होगी तो उसमें कास्ट का कॉलम भी जुड़वा दें और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मिला लेंगे क्या सही है क्या गलत।

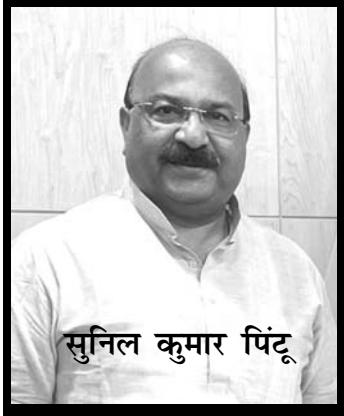
सुनिल कुमार पिंटू

संजय झा

कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों साथ हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में इस सर्वे का असर देश के बाकी राज्यों में भले ना हों, लेकिन बिहार में इस सर्वे का फायदा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। वही जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि हमलोगों ने बिहार जातीय जनगणना करा दिया। अब यह पूरे देश में होना चाहिए। इससे देश के गरीबों और दलितों को लाभ होगा। साथ ही सबको वाजिब हक मिलेगा। जातीय गणना नहीं होने से लोगों को उनका हक नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बसपा सुप्रिमो मायावती ने कहा कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना होने चाहिए, तभी दलितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करानी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज सुर्खियों में हैं और उस पर गहन चर्चा जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, मगर बसपा के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। साथ ही मायावती ने कांग्रेस के 'जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी' वाले बयान को नया चुनावी शगूफा बताते हुए हमला बोला है। मायावती ने जातीय गणना के मामले में भाजपा को भी घेरा है। मायावती ने कहा कि चुनावी माहौल देखकर सभी इसे भुनाने में लगे हैं। बसपा सुप्रीमों ने कहा कि अगले विधानसभा आमचुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व भाजपा द्वारा किस्म-किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, किन्तु प्रश्न यह है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वे पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए? इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम व छलावा ज्यादा। मायावती इतने पर ही चुप नहीं हुई। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, किन्तु कांग्रेस व भाजपा दोनों जातीय गणना, ओबीसी व महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने मे लगी हैं ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सकें। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। साथ ही, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी कांग्रेस का नया चुनावी शिगूफा है। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी व सरकार में इस पर अमल करके दिखाया। नहीं, तो फिर इन पर विश्वास कैसे? जबकि बीएसपी ने पार्टी व अपनी सरकार में इस सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया। वही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जनभावना और जनअपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना, सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, लेकिन इसका सही समाधान तभी होगा, जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। मायावती ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि बसपा को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में नई करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी, एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं।

मायावती

गौरतलब है कि बहुप्रतीक्षित जातिवार

सर्वेक्षण के निष्कर्ष के मुताबिक, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की राज्य की कुल आबादी में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की 27.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है? इसके आंकड़े आ गए हैं। वही इस साल अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस दौरान नारा दिया था-जितनी आबादी, उतना हक। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि सबका साथ-सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। इसी तरह का नारा दलितों के बड़े नेता कांशीराम ने भी दिया था। कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जनगणना में ये नहीं पता चल पाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं। अभी सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के ही आंकड़े आते हैं। ओबीसी जातियों की गिनती नहीं होती। जातिगत जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ये है कि जिस जाति की जितनी आबादी, उसको उतना आरक्षण मिले। वहीं, इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी। अभी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण 1931 में आखिरी बार हुई जाति जनगणना के आधार पर दिया

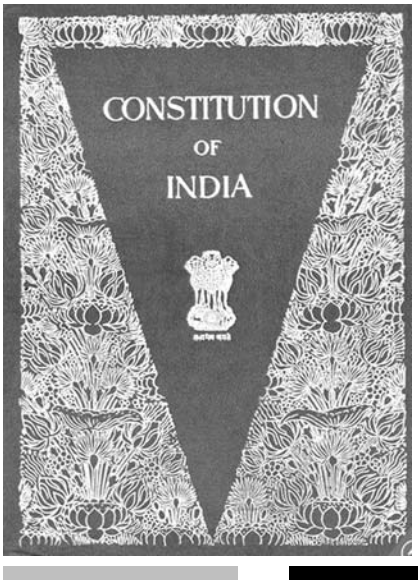

जाता है। 1990 में मंडल आयोग ने 1931 के आधार पर ओबीसी की आबादी 52 फीसदी होने का अनुमान लगाया था। जानकारों का मानना है कि एससी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब बिहार की जातिगत जनगणना में जो आंकड़े आए हैं, उनमें सामने आया है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 63 फीसदी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब आरक्षण बढ़ाने की मांग शुरू हो जाए। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84 फीसदी हैं इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी-उतना हक, ये हमारा प्रण है।

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर 1959 में संविधान में आठवां संशोधन कर आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 1969 में 23वां संशोधन कर आरक्षण बढ़ा दिया। तब से हर 10 साल में संविधान संशोधन होता है और आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ जाता है। साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती। फिलहाल, देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7. 5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलना बीते वर्ष से शुरू हुआ है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार जा चुकी है। हालांकि, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। वही कई राज्य सरकारें पिछड़ी जातियों का दर्जा देकर आरक्षण की सीमा जब-जब पार करती हैं, तब-तब या तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में आरक्षण की 50 फीसदी सीमा की बात दोहरा चुका है। पिछले साल जब नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण को सही ठहराया था, तब भी दो जजों ने इस पर असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 3-2 से 10 फीसदी आरक्षण का समर्थन किया था। 2014 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बनी फडणवीस सरकार ने मराठाओं को 16% का आरक्षण दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। हालांकि, सीमा होने के बावजूद कई राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है। हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण 6 फीसदी बढ़ाया है। अब वहां कुल 64 फीसदी आरक्षण है।

बिडम्बना है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गैरकानूनी कार्यों को छोड़कर सबके लिए कोई भी कार्य करने की छूट है। यह सही

है कि समाज में बहुत सारे मानव समूह जिन्हें आप जातियां या उपजातियां कह सकते हैं, अब भी संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का फल नहीं चख पा रही हैं, इसलिए जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी इन जातियों की पहचान नहीं होगी, तब तक उन्हें मुख्यधारा तक लाने के प्रयास कामयाब नहीं होंगे। पिछड़ी जातियों में भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ी नहीं रह गई उन्हें हटाए बिना अत्यधिक पिछड़ो का भला नहीं हो सकता। बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय गणना के आंकड़ों ने फिलहाल देश में हलचल तो मचा ही दी है। कारण साफ है। देश का सामाजिक तानाबाना लगभग एक जैसा है और समाज के साथ ही शासन प्रशासन में अगड़ी जातियों का वर्चस्व जगजाहिर है। यही अगड़ा वर्ग देश की राजनीति को भी दिशा देता है। बिहार की गणना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ों को मिलाकर उनका कुल योग 63.13 प्रतिशत हो रहा है और उनके साथ अगर मुसलमानों की 17.7 प्रतिशत आबादी मिला दी जाए तो वह 80.83 प्रतिशत हो जाती है। पहले सपा और राजद जैसे कुछ दल ही जातीय आधार पर जनगणना के पक्षधर माने जाते थे, लेकिन I.N.D.I.A. के बैनर तले समूचा विपक्ष जातीय गणना के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि भाजपा के हिन्दुत्व के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष के पास यही एक अमोघ शस्त्र बचा था, जो उसने तरकश से निकाल लिया। अब पक्ष और विपक्ष की तैयारियों से साफ जाहिर है कि 2024 का चुनाव देश के सामने खड़ी ज्वलंत चुनौतियों और जनता की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को लेकर नहीं बल्कि धर्म और जातियों के नाम पर लड़ा जाएगा। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा विवादित जातीय गणना के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद अब कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की बारी है। कर्नाटक में एच. कंथाराज के नेतृत्व में आयोग ने 2015-16 में सर्वेक्षण किया था। सिद्धारमैया पर सबसे अधिक अपनी ही पार्टी का दबाव होगा, क्योंकि जातीय गणना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सबसे अधिक मुखर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कर्नाटक में दो प्रमुख जातीय समुह लिंगायत- वीरशैव और वोक्कालिंगा हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 14 और 11 प्रतिशत बताई जाती है। लेकिन ये दोनों ही जातीय गणना के विरोध में हैं। दोनों समुदायों का दावा है कि उनकी संख्या रिपोर्ट में लीक हुए आंकड़ों से कहीं अधिक है। अगर कर्नाटक ने भी आंकड़े सार्वजनिक कर दिए तो फिर मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा।

मंडल तत्कालिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को मंडल कमीशन रिपोर्ट सौंपते

ज्ञात हो कि अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। संविधान लागू होने के साथ ही में एससी/एसटी के लिए आरक्षण शुरू हो गया था, फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी थी। पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि, कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक। कुल मिलाकर ये आयोग इतिहास की एक घटना भर रहा, पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव इस आयोग के बाद नहीं हुआ। अब आइए 1978 में। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52 फीसदी हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27 फीसदी आरक्षण देने की थी, तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था। देशभर में प्रदर्शन हुए थे। मामला कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50 फीसदी तय कर दी। इसे विस्तार से यूं समझते हैं। 25 दिसंबर 1989 को सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाने का ऐलान किया और पूरी प्रक्रिया की

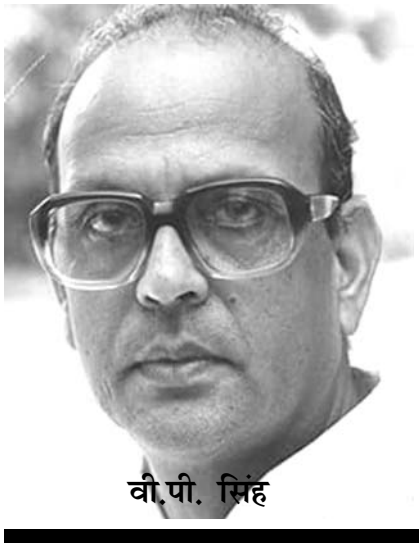

वी.पी. सिंह

बी.पी. मंडल

आरक्षण विरोधी आन्दोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी का आत्मदाह

निगरानी के लिए देवीलाल की अगुआई में एक कमेटी का गठन किया। बाद में वीपी सिंह और देवीलाल के बीच टकराव हुआ और अन्य नेताओं ने मौके का फायदा उठाया। वीपी सिंह ने अपनी सरकार पर मंडराते खतरे और मध्यावधि चुनाव की आशंका को देखते हुए 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 प्वाइंट में सिफारिशें की थीं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओबीसी वर्ग से जुड़े नेता मानते हैं कि उनको आबादी के मुताबिक कम आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में निश्चित है कि अगर ओबीसी जातियों की जनसंख्या 1931 की जनगणना के मुकाबले ज्यादा निकलती है तो मंडल समर्थकों की ओर से 27 फीसदी कोटा को बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी, जिससे देश में एक बार फिर से आरक्षण के नाम पर माहौल तनावपूर्ण होगा। ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जिस तरह की घटनाएं मंडल कमीशन को लागू करने के बाद हुई थीं, वैसे हालात फिर से बनें। यही कारण है कि कोई भी सरकार जातिगत जनगणना की बातें तो करती है लेकिन, पावर में आने पर इससे दूरी बना लेती है। कहा तो जाता है कि देवीलाल के बढ़ते कद को रोकने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थीं। उनके इस फैसले ने देश की सियासत बदल दी। सवर्ण जातियों के युवा सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध-प्रदर्शन होने लगे। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया तो बीजेपी ने नए पैंतरे के साथ खुद को किनारे कर लिया। कांग्रेस ने भी वीपी सरकार के फैसले का विरोध किया। इसके बाद 2006 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट-2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, आाईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। 2010 में आकर फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई, लेकिन तब कांग्रेस ने इसे लेकर उत्साह नहीं दिखाया। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में कहा था कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल शिक्षक, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है। वोटों के लिए धर्म के आधार पर समाज को बांटने का नतीजा हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब जातियों के नाम पर सामाजिक बंटवारे की नौबत मुंह बाए खड़ी हो गई है। नब्बे के दशक में मंडल आयोग विरोधी आन्दोलन में कम से कम 159 युवाओं ने आत्महत्या की कोशिश की थी और राजीव गोस्वामी समेत 63 युवाओं ने आत्मदाह जैसे तरीकों से विरोध प्रकट करने के लिए आत्महत्या कर ली थीं। जबकि उसके बाद भी आरक्षण के लिए उग्र आन्दोलन होते रहे हैं। कहा जाता है कि मंडल कमीशन को लागू करने के बावजूद वीपी सिंह कभी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन पाए और अपने सवर्ण समाज की नजर में पूरी उम्र खलनायक बने रहे।

विडम्बना देखिए कि देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसे आधार बनाकर अब तक बिहार में जातियों की जनसंख्या का जो अनुमान लगाया जाता है, करीब-करीब उतना ही अनुमान आधिकारिक तौर पर जारी किए गए सर्वे में भी सामने आया है। दिगर बात है कि बिहार की सियासत में सबसे बड़ा गेम चेंजर ओबीसी जातियां बनकर निकली हैं। जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे तभी वो भांप गए थे कि राज्य में जाति के खेल के बिना सियासत नहीं की जा सकती। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले वर्ग को दो भागों में बांटा। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जो इस जातिगणना में करीब 63 फीसदी तक है। इसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग 36 फीसदी है। वहीं, पिछड़ा वर्ग 27 फीसदी है। ऐसे में 63 फीसदी आबादी वाले इस वर्ग को कुल आरक्षण 30 फीसदी मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या संख्या बल के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। अगर

जातीय गणना रिपोर्ट पर किसने क्या कहा?

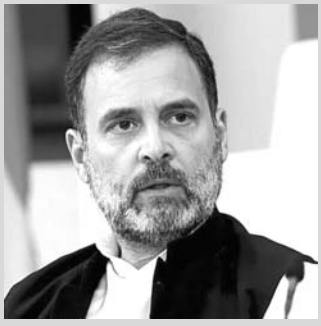

☞ बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% हैं केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं जो भारत का मात्र पांच फीसदी बजट संभालते हैं, इसलिए भारत के जातिगत आंकड़ें जानना जरूरी हैं। जितनी आबादी, उतना हक–ये हमारा प्रण है।

राहुल गांधी
लोकसभा सांसद

☞ आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे।

लालू प्रसाद यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद

☞ यह दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। हम लोगों ने कम समय में ये काम किया है। हमने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इसका प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने भी गए थे। पीएम ने जातिगत जनगणना की मांग को लोकसभा और राज्यसभा में नकार दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने राज्य में जातिगत जनगणना कराई।

तेजस्वी यादव
उपमुख्यमंत्री, बिहार

☞ बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ चुकी है। सूबे के एससी/एसटी, ओबीसी, ईबीसी की आबादी तो बहुत है पर उनके साथ हकमारी की जा रही है। नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि राज्य में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरी–स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करें, वही न्याय संगत होगा।

जीतन राम मांझी
पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

☞ बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है और उस पर गहन चर्चाएं जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। बीएसपी को खुशी है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी–एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और घोर ओबीसी–मण्डल विरोधी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित नजर आने लगे हैं। वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना और जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना तुरंत शुरू करा देना चाहिए।

मायावती
राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा

☞ सर्वेक्षण में पारदर्शिता की कमी है। बिहार में सत्तारूढ़ सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। लोजपा (रामविलास) जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सिरे से खारिज करती है। एक जाति की संख्या बढ़ा–चढ़ाकर बताई गई है। दूसरी ओर कई अन्य जातियों को संख्यात्मक रूप से इनसे छोटा दिखाया गया है। यहां तक कि मेरी अपनी जाति पासवान की जनसंख्या भी हम जितना समझते हैं, उससे बहुत कम दिखाई गई है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है। राज्य के अधिकांश लोगों से सर्वेक्षणकर्ताओं ने कभी संपर्क नहीं किया। हम मांग करते हैं कि सरकार नए सिरे से सर्वेक्षण का आदेश दे और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करे, तभी लोगों को कोई फायदा होगा।

चिराग पासवान
सांसद, जमुई

☞ यह सर्वे को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। जातिगत जनगणना का यह रिपोर्ट कार्ड लोगों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है।

गिरिराज सिंह
केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार

☞ जाति गणना की सफलता से कई नेता भौचक हैं। भाजपा तो खास बेचैनी महसूस कर रही है। जिनके परिजनों ने सभी सूचनाएं गणक- कर्मचारियों को दी, वही नेतागण फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। बदहवासी का आलम यह है कि भाजपा के कुछ नेतागण सभी आकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे, तो इसी दल के बड़े नेता निजता का अधिकार के हनन के आधार पर न्यायालय की अवमानना का प्रश्न मान रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस गणना की सफलता से राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित जनगणना कराने की उठ रही मांग से प्रधानमंत्री भी घबराहट महसूस कर रहे हैं, जो उनके भाषणों में स्पष्ट दिखता है। नीतीश सरकार को मिल रही वाहवाही से बेचैन भाजपा भूल जाती है कि इस फैसले में वह भी शामिल रही है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में भी स्पष्ट किया है कि किसी को अगर कुछ विसंगति दिखती है, तो सरकार जरूर उसका संज्ञान लेगी।

विजय कुमार चौधरी
संसदीय कार्य मंत्री, बिहार

☞ जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए।

अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री, उ०प्र०

☞ भारतीय जनता पार्टी जब बिहार की सरकार में फिर से शामिल थी, उसी सरकार ने निर्णय लिया था जातिगत जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सत्ता से जुड़ी चुनिंदा जातियों को छोड़ कर लगभग सभी जातियों के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के एक सांसद सहित अनेक लोग जब सर्वे के आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं, तब सर्वे प्रक्रिया की समीक्षा करायी जानी चाहिए। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि प्रगणकों ने अनेक इलाकों के आंकड़े घर बैठे तैयार कर लिए। वैश्य, निषाद जैसी कुछ जातियों के आंकड़े 8-10 उपजातियों में तोड़ कर दिखाये गए, ताकि उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास नहीं हो। यह किसके इशारे पर हुआ?

सुशील कुमार मोदी
राज्यसभा सांसद

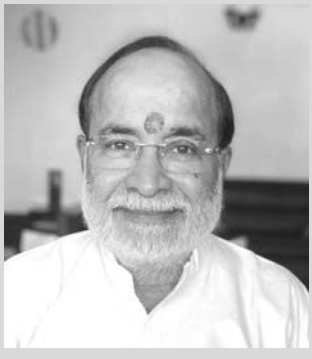

☞ वैश्य में 56 उपजातियां हैं। कुछ उपजातियों को अतिपिछड़ा, तो कुछ को पहले से पिछड़ावर्ग का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में सभी उपजातियों की गिनती उनके वर्गों के अनुसार अलग-अलग हुई है। जाति आधारित गणना का आधार भी प्रत्येक जाति की अलग-अलग स्थिति जानना था। ऐसे में वैश्य के सभी 56 उपजातियों के आंकड़ों को एकत्रित कर देखने से किसी को शिकायत नहीं रहेगी।

ललन कुमार सर्राफ
विधान पार्षद

☞ अतिपिछड़ा व पिछड़ा सहित अन्य वर्गों के अनुसार इस गिनती में वैश्य की 56 उपजातियों की संख्या को समग्र रूप से देखने पर आंकड़े कम नहीं हैं, वह बढ़ गये हैं। पहले से वे पूरे वैश्य समुदाय की जनसंख्या 27 फीसदी होने की बात कहते रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है।

समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

☞ जाति गणना के आंकड़े सही नहीं है, कुशवाहा-रांगी समाज के साथ ही सवर्ण समाज को अपमानित किया गया है। इसके खिलाफ अगले साल दो फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कोइरी महाशक्ति प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट में कुशवाहा समाज को मात्र 4.21% दिखाया गया है और दांगी समाज को आधा प्रतिशत, जबकि 2014 में इस समाज की जनसंख्या नौ प्रतिशत थी।

नागमणि
पूर्व केंद्रीय मंत्री

☞ मैं नीतीश कुमार को बार-बार कह रहा था कि रिपोर्ट जल्द जारी करें। यह आधी-अधूरी रिपोर्ट है, अभी भाजपा पूरी रिपोर्ट देखेगी, जांच करेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। यह आधा -अधूरा है, जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं है। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार ने बताई है लेकिन किस तकनीक से यह किया गया उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। लालू जी की आदत जातीय उन्माद फैलाने की रही है। भाजपा शुरू से जातीय सर्वेक्षण की समर्थक रही है।

सम्राट चौधरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बिहार

ऐसा होता है तो एक बार फिर मंडल वाला सियासी खेल नीतीश और लालू की अगुवाई में बिहार से देश के बाकी राज्यों तक पहुंच सकता है। बिहार में सबसे बड़े गेम चेंजर अति पिछड़ा वर्ग बनने वाले हैं, जिनकी आबादी 36 फीसदी है। इसमें करीब 144 जातियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कहार जैसी जातियां शामिल हैं। देश में ओबीसी जाति करीब 50 फीसदी से ज्यादा मानी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं महिला आरक्षण के वक्त भी विपक्ष लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठा रहा था और अब जाहिर तौर पर इस मुद्दे को और बल मिलेगा। साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। उस समय जाति के आधार पर जनगणना की जाती थी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार 1931 में जारी किए गए थे। हालांकि, उसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए जा सके थे। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसके बाद इसे लेकर काफी वक्त तक सियासत हुई। अब बिहार में जाति जनगणना के बाद बाकी राज्य भी अब जाति के आधार पर आंकड़े जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के आधार पर लोगों का बांटने का आरोप लगाया है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़ों को जारी करके 2024 में जाति के मुद्दे की रणभेरी बजा दी है, जाहिर सी बात है कि अब आगे की जो सियासी लड़ाई होगी उसमें जाति का मुद्दा जमकर गूंजेगा। इसके अलावा ओबीसी को लेकर अबतक जो जंग चल रही थी, उसे भी अब और जोर शोर से उठाया जाएगा। इन जातिगत आंकड़ों ने 2024 के समर की रूपरेखा खींच दी है, अब सवाल ये है कि इन जातिगत सर्वे का असर कितना होगा और बीजेपी विपक्ष के इस दांव की क्या काट निकालेगी। बिहार की सियासत में जाति के असर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि सर्वे का समर्थन करने वाली बीजेपी आंकड़े आने के बाद आर्थिक सर्वे जारी करने की बात कह रही है। नीतीश सरकार ने जाति वाली सियासत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है, जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ना तय है क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा के ऐलान से पहले ही ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा तेजी से उठाना शुरू हो गया है। प्रचार में

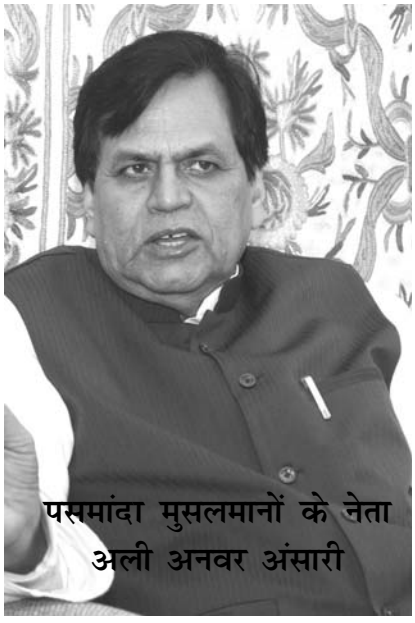

पसमांदा मुसलमानों के नेता
अली अनवर अंसारी

जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी की रैलियों में बार-बार ये बात दोहरा रहे हैं। उधर इस सर्वे का असर विपक्षी I.N.D.I.A. वाली पॉलिटिक्स पर भी बढ़ना तय है क्योंकि कांग्रेस के साथ अखिलेश जैसे नेता भी बार-बार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू नेता नीतीश कुमार को ओबीसी वर्ग का असल अगुवा बता रहे हैं। बिहार में सर्वे के आंकड़े के सामने विपक्षी दल एक सुर हो रहे हैं, पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के सर्वे के साथ जाति वाली राजनीति की नई पटकथा लिख दी गई है, पूरी पिक्चर 2024 में आएगी, लेकिन इससे पहले इस पटकथा पर सियासत तेजी से गरमाएगी।

बहरहाल, 2005 का वो वक्त याद कीजिए जब नीतीश कुमार ने लालू-राबड़ी सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। बिहार की बागडोर संभालते ही नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इसी शासनकाल में नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी चर्चा बाद में हुई। अब उनका यही फैसला बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का गेमचेंजर साबित हो सकता है। नीतीश ने 2005-10 के शासनकाल में दो नए जाति वर्गों को बनाया। इसमें एक था महादलित और दूसरा था अतिपिछड़ा। इस अतिपिछड़े वर्ग को ही जेडीयू ने अपना मुख्य वोट बैंक बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। अब बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि नीतीश का वो पुराना फैसला कितना कारगर निकला है। वही लालू प्रसाद यादव ने अपने जिस समीकरण के बदौलत बिहार में 15 साल राज किया, वो था 'एमवाई' यानी

मुस्लिम यादव समीकरण। इस वोट बैंक का उस वक्त तक कोई तोड़ नहीं था। लेकिन उस वक्त के 'जंगलराज' से ऊबी जनता ने लालू-राबड़ी सरकार के राज का अस्त कर दिया। लगभग सभी जातियों के लोगों का वोट जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिला। इसके बाद 2005 में 142 सीटों के साथ नीतीश-बीजेपी ने लालू-राबड़ी राज को उखाड़ फेंका। लेकिन उसी वक्त शायद नीतीश को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो सत्ता को 5 साल से ज्यादा नहीं चला पाएंगे। इसीलिए बिहार का राज संभालते ही उन्होंने वही किया जो इस सूबे का कड़वा सच है, यानी जाति। इस बात को सुनने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि बिहार के चुनावों में जाति ही एकमात्र सत्य होती है। लिहाजा नीतीश ने दो नई जातियों के वर्गों का गठन किया। इन्हीं में से एक था अतिपिछड़ा वर्ग। इस जाति में नीतीश ने लोहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, सोनार समेत 114 जातियों को रखा। कुल मिलाकर बिहार में ये एक बड़ा कदम था। 114 जातियों को एक वर्ग के तले ले आना, ये शुरुआत में कोई समझ नहीं पाया। नीतीश का ये दांव काफी दूरदर्शी वाला था। 2015 की एक गैर आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 25 फीसदी अतिपिछड़ी जातियां थीं। उस वक्त नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का लगभग लगभग सूपड़ा ही साफ कर दिया था। अब नीतीश सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट की सत्यता पर अभी काफी राजनीतिक बहस होगी,

इसे भी तय मान लीजिए। लेकिन इसी रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने नीतीश कुमार के 10 साल पहले के फैसले को एकदम सटीक ठहरा दिया है। बिहार में इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जनसंख्या अतिपिछड़ों की ही है, यानी पूरी 36.01 फीसदी। अगर नीतीश कुमार सरकार की ये रिपोर्ट सही है तो इसे एकदम तय मान लीजिए कि यही अतिपछड़ा वोट बैंक 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है। जो भी दल इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी इस सियासी जंग में जीत करीब-करीब तय हो जाएगी।

गौरतलब है कि भारत में 'जाति' इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यह महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर भारी साबित हो सकता है। हालांकि, राष्ट्रवाद ऐसा मुद्दा है, जिसके सामने यह नहीं टिक पाता है और बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को

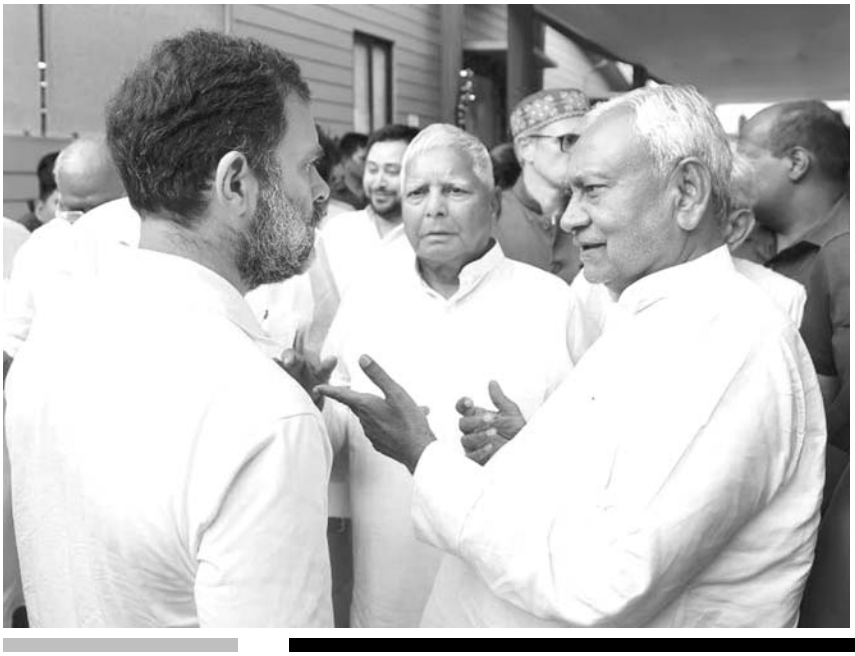

भुनाती है। अब बात नीतीश कुमार की। वह ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास सिर्फ 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में वह तीसरी बड़ी पार्टी हैं। उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को बनाकर रखा है, जो कि उनकी राजनीति करने का स्टाइल है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस जाति (कुर्मी) से आते हैं, वह बिहार की आबादी में मात्र 2.87 प्रतिशत है। इसके बावजूद वह करीब 18 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार को एक कुशल रणनीतिकार और सोशल राजनीति में माहिर खिलाड़ी माना जाता है। जाति गणना को उनके मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि जाति गणना करवाकर नीतीश कुमार ने बिहार से लेकर दिल्ली तक अपनी प्रासंगिता को बढ़ाया है, बल्कि अपने साथी राजद को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि राजद के कई नेता दबी जुबान तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की लगातार मांग कर रहे हैं। जेडीयू के अलावा नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का एक समूह शामिल है। 2020 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ने के बाद नीतीश ने 2022 में राज्य के विपक्षी गुट से हाथ मिला लिया। बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जाति सर्वेक्षण के साथ नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। उन्होंने दोहराया है कि वह सिर्फ कुर्मियों के नेता नहीं हैं, बल्कि अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के भी नेता हैं। जाति सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है। वहीं, बिहार की आबादी में 14 प्रतिशत यादव हैं। राजद यादव-मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर है, लेकिन यहां भी नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण

से सेंध लगाने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को ईबीसी में शामिल कर नीतीश कुमार ने मुस्लिम राजनीति के पिच पर खेलने की कोशिश की है। वह पसमांदा मुस्लिम के एक वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पसमांदा मुसलमानों के नेता अली अनवर अंसारी को आगे बढ़ाया। इससे राजद का महत्वपूर्ण वोट बैंक मुस्लिम छिटक सकता है। इस जाति सर्वेक्षण से नीतीश को उम्मीद है कि वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईबीसी के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के लिए ईबीसी महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने 2005 से कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस वोट आधार को पोषित किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक और यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराए थे, लेकिन किसी का भी नतीजा सामने नहीं आया। बिहार पहला राज्य है जिसने 2 अक्टूबर को अपने जाति सर्वेक्षण के परिणाम घोषित कर दिया। सनद् रहे कि बिहार की राजनीति में एक कोने में सिमटे नीतीश कुमार राष्ट्रीय मंच पर भी हाशिए पर धकेले जा रहे थे। इस बात की संभावना है कि जाति जनगणना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मौका दे दिया है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने की भी खूब चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। I.N.D.I.A. गठबंधन की हाल की कुछ बैठकों में नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया था। अब स्थिति बदलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस को अब यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि I.N.D.I.A. गठबंधन में नीतीश कुमार को कौन सा पद दिया जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के अंतर ने नीतीश कुमार को सतर्क कर दिया। अब वह जाति गणना के जरिए ईबीसी को वापस आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश 2019 की हार के बाद अपनी ईबीसी राजनीति को फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने एक तीर से एक नहीं बल्कि कम से कम तीन शिकार किए हैं। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मुद्दे को संभाला है। राजद की धमकी का भी जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिता को मजबूत किया है।

बहरहाल, यह सच है कि धर्म की ही तरह जाति भी हिन्दू समाज की सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि फोटो खिंचाने के लिए चाहे आप किसी दलित के घर खाना खाने चले जाएं मगर उस दलित से बेटी का रिश्ता शायद ही करना चाहें। जातियां व्यक्ति विशेष की पहचान भी होती हैं इसलिए लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति का भी उल्लेख करते हैं। इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि समाज में कुछ जातियां वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर बहुत पिछड़ी रह गई। आजादी के बाद भी तरक्की के अवसर मुट्ठीभर अगड़ी जातियों ने लपक लिए। यहां तक कि पिछड़ी जातियों में भी जो अगड़ी जातियां थीं उन्होंने तरक्की के अवसरों को अत्यन्त पिछड़े लोगों तक पहुंचने से पहले हथिया लिया। इसका जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने कुछ जनजातियां हैं जिनकी शासन-प्रशासन तक पहुंच हो गई जबकि अण्डमान निकोबार की जातियों तक प्रगति के अवसरों पहुंचना तो रहा दूर उनका अपना अस्तित्व ही गंभीर खतरे में है, इसलिए समाज की अंतिम पक्तियों पर बैठे लोगों की बात करना या उनकी व्यथा कथा को आवाज देना हर भारतीय का कर्तव्य है। एक सच यह भी है कि कोई भी इंसान जाति या धर्म का टैग लगाकर पैदा नहीं होता है। मनुष्य के पैदा होने के बाद उस पर हिन्दू-मुसलमान या अगड़ी-पिछड़ी जाति का लेबल लगाया जाता है। प्राचीन काल में भी जातियां कर्म के अनुसार तय होती थी। यहां तक कि सनातन धर्मावलम्बियों के अनुसार मानव जाति के पहले संविधान और धर्मशास्त्र ''मनुस्मृति'' में मनुष्यों के जिन चार वर्णो का उल्लेख है उनका वर्गीकरण उनके कर्म के आधार पर किया गया है। हालांकि लोग विभेदकारी उस मनुवादी वर्ण व्यवस्था की मुखालफत करने लगे हैं। चूंकि पैतृक व्यवसाय अपनाना भी एक परम्परा रही है और उसके लिए लोगों को वैसे ही दीक्षा और संस्कार मिलते रहे हैं, इसलिए पुश्तैनी व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। अब व्यवसाय में बदलाव तो आ रहा है मगर पुरखों से विरासत में मिली जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। चूंकि तब समाज और राजे महाराजाओं की शासन व्यवस्था जातियों के आधार पर चलती थी। कोई जाति रक्षा की जिम्मेदार थी तो कोई कोष की और कोई प्रशासन की जैसी अन्य जिम्मेदारियां संभालती थी। लेकिन आज संविधान ही शासन प्रशासन चलाता है। हां! आज भी कुछ लोग जाति के आधार पर कार्य कर रहे हैं अन्यथा जातियों के आधार पर कर्म का निर्धारण का प्राचीन सिद्धान्त लगभग निरर्थक हो चुका है।●

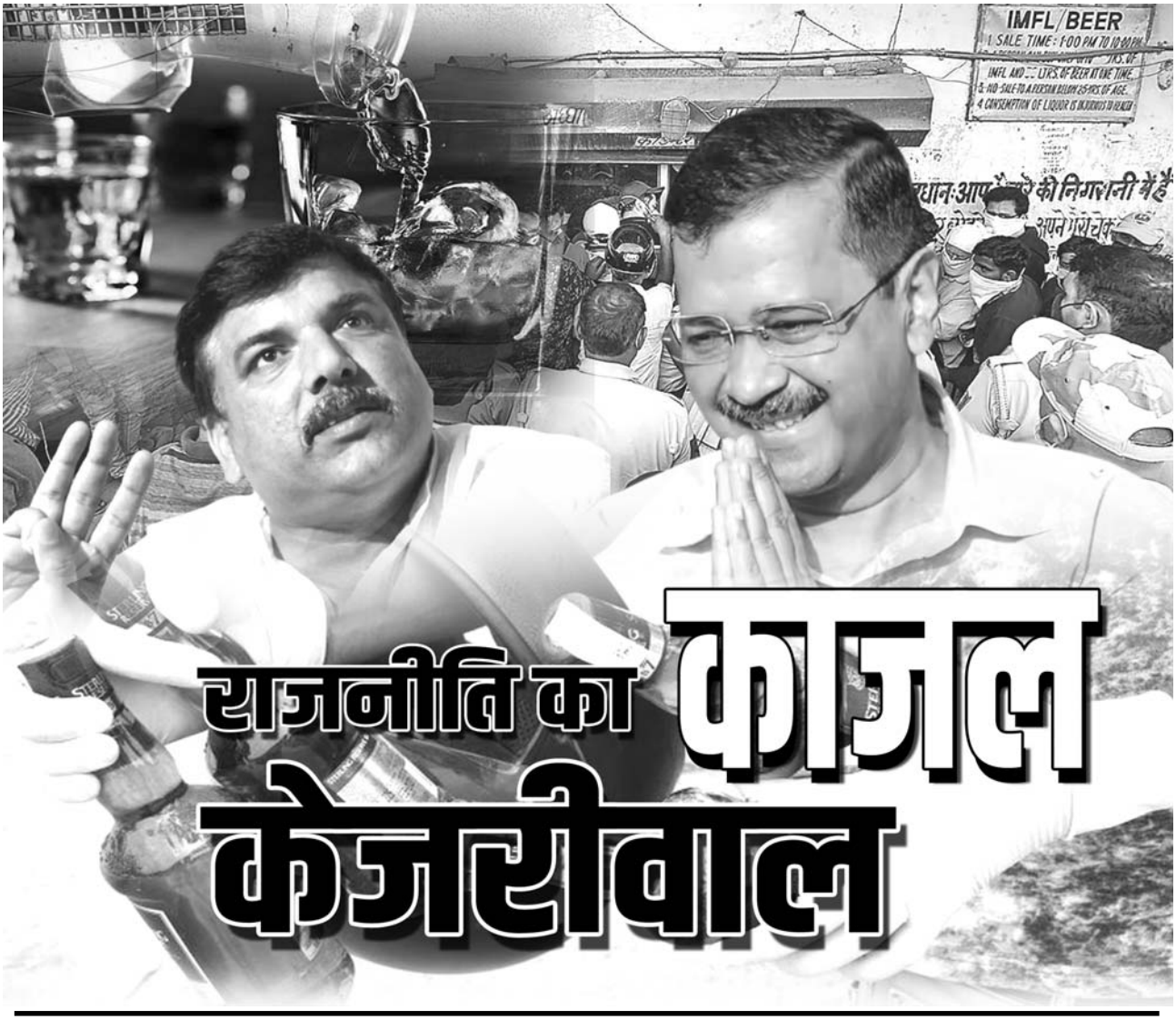

राजनीति का काजल केजरीवाल

● संजय सिन्हा

इधर....इधर देखिये! अब हम बिहारी नहीं रहें राजनीति का काजल, जब भी राजनीतिक भष्ट्राचार की बात आती थी तो लोग लालू यादव को सबसे बड़ा भष्ट्र मानते थे, परंतु वो दिन अब नहीं रहे, बिहार के लोगों जो बिहार से बाहर रहतें हैं उन्हें लगता था कि मेरा बिहार सबसे बड़ा भष्ट्र हैं, वो अब ऐसा नहीं मानेगें, राजनीति के दुनिया में ऐसा नहीं है कि लालू यादव या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही सबसे ज्यादा भष्ट्र हैं इनसे भी भष्ट्र सरकार रहीं हैं, नेता रहें हैं परंतु भष्ट्राचार से ज्यादा थेथर और भठियारापन का अंत का ताज कुछ समय पहले तक ये लालू यादव के सर पर होता रहा था जो अब दिल्ली के और सबसे अधिक पढ़े-लिखे व कट्टर ईमानदार का डीलर अरविंद केजरीवाल के सर पर शोभामान है, अब मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को छोटे नाम केजरी से कहानी-आलेख को आगे बढ़ाउगा, केजरी जब कट्टर ईमानदार बोलता है तो उसके चेहरे सरेला बैगन के तरह लगता है, जैसे कोई कसाई कहें कि मैं तो शाकाहारी हूँ, इस थेथरलोजिस्ट मुख्यमंत्री केजरी ने जनता को विश्वास में लेकर जितना मुर्ख बनाया है उतना किसी मुख्यमंत्री या कोई और नेता ने शायद ही किया हो? इसने शराब के ठेके को कम और आवासीय क्षेत्र में बिल्कुल बंद करने की बात कही थी, लेकिन किया उसका उल्टा उसने छोटे-बड़े सभी मुहल्लों में ठेके खोल दिये और एक बोतल पर एक फ्री भी कर दिया इसके बाद भी ये नहीं रुका शराब के ठेके

को ड़ाई डे कम, खुलने की अवधी अधिक, बार के समय को भी बढ़ा दिया , पीनेवाले के उम्र 25 से घटा कर 21 कर दिया इस केजरी ने गंध मचा दिया। ये केजरी भारत ही नहीं पुरी दुनिया का ऐसा शार्तिर मुख्यमंत्री है जो अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है और न ही किसी फाईल पर हस्ताक्षर करता है, परंतु कोई पत्रकार या उप राज्यपाल इस धुर्त मुख्यमंत्री से सवाल नहीं उठाता, ये अपने ऐसे ऐसे नेताओं को कट्टर ईमानदार बताता है, जिसे हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट बैड करेक्टर (बीसी) बताती है। इसने अभी अपने विधायक अमानतुल्ला खान को कट्टर ईमानदार बताया जबकि कुछ दिनों पहले दोनों उपरी कोर्ट ने उसे बीसी बताया है, केजरी ने अपने लठैत राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए कहा था कि ईडी लोगों को हरकाता है और संजय सिंह ईडी की पैंट गीली कर देता है क्या कोई सभ्य मुख्यमंत्री किसी जिम्मेदार सरकारी संस्थान के लिए ऐसा बोल सकता है क्या? इस थेथर केजरी ने वैसे कारनामा कर दिखाया जो पहले के भष्ट्र मंत्री मुख्यमंत्री भी न कर सका था इसने अपने मंत्री सतेन्द्र जैन को जेल में जाने के बाद भी दस महीने तक मंत्री पद पर रखें हुए था, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल जाने की स्थिति में उसने अपने अंगुठा छाप पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, ये धुर्त मुख्यमंत्री कहता है कि ईडी सीबीआई आई को घर पर छापे में कुछ भी नहीं मिला क्या कोई अनपढ़ चोर भी चोरी कर के लाये हुए धन पैसे को अपने घर में रखता है क्या? कोई हत्यारा हरे रंग का टीशर्ट पहन कर हत्या कर के आने के उपरांत अपना हरे रंग वाला टीशर्ट

घर में रखेगा क्या? ये बेशर्म मुख्यमंत्री खुल कर बोलता है कि बक्फ बोर्ड को धन की कमी नहीं होने देंगे अभी बक्फ बोर्ड में अनिमियता हुई है परंतु उसके मुखिया आमानतुल्ला खान कट्टर ईमानदार है केजरी के नजर में आने वाले कुछ समय में अमानतुल्ला खान को कोर्ट से सजा होना लगभग निश्चित है, जेल तो आखिर में केजरी भी जायेगा लेकिन अपने जेल जाने के पहले कितने कट्टर को नाप देगा, ये ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने जैसा उस्तादों को सत्ता के पहले तो उनकों प्रयोग किया लेकिन सत्ता मिलने के बाद जैसे तैसे जलील कर पार्टी से निकाल दिया, इस केजरी को अपने से ज्यादा धुर्त नेता नहीं पसंद है, इसी का परिणाम है कि इसके सहयोगी व मित्र आज इससे अलग है वो भले कुमार विश्वास, योगेन्द्र यादव, पत्रकार आसुतोष, प्रशांत भूषण या कपिल मिश्रा, अलका लांबा हो, इस केजरी के साथ वही लोग टीक पाये जो चतुर तो है परन्तु केजरी के निचे वो भले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सतेन्द्र जैन, बड़बोला संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता। अन्ना हजारे भी देश को क्या दे गयें? इतने बड़े बहुमत मिलने के बाबजूद भी न लोकपाल आया और न भविष्य में अब कभी केजरी लोकपाल के लिए कुछ बोलेगा अब तो केजरी सिर्फ इन्जांय करने के लिए राजनीति कर रहा है बड़े घर, लंबी चौरी सुरक्षा, बड़े बड़े गाड़ीयां विधायकों को विदेश यात्रा, केजरी ने जिसे चोर बोला उसी के गोद में बैठ कर सिर्फ और सिर्फ जेल जाने से बचना चाहता है, उम्मीद है कि ये स्याना मुख्यमंत्री दो चार और बुड़बक को जेल में पहुचा कर अपने भी जेल चला जायेगा। ●

बेरोजगारी दूर करने में सहायक है ऋण किन्तु

उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर

अबतक के सारे रिकॉर्ड होंगे ध्वस्त

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उधमी योजना के अंतर्गत नये उद्योग शुरू करने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी के साथ 10 लाख रूपये कि सहायता के रूप में व्यवसाय शुरू करने के साथ बेरोजगारी भगाने का एक आकर्षित पैकेज दिया जा है, जिसमें 5 लाख रूपये अनुदान और 5 लाख रूपये ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसमें ऋण पर कोई ब्याज नही लिया जाता है, जो देय राशि ब्याज मुक्त होता है और इसे सात वर्षो में 84 किस्तों में देय है। इस योजना के तहत केवल नये उधोगों कि स्थापना के लिए लाभ देय है। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को विभाग कि तरफ से यह सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है जो इच्छुक आवेदक व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूत के हिसाब से कई प्रकार के ऑप्शनल प्रोजेक्ट प्लान कर सकते है जो कम्प्यूटर हार्डवेयर/एसेम्ब्लिंग एवं वेंटवर्किंग, टेंट हॉउस एवं इवेंट मैनेजमेंट, ब्यूटीपार्लर, आटा-सतु एवं बेसन उत्पादन, सीमेंट-जाली, गमला निर्माण, तेल मिल, पीवीसी जूता/चप्पल, पैथोलोजिकल जाँच घर, गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, मुर्गी दाना उत्पादन, डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग, बोतल बंद पानी, नोट बुक/कॉपी/फाइल, फोल्डर उत्पादन, टूरिस्ट टैक्सी, चांदी आभूषण निर्माण, बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, दाल मिल, चमड़े का जूता निर्माण, सैलून, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, ढाबा/होटल/रेस्टुरेंट/फूड ऑन व्हील्स, अगरबत्ती उत्पादन, डेस्कटॉप पब्लिशन-स्क्रीन प्रिंटिंग, पेवर ब्लॉक, मोबाइल-चार्जर रेपीरिंग, फ्लाईएस ब्रिक्स निर्माण, आईटी विजनेस केंद्र, आइसक्रीम उत्पादन, पोल्ट्री फॉर्म, कृषि यंत्र निर्माण, लेदर बैग निर्माण, प्लम्बिंग वर्क्स जैसे दर्जनों व्यवसाय के लिए चयनित किया जाता है जो प्रथम किश्त के रूप में डेढ़ लाख से दो लाख रूपये दिया जाता है। प्रथम किश्त की उपयोगिता समय सीमा 60 दिन रखा गया है। 60 दिनों के अंदर ही कार्यस्थल की तैयारी, बिजली कनेक्शन, अग्निशामक यंत्र इत्यादि लगाना होता है। इसके पश्चात् द्वितीय किश्त के लिए मशीन खरीदने की राशि दी जाती है, जो अंतिम किश्त के रूप में सभी शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इससे पूर्व कार्यस्थल का निरिक्षण एवं लाभुक से अन्य विभागीय नियम के अनुसार दस्तावेज लिया जाता है।

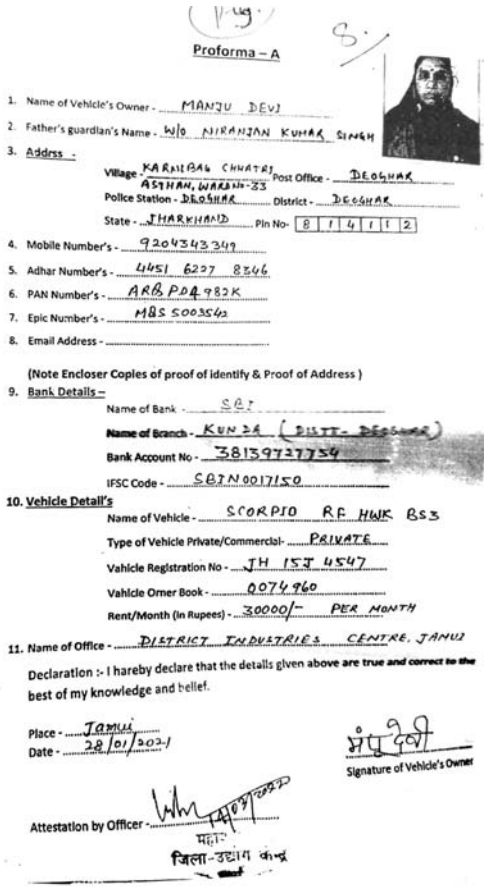

Proforma – A

1. Name of Vehicle's Owner - MANJU DEVI
2. Father's guardian's Name - W/O NIRANJAN KUMAR SINGH
3. Addrss -
   Village - KARNIBAG CHHATRI ASTHAN, WARD No-33 Post Office - DEOGHAR
   Police Station - DEOGHAR District - DEOGHAR
   State - JHARKHAND Pin No- 8 1 4 1 1 2
4. Mobile Number's - 9204343349
5. Adhar Number's - 4451 6227 8346
6. PAN Number's - ARBPD4982K
7. Epic Number's - MBS 5003542
8. Email Address -

(Note Encloser Copies of proof of identify & Proof of Address)

9. Bank Details –
   Name of Bank - SBI
   Name of Branch - KUNDA (DISTT- DEOGHAR)
   Bank Account No - 38139727754
   IFSC Code - SBIN0017150
10. Vehicle Detail's
   Name of Vehicle - SCORPIO RF HWK BS3
   Type of Vehicle Private/Commercial- PRIVATE
   Vahicle Registration No - JH 15J 4547
   Vahicle Orner Book - 0074960
   Rent/Month (In Rupees) - 30000/- PER MONTH
11. Name of Office - DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, JAMUI

Declaration :- I hareby declare that the details given above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place - Jamui
Date - 28/01/2021

मंजू देवी
Signature of Vehicle's Owner

Attestation by Officer -
महा-
जिला-उद्योग केन्द्र

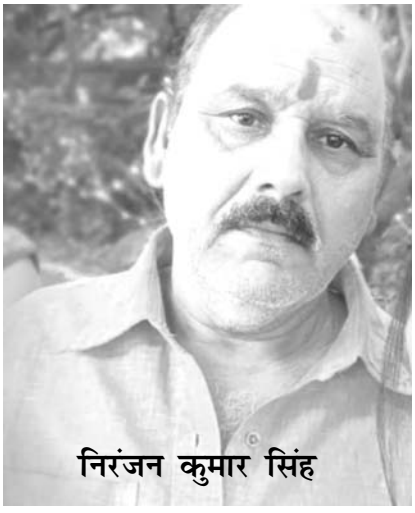

निरंजन कुमार सिंह

महेन्द्र प्रसाद

अमरीश आनंद

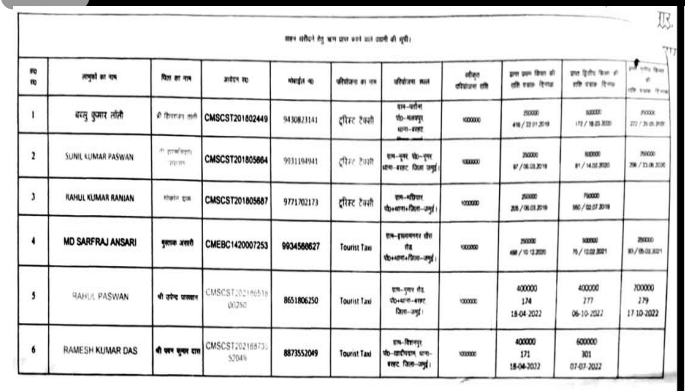

वाहन खरीदने हेतु ऋण प्राप्त करने वाले उद्यमी की सूची।

क्र० सं०	लाभुकों का नाम	पिता का नाम	आवेदन सं०	मोबाईल नं०	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल	स्वीकृत परियोजना राशि	प्राप्त प्रथम किश्त की राशि एवं दिनांक	प्राप्त द्वितीय किश्त की राशि एवं दिनांक	प्राप्त तृतीय किश्त की राशि एवं दिनांक
1	बब्लु कुमार तांती	श्री [illegible]	CMSCST201802449	9430823141	टूरिस्ट टैक्सी	[illegible]	1000000	250000 [illegible]	500000 [illegible]	250000 [illegible]
2	SUNIL KUMAR PASWAN	[illegible]	CMSCST201805664	9931194941	टूरिस्ट टैक्सी	[illegible] जमुई।	1000000	250000 [illegible]	500000 [illegible]	250000 [illegible]
3	RAHUL KUMAR RANJAN	[illegible]	CMSCST201805687	9771702173	टूरिस्ट टैक्सी	[illegible] जमुई।	1000000	250000 [illegible]	750000 [illegible]	
4	MD SARFRAJ ANSARI	[illegible] अंसारी	CMEBC1420007253	9934568627	Tourist Taxi	[illegible] जमुई।	1000000	250000 [illegible]	500000 [illegible]	250000 [illegible]
5	RAHUL PASWAN	श्री उपेन्द्र पासवान	CMSCST202186516 00250	8651806250	Tourist Taxi	[illegible] जमुई।	1000000	400000 174 18-04-2022	400000 277 06-10-2022	200000 279 17-10-2022
6	RAMESH KUMAR DAS	श्री [illegible] कुमार दास	CMSCST202168735 52049	8873552049	Tourist Taxi	[illegible] जमुई।	1000000	400000 171 18-04-2022	600000 301 07-07-2022	

महाप्रबंधक
जिला-उद्योग केन्द्र
जमुई
15/09/23

कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई।
मुख्यमंत्री अनु0जाति/अनु0जनजाति/अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनान्तर्गत पंचायतवार/परियोजनावार समेकित प्रतिवेदन।
(प्रखण्ड एवं पंचायतवार)

क्र. सं.	प्रखण्ड	पंचायत	फॉर्म/कार्य का प्रकार	इकाई का पता	लाभार्थी का नाम	आवेदन आई०डी०	मोबाईल न0	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sikandra	Bhullo	कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग	Add.- Nawabganj	GIRISH KUMAR VISHNU	CMSCT201800076	8002007941	
2			टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट	Add.-Kirparamdih	VIKASH KUMAR	CMSCT201800398	6200263843	
3		Sabal Bigha	ब्यूटीपार्लर	Add.-Jansidih	JYOTI KUMARI	CMSCT201803354	7461055585	
4			टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट	Add.-Jansidih	RUPESH KUMAR	CMSCT201800368	7634064197	
5		Pohe	कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग	Add.-Pohe	INDRA KUMAR RAM	CMSCT201801052	8800125381	
6			टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट	Add.-Pohe	SHISHUPAL KUMAR	CMSCT201801085	9661454071	
7			आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन	Add.-Pohe	CHANDAN KUMAR	CMSCT201801087	8002873833	
8		Sijhauri	Beauty Parlour	Add- Talsahrsha	DEEPIKA KUMARI	CMEBC1420005479	8292022097	
9		Kumar	कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग	Add.-Tuladih	KAMLESH KUMAR	CMSCT201801251	9128310928	
10		Goukhula, Fatehpur	CEMENT JALI, GAMLA NIRMAN	Add.-Goukhula	PURSHOTTAM KUMAR	CMSCT201802249	9534266488	
11			तेल मिल	Add.-Goukhula	DEVNANDAN PASWAN	CMSCT201805937	9297537722	
12		Najari	पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल	Add.-Najari	Manoj Kumar Arya	CMSCT201803630	7033006777	
13			पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल	Add.-Najari	CHANDAN KUMAR	CMSCT201801886	8405987619	
14			पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल	Add.- Sakal Nouathika	CHANDAN KUMAR	CMSCT201801455	8886059845	
15			पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल	Add.- Sakal Nouathika	RAMBILASH KUMAR	CMSCT201803115	9007633085	
16			पैथोलोजिकल जाँच घर	Add.-Najari	DINESH KUMAR AMBEDKAR	CMSCT201801875	9931542540	
17			गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई	Add.-Najari	ROHIT KUMAR	CMSCT201801691	6204424074	

☞ **वर्ष 2023-24 में 8000 उधमियों का चयन किया जाना लक्ष्य है:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलावार तीन श्रेणियों में 8000 आवेदनों का चयन निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है। पहली श्रेणी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुको का चयन किया गया है। इसमें पशु आहार का उत्पादन, मुर्गी दाना का उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग, बेकरी उत्पादन (ब्रेड बिस्कुट) आटा और बेसन उत्पादन, आयल मिल, मसाला उत्पादन शामिल है। दूसरी श्रेणी में चर्म, वस्त्र, खाध प्रसंस्करण तथा प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया गया है। तीसरी श्रेणी में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र उद्योग के लिए 500 लाभुकों का चयन किया गया। लेदर गारमेंट्स, जैकेट इत्यादि का उत्पादन, लेदर, शूज/शैंडल उत्पादन, बैग्स, बेल्ट, पर्स, ग्लब्स, गाड़ी सीट कवर जैसे लेदर एवं रेक्सीन का उत्पादन निर्माण, रेडिमेट गार्मेंट्स और पावर लैम्प इकाई शामिल है। तीसरी श्रेणी में जिलेवार न होकर पूरे राज्य के लिए रखा गया था, जो किसी भी जिले के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन दिया जाना था। आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर पुन: संशोधित करने का कोई वित्तीय सहायता नही दिया जा सकता। आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं, उस जिले का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। एक आवेदक अपने आधार के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं।

STATEMENT OF ACCOUNT

P-7

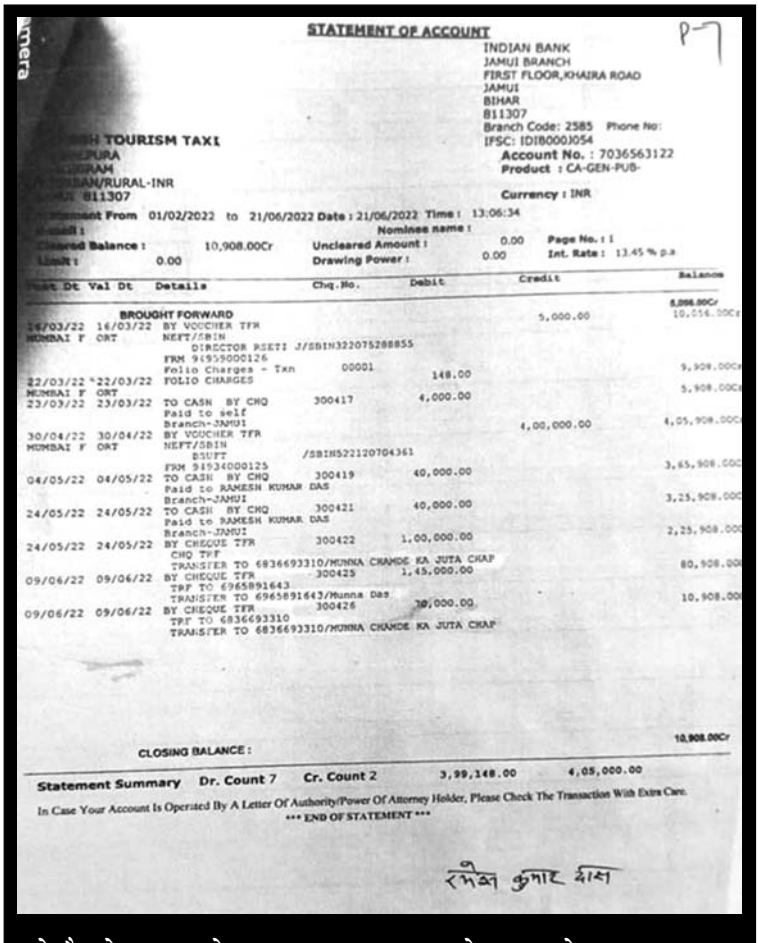

INDIAN BANK
JAMUI BRANCH
FIRST FLOOR,KHAIRA ROAD
JAMUI
BIHAR
811307
Branch Code: 2585 Phone No:
IFSC: IDIB000J054
Account No. : 7036563122
Product : CA-GEN-PUB-
Currency : INR

...H TOURISM TAXI
...PURA
...RAM
...BAN/RURAL-INR
... 811307

...ment From 01/02/2022 to 21/06/2022 Date : 21/06/2022 Time : 13:06:34
Nominee name :
...red Balance : 10,908.00Cr Uncleared Amount : 0.00 Page No. : 1
Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00 Int. Rate : 13.45 % p.a

Post Dt	Val Dt	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD				5,056.00Cr
16/03/22 MUMBAI F ORT	16/03/22	BY VOUCHER TFR NEFT/SBIN DIRECTOR RSETI J/SBIN322075288855 FRM 94959000126			5,000.00	10,056.00Cr
		Folio Charges - Txn	00001	148.00		9,908.00Cr
22/03/22 MUMBAI F ORT	22/03/22	FOLIO CHARGES				5,908.00Cr
23/03/22	23/03/22	TO CASH BY CHQ Paid to self Branch-JAMUI	300417	4,000.00		
30/04/22 MUMBAI F ORT	30/04/22	BY VOUCHER TFR NEFT/SBIN BSUFT /SBIN522120704361 FRM 91934000125			4,00,000.00	4,05,908.00Cr
04/05/22	04/05/22	TO CASH BY CHQ Paid to RAMESH KUMAR DAS Branch-JAMUI	300419	40,000.00		3,65,908.00Cr
24/05/22	24/05/22	TO CASH BY CHQ Paid to RAMESH KUMAR DAS Branch-JAMUI	300421	40,000.00		3,25,908.00Cr
24/05/22	24/05/22	BY CHEQUE TFR CHQ TRF TRANSFER TO 6836693310/MUNNA CHANDE KA JUTA CHAP	300422	1,00,000.00		2,25,908.00Cr
09/06/22	09/06/22	BY CHEQUE TFR TRF TO 6965891643 TRANSFER TO 6965891643/Munna Das	300425	1,45,000.00		80,908.00Cr
09/06/22	09/06/22	BY CHEQUE TFR TRF TO 6836693310 TRANSFER TO 6836693310/MUNNA CHANDE KA JUTA CHAP	300426	70,000.00		10,908.00Cr

CLOSING BALANCE : 10,908.00Cr

Statement Summary Dr. Count 7 Cr. Count 2 3,99,148.00 4,05,000.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

*** END OF STATEMENT ***

रमेश कुमार दास

ये है रमेश दास के भ्रष्टाचार का सबूत, जो वाहन के नाम पर ऋण लिया और पैसा उठाया जूता चप्पल के फर्जी दुकान के नाम पर और किया कुछ नही।

☞ **मुख्यमंत्री उधमी योजना की पात्रता और आवेदन :-** इस योजना का लाभ उठाने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन उद्योग विभाग की अधिकारीक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यक्तिगत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) नहीं बनाया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को ही अंतिम माना जाता है। विभागीय निर्देश के अनुसार उधमी योजना के लाभ प्राप्त करने के उपरांत किसी भी तरह का फ्रॉड या फर्जी बिल के साथ छेड़छाड़, राशि का योजना प्रावधान के विपरीत दुरूपयोग इत्यादि करने पर लाभुक पर कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिये बिहार के स्थाई निवासी होना शर्त

रखा गया है। योजना सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा श्रेणी में आने वाले आवेदकों के लिए है। आवेदकों को कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित किया गया है।

☞ **आवेदन करने के पहले :-** वेबसाईट https://udyaminbihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये आवेदक 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आवेदन करना था। मेडिकल जांच घर, केला रेशम निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई, डिजाइन, गेट ग्रिल निर्माण इकाई परियोजना में आवेदन करने हेतु आवेदकों को सम्बंधित परियोजना में प्रशिक्षित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र उधमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

☞ **ऋण दिलाने में महाप्रबन्धक की भूमिका :-** जिले के महाप्रबन्धक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होता है, जो अपने स्वविवेक से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 50 लाख रूपये तक ऋण इच्छुक लोगों को अपने अनुशंसा के आधार पर दिला सकते हैं, जो आजकल नये तरकीब का ईजाद करते हुये चतुराई से उन्ही लोगों से उप विकास आयुक्त के यहाँ आवेदन करवाते हैं, जिनको यह लाभ देना है। आवेदन उतना ही उप विकास आयुक्त के पास पहुँचता है, जितने की आवश्यकता है। जिस पर अपनी अनुशंसा कर उन लाभुकों से मोटी राशि वसूल कर अपने सगे-संबंधियों में बाट दिया करते हैं या उन्ही लोगों को लाभुक बनवाते हैं, जिनसे वसूली की गई है। यह भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी होता है। जिस चतुराई का ईजाद कर जिले के चयन कमेटी पर मामले को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो यह पूरे राज्य में जिले के सभी महाप्रबन्धक इस कार्य को करते हैं। ऋण प्रदत्त के व्यवसाय के कार्यस्थल का निरीक्षण स्वयं अथवा अपने चहेते उद्योग विस्तार पदाधिकारी से करवा कर सम्पूर्ण राशि का न्यारा-ब्यारा कर दिया गया है। जिसकी सत्यता लगभग 75 प्रतिशत है, जो लाभुक बिना कार्य किये सरकारी राशि के पेपर में व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है की लाभुक द्वारा जिस व्यवसाय के नाम पर ऋण लिया गया उस पर कार्य नही कर अन्य व्यवसाय के नाम पर राशि निकाल लिया गया है तथा जो राशि की निकासी की गई है वह भी फर्जी प्रतिष्ठान को दिखा कर ऐसा कृत किया गया है, जिससे हर वर्ष योजना के कार्यान्वयन में किये गए अनिमियतता से करोड़ों रूपये की क्षति एवं नुकसान सरकार को की जा रही है। चूकि योजना का मकसद लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आसपास के बेरोजगारों को कार्य दिलाना है, जिससे सरकार की नीति का लाभ अन्य लोगों के किचन तक पहुँचे। जिसमें बड़े बाधक के रूप के रूप में खुद अधिकारी संलिप्त होते हैं।

बानगी यह है कि जमुई जिला उद्योग केंद्र, जमुई के तत्कालीन महाप्रबंधक नरेश दास के साथ उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद (स्थापना), महेंद्र प्रसाद (स्थापना), वरीय लिपिक निरंजन कुमार सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी एवं सहयोगी कर्मी हैं, जो गत् वर्ष नरेश दास को सेवा निवृत होने से पूर्व निलंबित किया जा चुका है।

☞ **योजना के कार्यन्वयन में पलीता लगाते हैं अधिकारी :-** जमुई जिले अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच लगभग डेढ़ सौ ऐसे लाभुक हैं, जो कार्यस्थल पर बिना कुछ किये दूसरी और अंतिम किश्त की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर लिया। राशि मिलने के पीछे जाँच पदाधिकारी सह उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद एवं महेंद्र प्रसाद हैं, जिनके जाँच के आधार पर तीसरी एवं अंतिम किश्त जारी किया गया। चूकि प्रथम किश्त के बाद दूसरी किश्त की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय/विभाग को देना अतिआवश्यक माना गया है, जो तीसरी यानी अंतिम किश्त का भुगतान करने से पहले यह नियम और भी सख्त किया गया है। किन्तु ऐसे अधिकारी के रहते सारे नियम एक तरफ और इनके अधिकार एक तरफ। यह तभी सम्भव होता है, जब लाभुक से अग्रिम दो लाख का श्रम सेवा के रूप में राशि को वसूल कर लिया गया हो। उदाहरण के तौर पर तत्कालीन महाप्रबंधक नरेश दास के द्वारा किये गये अनिमियतता एवं उनके सहयोगी उद्योग विस्तार पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद के द्वारा नियम के विरुद्ध वर्तमान जनप्रतिनिधि से रिश्वत के नाम पर लाभुक बनवाने में मदद की गई, जो वर्तमान में सरपंच हैं। महेन्द्र प्रसाद, उधोग विस्तार पदाधिकारी, जि.उ.के. जमुई द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए मोटी रकम लेकर लक्ष्मीपुर प्रखंड (जिला-जमुई) के ग्राम पंचायत राज नजारी के विजेता सरपंच-कल्पना कुमारी, पिता-रंजय कुमार (परियोजना-गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई) ग्राम+पोस्ट+थाना-लक्ष्मीपुर, जिला-जमुई को द्वितीय किश्त दिलवाने की अनुशंसा कर योजना के क्रियान्वयन में अनिमियतता किया

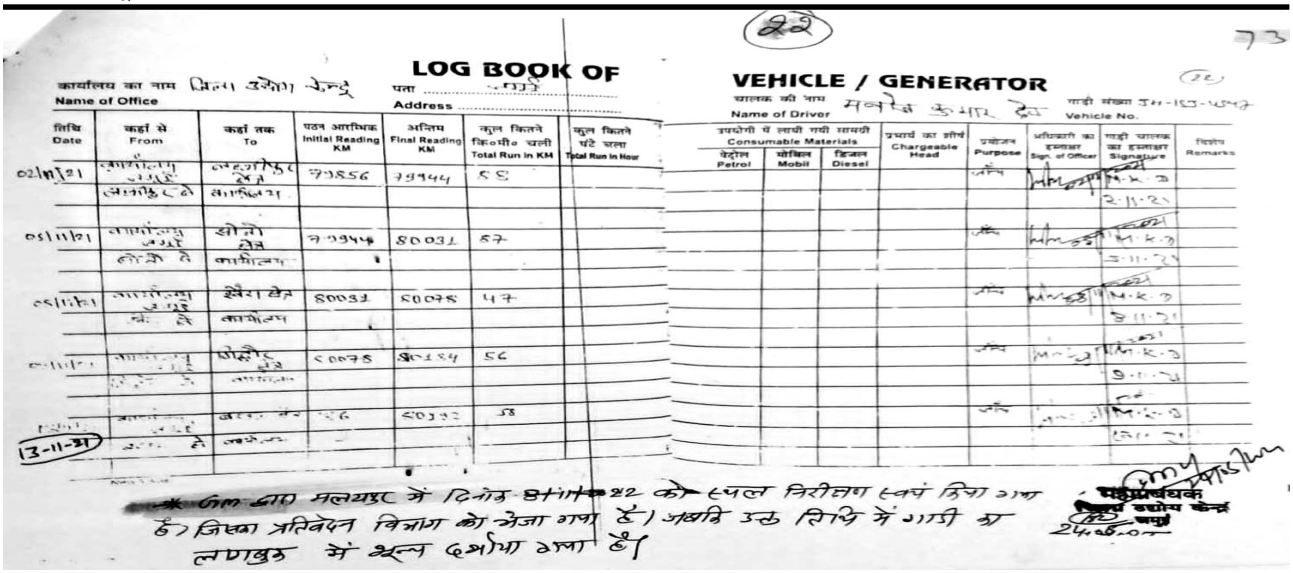
LOG BOOK OF VEHICLE / GENERATOR

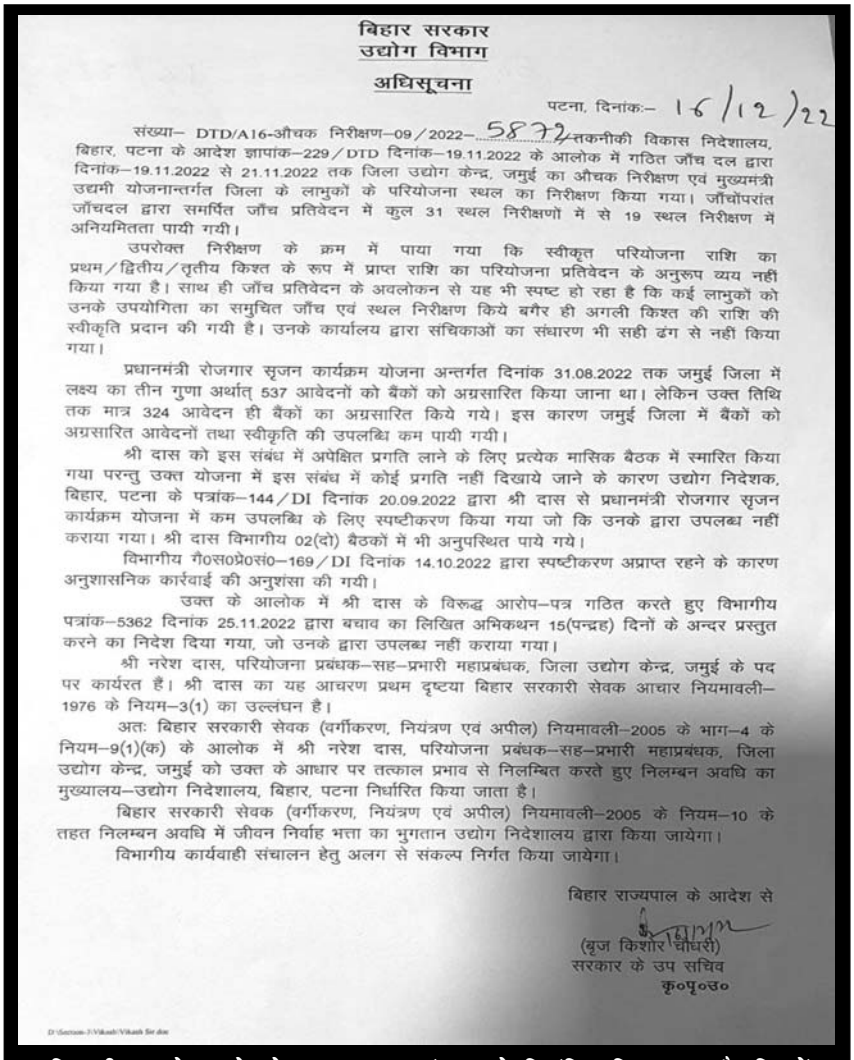

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 16/12/22

संख्या– DTD/A16-औचक निरीक्षण–09/2022–5877 तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–229/DTD दिनांक–19.11.2022 के आलोक में गठित जाँच दल द्वारा दिनांक–19.11.2022 से 21.11.2022 तक जिला उद्योग केन्द्र, जमुई का औचक निरीक्षण एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत जिला के लाभुकों के परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया। जाँचोपरांत जाँचदल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कुल 31 स्थल निरीक्षणों में से 19 स्थल निरीक्षण में अनियमितता पायी गयी।

उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत परियोजना राशि का प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में प्राप्त राशि का परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप व्यय नहीं किया गया है। साथ ही जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कई लाभुकों को उनके उपयोगिता का समुचित जाँच एवं स्थल निरीक्षण किये बगैर ही अगली किश्त की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उनके कार्यालय द्वारा संचिकाओं का संधारण भी सही ढंग से नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत दिनांक 31.08.2022 तक जमुई जिला में लक्ष्य का तीन गुणा अर्थात् 537 आवेदनों को बैंकों को अग्रसारित किया जाना था। लेकिन उक्त तिथि तक मात्र 324 आवेदन ही बैंकों का अग्रसारित किये गये। इस कारण जमुई जिला में बैंकों को अग्रसारित आवेदनों तथा स्वीकृति की उपलब्धि कम पायी गयी।

श्री दास को इस संबंध में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए प्रत्येक मासिक बैठक में स्मारित किया गया परन्तु उक्त योजना में इस संबंध में कोई प्रगति नहीं दिखाये जाने के कारण उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–144/DI दिनांक 20.09.2022 द्वारा श्री दास से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में कम उपलब्धि के लिए स्पष्टीकरण किया गया जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। श्री दास विभागीय 02(दो) बैठकों में भी अनुपस्थित पाये गये।

विभागीय गै0स0प्रे0सं0–169/DI दिनांक 14.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में श्री दास के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–5362 दिनांक 25.11.2022 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री नरेश दास, परियोजना प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के पद पर कार्यरत हैं। श्री दास का यह आचरण प्रथम दृष्टया बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–4 के नियम–9(1)(क) के आलोक में श्री नरेश दास, परियोजना प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई को उक्त के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि का मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के तहत निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बृज किशोर चौधरी)
सरकार के उप सचिव
कृ०पृ०उ०

विभागीय आदेश। जो नरेश दास, महाप्रबंधक को निलंबित किया गया है। जिसमें 31 में 19 योजना को गलत एवं गड़बड़ पाया गया, जिसका प्रतिवेदन अब तक जमुई के द्वारा नही दिया गया।

गया है। इससे पूर्व तत्कालीन महाप्रबंधक नरेश दास के द्वारा कार्यालय में बिना गाड़ी के उपयोग किये फर्जी लॉगबुक भरने में इनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया है, जिसकी राशि कि निकासी कर गबन कर लिया गया। जिस बात कि सूचना वहां के स्थानीय लोगों ने कार्यालय में जाकर दिया था। बावजूद फर्जी लॉगबुक भरने का फॉर्म उपलब्ध करवाया गया। महेंद्र प्रसाद के द्वारा दर्जनों ऋण लाभुकों का स्थलीय कार्य का निरीक्षण के पश्चात् गलत प्रतिवेदन देकर दूसरी एवं अंतिम किश्त जारी करने में मदद कि गयी है, जो इनके द्वारा जाँच किये गए सभी लाभुकों के कार्यस्थल कि फोटोग्राफ, जांच प्रतिवेदन एवं अघतन स्थिति का अवलोकन करने से सत्य की पुष्टि हो सकेगा।

विदित हो कि कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, जमुई के पत्रांक-323, दिनांक-03/08/2022 के द्वारा नोडल पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, मुख्यमंत्री उधमी योजना, प्रमंडल-मुंगेर को संबोधित पत्र में मोहम्मद अख्तर अली (आवेदन संख्या-CMEBC20219708155500) ग्राम पंचायत राज-सोनो (जिला-जमुई) के वार्ड संख्या-01 के वार्ड सदस्य हैं, के अभ्यर्थित्व को इसलिए निरस्त कर दिया गया कि विभागीय बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-1092, दिनांक-19/05/2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज से चयनित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री उधमी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। बावजूद महेंद्र प्रसाद के द्वारा ऐसा जानबूझकर कृत किया गया।

☞ **बिना गाड़ी रखे फर्जी लॉगबुक को भरकर गबन कर लिये लाखों रूपये :-** उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद जो नरेश दास, तत्कालीन महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र जमुई के कार्यकाल में झारखण्ड की रहने वाली स्कार्पियो वाहन की मालकिन श्रीमती मंजू देवी के नाम को आगे कर सम्पूर्ण राशि की निकासी कर दूसरे हाथ से वसूली कर लिये, जो मात्र गाड़ी मालकिन को पांच हजार रूपये हाथ उठाई देकर सभी की वसूली करते रहे, जो गाड़ी कभी भी सरकारी कार्यालय जिला उद्योग केंद्र जमुई के कैम्पस में देखा नही गया और नहीं किसी अधिकारी या कर्मी इस गाड़ी से कही भी सरकारी कार्य के निष्पादन के कही गये। चूकि गाड़ी JH15J/4547 (स्कार्पियो) सिर्फ पेपर में रखा गया था, जिस बात की जानकारी उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद एवं महेंद्र प्रसाद को था। जो गाडी कभी भी कार्यालय में नही चला अथवा देखा ही नही गया जिस बात पुष्टि कार्यरत उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमित कुमार यादव मोबाईल संख्या :- 9006888895, परिचारी अजय कुमार सिंह, सम्पर्क नम्बर :- 9549802995, परिचारी विपुल सिँह, सम्पर्क नम्बर:- 9709435182, संतोष कुमार राम (ऑपरेटर), सम्पर्क नम्बर :-7903670460 से किया जा सकता है। इस बात को दैनिक जागरण के स्थानीय रिपोर्टर विभूति कुमार सिँह, हिंदुस्तान के स्थानीय प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह के सितंबर 2022 में लिया गया वीडयो साक्षात्कार से प्रमाणित होता है। जिसमें वाहन मालिक श्रीमती मंजू देवी का स्कॉर्पियो कभी भी कार्यालय कैम्पस में कभी भी देखा नहीं गया। जिनका ब्यान स्थानीय अखबार में प्रकाशित भी हुआ था। मजे की बात और भी यह है की तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेश दास के द्वितीय सुपुत्र आशीष कुमार ने अपने पिता के करतूत को बताते हुये आरोप को सत्य कहा है। जिनका ऑडियो विभाग को सुपुर्द किया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी पिता जी घर पर स्कार्पियो से नहीं आये। यही नही आशीष ने अपने पिता के द्वारा किये गए भ्रष्टाचार से काली कमाई कर बांका में लगभग तीन करोड़ रूपये की लागत से मकान में खर्च को लेकर बताते हुए कहते हैं कि जब यह मकान बनया जा रहा था, तब मेरे पिता जी पूर्वी चम्पारण के घोरहसन अंचल के अंचल पदाधिकारी थे, जिसकी काली कमाई से यह सम्पति अर्जित किया गया तथा मेरे रहते घर पर दर्जनों लड़के पैसों की वसूली के लिये घर पर चढ़कर गाली-गलौज व मारपीट करने को आतुर

रहा करते थे। आशीष जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है।

सबसे इंट्रेस्टेड बात और साहस यह है की यह गाड़ी की मालकिन मंजू देवी वर्तमान में कार्यरत उच्च वर्गीय लिपिक निरंजन कुमार सिंह की पत्नी है तथा जिस गाड़ी से एकरारनामा किया गया वह कॉमर्शियल नहीं होकर प्राइवेट नम्बर की गाड़ी निबंधित है, जो झारखण्ड प्रदेश की है। विभागीय नियमानुसार यह गाड़ी विभाग में रखा जाना अवैध है। गाड़ी कॉमर्शियल नहीं होकर प्राइवेट नम्बर की गाड़ी है, जो गाड़ी दूसरे प्रदेश की है। बिना अनुमति लिये दूसरे प्रदेश की गाड़ी बिहार में वर्षो तक रखना ही अपराध है। वही जो सबसे बड़ा अपराध है की सरकारी सेवक रहते अपने पत्नी के नाम से गाड़ी इन सारे विभागीय नियमों को ताख पर रख ऐसा किया गया है। यह समझ से परे है।

बिना गाड़ी रखे फर्जी लॉगबुक को भरकर सरकारी राशि की निकासी कर लिया गया। जिस बात की जानकारी उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद एवं महेंद्र प्रसाद को थी तथा स्वयं उच्च वर्गीय लिपिक के द्वारा ऐसे कृत में नरेश दास के साथ शामिल हो गया। इसके अलावे जो दूसरे स्कार्पियो को चलते दिखाया गया है, वह जयराम कुमार है। जिसका गाड़ी मात्र तीन महीने ही चली थी। किन्तु इनके गाड़ी का फर्जी लॉगबुक भरकर एक साल का पैसों का निकासी करने वाले ही थे, तब तक कांड का उद्भेदन कर दिया गया। जिस फाइल में टिप्पणी किया गया है कि राशि उपलब्ध होते ही विधिवत भुगतान कर दिया जायेगा। इस बात की भी पुष्टि कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा किया गया है। जिस गाड़ी को अक्टूबर 2022 में रखा गया, उस गाडी का अग्रिम लॉगबुक मार्च 2022 से भरकर ऐसा गड़बड़ी किया गया, जिस बात की जानकारी उद्योग विस्तार पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद एवं वरीय लिपिक निरंजन कुमार सिंह को है। जिनके द्वारा रिश्वत लेकर ऐसा घपला किया गया। प्रथम लॉगबुक में समाहरणालय जिला जमुई से कार्यालय और कार्यालय से समाहरणालय का परिभ्रमण आठ किलोमीटर दिखया गया है, जबकि कार्यालय से समाहरणालय की दूरी मात्र 500 मीटर की है, जो सर्विदित है। वही कार्यालय से चकाई आने जाने की दूरी 127 किमलोमीटर दिखाया गया है, जो सत्य से परे है। मजे की बात है की दूसरे दिन भी निरीक्षण कार्य हेतु कार्यालय से चकाई आने जाने की दूरी 127 किलोमीटर दिखाया गया है। यानी पहले दिन 127 किलोमीटर चलने के बाद दूसरे दिन भी 127 किलोमीटर ही चला गया दिखाया गया है, जो एक फिक्स कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम की तरह है। प्रथम लॉगबुक की तरह महीने के बीच में एक बार भी पटना मुख्यालय या समाहरणालय जमुई में यात्रा किया गया नही दिखाया गया है, जो समझ से परे है। वही दूसरे लॉगबुक में नौ महीने के अंदर 27 बार समाहरणालय आना-जाना दिखाया गया है, जिसके मालिक जयराम कुमार हैं।

वर्ष 2018 से 30 जून 2023 तक जो वाहन पर ऋण दिए जाने की अनुशंसा की गई वह वर्ष 2018 से 2021 तक चार वाहन एवं 2021-22 से 2023 तक दो वाहन शामिल है, जिसमें केवल एक ही वाहन कॉमर्शियल है। जो राहुल पासवान, पिता-उपेंद्र पासवान, आवेदन संख्या:-CMSCST202118651806250 जिनका मोबाईल नम्बर :- 8651806250 (टूरिस्ट टैक्सी) है, बाकी सभी पांचो वाहन बब्लू कुमार, पिता-शिवशंकर तांती, आवेदन संख्या:-CMSCST201802449, सुनील कुमार, पिता-श्याम किशोर पासवान, आवेदन संख्या:-CMSCST201805664, राहुल कुमार रंजन, पिता-गोवर्धन दास, आवेदन संख्या:-CMSCST201805687, मोहम्मद सरफराज अंसारी, पिता:-मुस्ताक अंसारी, आवेदन संख्या:-CMSCST1420007253, रमेश कुमार दास, पिता-श्री पवन कुमार, आवेदन संख्या:-CMSCST202188735, जो सभी प्रावेट नम्बर के वाहन हैं। जिनके द्वारा सरकारी नियम एवं शर्त के विपरीत किया गया कार्य है, जिसमें भी गड़बड़ी किया गया है। जांच पदाधिकारी अमरीश आनंद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी ,जमुई के द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन दिया गया, वह दिनांक:-06/07/2022 से प्रतिवेदन किया गया। जो लाभुक के कार्यस्थल का निरिक्षण कर अंतिम किश्त दिलाने में सहायक थे, जिस बात की जानकारी उद्योग विस्तार पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद को थी। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है जिसे समझ पाना मुश्किल है। लाभुक रमेश कुमार दास टूर एंड टूरिस्ट के तहत वाहन के लाभुक थे, जिसने मुन्ना चप्पल दुकान के नाम पर सम्पूर्ण राशि की निकासी कर लिया। जिसे आगे कर तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेश दास ने पूरी राशि वसूल कर ली और इस कृत में ये सभी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री उधमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच जिला उद्योग केंद्र जमुई के लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि प्राप्ति के पश्चात् ही मशीन क्रय करने के बाद ही द्वितीय एवं अंतिम किश्त देय था किन्तु ऐसा नही कर सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन में अनिमियतता की गई। जिस कृत में तत्कालीन महाप्रबन्धक सहित विस्तार पदाधिकारी एवं वरीय लिपिक शामिल थे। जिनके द्वारा कार्यस्थल का झूठा प्रतिवेदन देकर भ्रष्टाचार किया गया तथा अतिमहवपूर्ण योजना को धरातल पर उतरने से रोका गया, जो उदाहरण के तौर पर कुछ देखा जा सकता है :-

☞ मनोज कुमार आर्या, जो मिठाई उत्पादन के नाम पर लाभुक हैं। जिनके द्वारा जूता-चप्पल पर व्यवसाय दिखाया गया है।

☞ बब्लू कुमार, टूर एण्ड टैक्सी से लाभुक हैं।

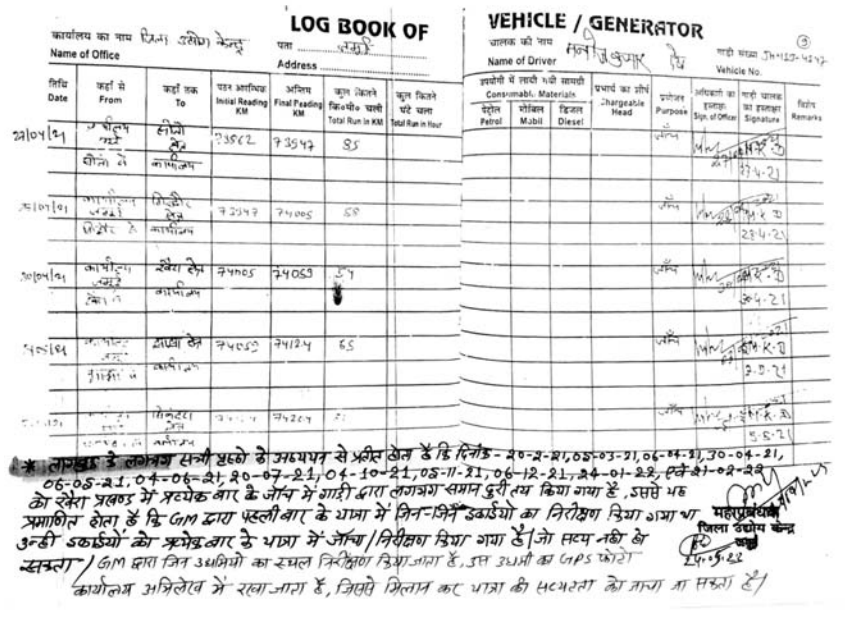

जिनके द्वारा PMEGP हैंडीक्राफ्ट दिखाया गया है।

☞ शिवशंकर तांती, जो चांदी आभूषण के नाम पर लाभुक हैं। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया है।

☞ लक्ष्मी कुमारी, जो ब्यूटी पार्लर के नाम पर लाभुक हैं। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया गया है।

☞ शैलेन्द्र पासवान, जो वस्त्र उद्योग पर लाभुक हैं। जिनके द्वारा मार्बल कटिंग किया जा रहा है।

☞ खुशबू कुमारी, जो टेंट हॉउस के नाम पर ऋण ली हैं। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया गया।

☞ गोल्डन कुमार, जो टेंट हॉउस पर लाभुक बने हैं। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया गया है।

☞ बबिता कुमारी, जो ब्यूटी पार्लर के नाम पर ऋण प्राप्त किया है। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया गया।

☞ पिंकी कुमारी जो रेडीमेड गार्मेंट्स के नाम पर लाभुक हैं। जिनके द्वारा कुछ भी नही किया गया।

☞ मुन्ना कुमार, टेंट हॉउस के नाम पर ऋण प्राप्त कर कुछ भी नही किया।

☞ राजेंश कुमार पासवान, जो टेंट हॉउस के नाम पर ऋण प्राप्त किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं।

☞ रत्नेश्वर कुमार, जो मुर्गी दाना के नाम पर ऋण प्राप्त किया। लेकिन किया कुछ भी नही।

☞ प्रभा कुमारी, जो ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर ऋण प्राप्त किया, लेकिन किया कुछ भी नही।

(32)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक- 109 /पटना, दिनांक- 09.01.2023
सं०सं०- 4तक०/मु०मं०उद्यमी योजना-निरीक्षण/167/2022

प्रेषक,
संजीव कुमार (भा०प्र०से०),
निदेशक,
तकनीकी विकास, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

विषय:-मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 एवं 2021-22 में तृतीय किश्त स्वीकृत/भुगतान किये गये लाभार्थियों का स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक निम्नवत उद्यमियों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान किया गया है:-

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक
मु0मं0अ0जा0/अ0ज0 उद्यमी योजना	3267	264
मु0मं0 अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना	1274	249
मु0मं0 युवा उद्यमी योजना	-	257
मु0मं0 महिला उद्यमी योजना	-	289

सभी तृतीय किश्त प्राप्त लाभुक के उद्यमियों का वर्तमान परिस्थिति में व्यवसाय के पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। पर्यवेक्षण के दौरान स्थलीय जाँच के लिए जाँच प्रारूप भी संलग्न किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि शीघ्रताशीघ्र तृतीय किश्त प्राप्त लाभुकों के उद्यम का स्थलीय जाँच कराया जाय तथा सभी सफल उद्यमियों को चिन्हित करते हुए उनके सफलता की कहानी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय। साथ ही जिन उद्यमियों द्वारा तृतीय किश्त प्राप्त करने के पश्चात् भी उद्यमी योजना की राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है, उनसे नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया भी अपनायी जाय। दो सप्ताह के अंदर उपरोक्त प्रतिवेदन जाँच प्रपत्र एवं फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

अनुलग्नक- यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
09.01.23
निदेशक,
तकनीकी विकास, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

जिन सभी के द्वारा सभी किश्त की राशि यानी दस लाख रूपये की निकासी कर भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसे लाभुकों की संख्या कम से कम डेढ़ सौ है। जिसके जाँच पदाधिकारी स्वयं तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेश दास थे तथा इनके सहयोगी उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमरीश आनंद एवं महेंद्र प्रसाद के अलावे उच्च वर्गीय लिपिक निरंजन कुमार सिंह हैं। वही महेंद्र प्रसाद जो बांका में इससे पूर्व अंचल अधिकारी थे, जिनके द्वारा अवैध वसूली से करोड़ों की सम्पति अर्जित किया गया है और जो वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र जमुई में ही कार्यरत हैं। अमरीश आनंद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं, जो वर्तमान मुख्यालय, पटना में पदस्थापित हैं, तथा उच्च वर्गीय लिपिक निरंजन कुमार सिंह जो देवघर में निवास करते हैं, जिनके पास जिले में वैसा मकान किसी के पास नही हैं, जो दो बीघा जमीन के कैम्पस में बना है। जिसकी लागत करोड़ो में है। फिलहाल यह भी जमुई उद्योग केंद्र में पदस्थापित है।

परिवाद की सुनवाई कर रहे प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार श्री संजय सिंह के न्यालय ने सभी मामले की जाँच के लिये जिला अपर समाहर्ता सामाजिक सुरक्षा सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र जमुई से आरोप की जाँच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ स्वयं उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया है। जिसमें मामले का उद्भेदनकर्ता त्रिभुवन प्रसाद यादव से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सह व्हिसिल ब्लोयर त्रिभुवन प्रसाद यादव ने कहा की जमुई के अलावे छपरा (सारण) में भी ऐसी ही बद्तर स्थिति है। योजना के आलावे जिले में गाड़ी का लॉगबुक भरा ही नही गया है। श्री त्रिभुवन ने कहा कि उक्त बात की भनक लगते ही विभागीय स्तर पर वर्ष 2018 से 2023 तक के सभी लाभुकों का कार्यस्थल की जाँच हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है तथा गड़बड़ी करने वालो से सम्पूर्ण राशि की निकासी करने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो जिले से अबतक रिपोर्ट नही आ सका है। उन्होंने कहा कि सही से जाँच हो तो अरबों रूपये के गबन एवं भ्रष्टाचार का उजागर होगा, जो हमने सैम्पुल के रूप में जमुई का चयन किया है। श्री त्रिभुवन ने कहा की इन सारे राशि की निकासी जाँच पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक से की जानी चाहिए, जिनके गलती के कारण लाभुक गलत फायदा उठाये हैं। जो यह सब जानते हुये की विभागीय नियम से इतर कार्य किया जा रहा है, नही कह कर करवाया गया है।●

भाजपा या राजद को एक सीट भी घटा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारत में शायद एक ऐसा चाणक्य हैं जीने की तुलना में शायद ही कोई मिलेगा। नीतीश कुमार जनता का विश्वास हो चुके हैं। अब एक सीट भी जीतने के काबिल नहीं है। पिछली बार चुनाव में चिराग पासवान को हटने से नीतीश कुमार को अपनी औकात का पता चल गया? यदि भाजपा साथ नहीं होता तो एक सीट भी नहीं जीत सकता है। चुनाव के बाद भाजपा यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो उस समय राजद में चले जाते? नीतीश कुमार को यदि राजद ने मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो भाजपा में चले जाते तथा मुख्यमंत्री का ताज पहन लेते?

बिहार में राजनीतिक लड़ाई सिर्फ भाजपा और राजद के बीच में ही रह गई है। नीतीश कुमार को भाजपा या राजद को साथ में रखना दोनों के लिए खतरे की घंटी है। बिहार की धरती पर एक भी आदित्यनाथ योगी की तरह बड़े -बड़े पद पर बैठे भाजपाइयों के गर्भ से पैदा होते तो भाजपाई को सत्ता मिल सकती हैं। बड़े-बड़े पद पर बैठे लोगों ने सिर्फ तीन ही काम सीखा है, कार्यकर्ताओं से नारा लगवाना, माला पहनना और फोटो खिंचवाना? बड़ -बड़े पद पर बैठे लोग, विधायक ,सांसद या मंत्री मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का एक सूची भी कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंचाया।

बताया जाता है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल द्वारा बार-बार लिखा जाता है कि

बड़े-बड़े पद पर बैठे भाजपाई सिर्फ तीन ही काम जानता है कार्यकर्ताओं से नारा लगाना माला पहनना और फोटो खिंचवाना , इसी का असर समुचे देश में हो रहा है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झकझोर दिया है, जिसके कारण ही बिहार में संगठन को सुधारने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में एक महीना के लिए आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना ? 5 अक्टूबर को पटना आएंगे तथा एक महीना रहकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बड़े-बड़े पद पर बैठे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी भी नहीं जा रही है। यहां पर कुछ उदाहरण दी जा रही है जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम परिवहन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम वरिष्ठ पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण जिला साक्षरता अभियान, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीन कौशल्या योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रम एवं ज्योति योजना अटल मिशन, स्वदेश दर्शन योजना, पूरन स्कीम नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरु ग्रंथ मिशन, प्रकाश पाठ विकल्प स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, आधार बिल, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, टीवी मिशन, धनलक्ष्मी योजना, गंगाजल डिलीवरी स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, सामाजिक अधिकारिता सिविल रेलवे यात्री बीमा योजना, स्मार्ट गंगा सिटी आदि 200 से ज्यादा चलाई जा रही है, योजनाओं को घर-घर तक पहुंचा कर मजबूत संगठन बनाए जा सकती है, संगठन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है, परंतु कार्यकर्ता को जानकारी तक नहीं दी जा रही है।●

गोपालगंज जिले में थानों से मिलेगी प्राप्ति रसीद

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

गोपालगंज जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिया है की थाने में पहुंचने वाली हर शिकायती पत्र की प्राप्ति रसीद पुलिसकर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता को देनी होगी। थानों में आने वाले कई शिकायत की पत्रों के गुम होने का बहाना बनाकर अक्सर पुलिस पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन अब तो थाने से कोई शिकायत की पत्र गायब होगा, और नहीं थाने से कोई शिकायतों को छुपाया जा सकेगा। अब कार्रवाई की रिपोर्ट भी 15 दिनों के अंदर देनी होगी रसीद ना देने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के सभी थानों में प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद भेज दी गई है। व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रत्येक थाने पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। और शिकायत लेकर थाने पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित पुलिसकर्मी शिकायत पत्र लेकर प्राप्ति रसीद देगा। प्राप्ति रसीद छत पर अपना नाम, तिथि सहित हस्ताक्षर करेंगे तथा थाने के मुहर लगाएंगे।

रसीद में आवेदक का नाम, घर का पता मोबाइल नंबर, विवाद का कारण ,जांच करने वाले पदाधिकारी का नाम, जांच करने वाले पदाधिकारी का मोबाइल नंबर, शिकायत पत्र दिए जाने की तारीख ,यह व्यवस्था एसपी कार्यालय से लेकर सभी थानों पर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। थाना रजिस्टर में दर्ज होगी लोगों की समस्या। स्थान पर शिकायत पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से संबंधित जानकारी थाना रजिस्टर में दर्ज करेगा। थाना रजिस्टर में आवेदक का नाम, पता अन्य आवश्यक विवरण, जांच अधिकारी का नाम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक व जांच करवाई का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके आधार पर ही शिकायतकर्ता उसकी शिकायत के निस्तारण के बारे में जानकारी दी जाएगी। समस्या का 15 दिनों के अंदर निस्तारण कर इसके संबंधी सूचना भी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने गोपालगंज जिला पीएसपी को बहुत-बहुत बधाई दी है तथा बिहार के सभी एसपी से अनुरोध किया है कि आप भी ऐसे ही व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें, तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि आप सभी थानों में ऐसे ही व्यवस्था करें।●

जनसंख्या वृद्धि सत्ता की सीढ़ी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पतन कई स्तरों पर हुआ है। धर्म की दृष्टि से,आचरण की दृष्टि से,भावनाओं की दृष्टि से तथा चारित्रिक दृष्टि से भी पतन हुआ है। आज कोई भी राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभभाई पटेल ,जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी ,पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह वैचारिक ऊर्जा से परिपूर्ण नेता नजर नहीं आ रहा है। जनता ने भी नेताओं का चयन करने से पूर्व नेताओं का चरित्र,प्रकृति, गुण, व्यवहार आदि की जांच पड़ताल नहीं करती है। अधिकांश राजनीतिज्ञों के नजरों में जनसंख्या वृद्धि ही सत्ता की सीढ़ी है या जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है उन्हीं के पास सत्ता होगी। बताया जाता है कि जनगणना आयुक्त डोनाल्ड ने 1801 ईस्वी में ही कहा था कि 620 वर्ष में हिंदू समाप्त हो जाएंगे। 1991 की जनगणना के बाद डॉक्टर रफीक जकरिया ने लिखा है कि मुसलमान 365 वर्ष के बाद भारत में बहुमत में होंगे। डॉ भीमराव अंबेडकर भारत के भविष्य को देखते हुए ही कहा था कि मुस्लिम आबादी की समस्या को सुलझाने के लिए ही पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया था तथा जनसंख्या अदला बदली का सुझाव भी दिया था परन्तु ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम समान नागरिक सघिंता भी नहीं मानते। राजनितिज्ञों की नजर में मुस्लिम गोलबंद वोट बैंक है। यह चुनौती असाधारण है, मुस्लिम मजहब का वास्ता देकर परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। हिंदू भी यदि ऋग्वेद के अनुसार संस्कृति सूत्र पर चलने लगे तो जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या होगा? ऋग्वेद (10,85, 45) में नवविवाहितों के लिए प्रार्थना है कि हे इंद्रदेव आप उसे सौभाग्यशाली मनाएं और 10 पुत्रों वाली बनाएं। यदि सभी लोग ऋग्वेद में बताए अनुसार चले तो देश का भविष्य का क्या होगा। कई इस्लामी देशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम अपनाएं हैं। ईरान ,पाकिस्तान, मिश्र, कजाकिस्तान ,कुवैत, ओमान ,कतर ,सऊदी अरब, बनई और अजर, वैजान की आबादी इस प्रयास से स्थिर हो गई है अल्बेनिया, फिलिस्तीन और सिरिया की आबादी ऋणा आत्मक है।

फिलहाल बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु तमाम भारतवासियों को सचेष्ट होना पड़ेगा। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम,सिख हो या इसाई। जनसंख्या नियंत्रण के कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि भारत के राजनीतिज्ञों ने ध्यान नहीं दिया तो भारत का अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो जाएगा। जो समाज देश हित में जनसंख्या को नियंत्रण रखनी होगी तथा जनसंख्या नियंत्रण रखने वाले समाज को सम्मानित करना चाहिए।●

योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी : डॉ. लक्ष्मी

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने भाजपा के बड़े-बड़े पद पर बैठे भाजपाइयों से आग्रह किया है की कार्यकर्ताओं से नारा लगवाना, फोटो खिंचवाना आवश्यक नहीं है। यह समय की बर्बादी है, ऐसे महत्वपूर्ण समय को बर्बादी होने से बचाएं तथा समय का सदुपयोग करें? सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही योजनाओं को हर लाभुकों तक पहुंचाएं। कुछ दिन पूर्व खुसरूपुर में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव आए तथा दोनों मंडल अध्यक्ष को 15 सितंबर तक बूथ स्तर पर कमेटी, पन्ना प्रमुख का गठन करने के साथ ही बूथ पालक नियुक्त करने का निर्देश दिया। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कौन कहे विश्वकर्मा योजना का कोई चर्चा तक नहीं की गई। जबकि विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले सभी लोगों को बुलाकर हर बूथ पर मेला लगा देना चाहिए था जैसे वोट देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार सूची बनाकर सभी लोगों को एक लाख लोन तथा रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हर बूथ पर मेला लगवा देना चाहिए। इस योजनाओं के ट्रेनिंग में 500 रुपए प्रति दिन दी जाएगी ।भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि नंदकिशोर यादव को बैठक में आने का एक ही उद्देश्य था, कार्यकर्ताओं से माला पहनना और फोटो खिंचवाना जबकि उनका उद्देश्य होना चाहिए था कि मोदी जी द्वारा चलाई जा रहे सभी योजनाओं को हर एक कार्यकर्ताओं को जानकारी देना तथा योजनाओं को हर घर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में सहयोग करना, साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना को मिली मंजूरी में लोहार, बढ़ई,राज मिस्त्री समेत 30 वर्गो के लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों को एक लाख रुपए तक का लोन पांच प्रतिशत व्याज पर दिया जाएगा। 30 लाख शिल्पकार परिवार इससे लाभान्वित होंगे। यह योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हो गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है।

इनमें बढ़ई,नौका बनाने वाले, लोहार, हथोड़ा और औजार बनाने वाले ,सुनार, कुम्हार,पत्थर की कारीगरी करने वाले, चर्मकार , राजमिस्त्री ,दरी, झाड़ू एवं टोकरी बनाने वाले, धोबी, दर्जी,नाई, ताला चाभी, मछली पकड़ने वाले का दाल बनाने वाले, जाल बनाने वाले शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों ,शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दी जाएगी।

☞ **क्या है योजना** :- दो तरह की स्किल ट्रेनिंग बेसिक और एडवांस।500 रुपए का दैनिक भत्ता रोजाना ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। 1 लाख तक लोन 5% ब्याज पर पहले चरण में 2 लाख का रियायती दर पर दूसरे चरण में दिया जाएगा ।15000हजार की मदद आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए दी जाएगी। बड़े-बड़े पद पर बैठे लोग विश्वकर्मा योजना का चर्चा करना भी शायद फिजूल समझते हैं। बड़े-बड़े पद पर बैठे लोग तीन ही काम जानता है कार्यकर्ताओं से नारा लगवाना, माला पहनना तथा कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाना।●

फतुहा क्रांतिकारियों का स्थान

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि फतुहा क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता है। फतुहा के क्रांतिकारियों ने फतुहा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठे दो अंग्रेज को मारकर एवं ट्रेन से उतारकर दोनों को एक बोरा में कसकर और टमटम पर लाद कर पुनपुन नदी में डाल दिया गया था। इसी घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने फतुहा को तोप से उड़ा देने का फैसला लिया था। इस केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वय कोर्ट में बहस किया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था की दोषी तो कुछ ही लोग होगा, ऐसे स्थिति में पूरे फतुहा वासी को सजा देना ठीक नहीं है। इसी बीच भारत को आजादी मिल गई। उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने फांसी के सजा प्राप्त, आजीवन सजा 10 साल सजा आदि को सजा मुक्त कर दिया। इस कारण सजा से लोग बच गए।

★ फाँसी की सजा जिन्हें सुनाया गया था :-

1. बिहारी तिवारी 'महंथ' - बांकीपुर गोरख
2. त्रियुगी नारायण दुबे - कल्याणपुर
3. बिन्दा ठठेरा-बांकीपुर गोरख
4. सिराजुद्दीन मियाँ-सोराकोठी
5. मरन दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर
6. प्यारे दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर
7. झोपड़ी दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर
8. राघो गोप-गोविंदपुर।

★ आजीवन कारावास :-

1 अमृत दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर

2. बुलाकी दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर
3. द्वारिका तिवारी-बांकीपुर गोरखपुर
4 हरिद्वार तिवारी-बांकीपुर गोरखपुर
5. नत्थु दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर
6. विशुन गोप-नोहटा
7 भोला दुसाध-बांकीपुर गोरखपुर

★ पाँच वर्ष का कारावास :-

1 गौरी महतो-भोजीपुर
2. गनौरी महतो-रायपुर
3. जमुना कुर्मी-शैदपुर
4 शिवनन्दन दुसाध-सोराकोठी

★ सन् 1921 एवं 1932 के आन्दोलनों में गिरफ्तार फतुहा के आन्दोलनकारियों की सूची :-

1. स्व० हरिनारायण पाठक-बाँकीपुर गोरख (प्रमोद शरण पाठक जी के पिता)
2. स्व० राम हरि सिंह-देवी चक
3. स्व० वेणी सिंह-दरियापुर
4. स्व० जीतेन्द्र तिवारी-बाँकीपुर गोरख (रामचंद्र तिवारी के पिता)
5. स्व० केवल सिंह
6. स्व० बिहारी तिवारी- बाँकीपुर गोरख
7. स्व० प्रमोद शरण पाठक-बाँकीपुर गोरख
8. स्व० राम गुलाम साव-दरियापुर
9. स्व० रामचन्द्र सिंह-देवीचक
10. स्व० विश्वेश्वर पाण्डेय- गोविंदपुर
11. स्व० बाबू लाल-गोविन्दपुर
12. स्व० श्री वासुदेव सिंह-चक बिहारी
13. स्व० रामाशीष सिंह-चक बिहारी
14. स्व० बाबू लाल मिस्त्री-चक बिहार
15. स्व० शिव दयाल महतो-उसफा
16. स्व० गौरी शंकर पाण्डे-उसफा
17. स्व० सिद्धेश्वर तिवारी-उसफा
18. स्व० राम प्रसाद सिंह-अब्दुल्लाह चक
19. स्व० लखन देव सिंह- सैदनपुर
19 हरकधारी धारी महतो-तुर्कडीहा परिशिष्ट

★ अगस्त क्रान्ति, 1942 में 12/8/42 को गिरफ्तार फतुहा के आन्दोलनकारियों की सूची :-

1. स्व० श्री रामचन्द्र तिवारी- बाँकीपुर गोरख
2. श्री परमात्मा सिंह-मसाढ़ी
3. श्री रामनारायण मस्ताना-नोहटा
4. स्व० ललित नारायण पुरी-चौराहा
5. स्व० कुलदीप प्रसाद-चौराहा
6. श्री बांके बिहारी निर्मल-सिगंरियावाँ (जिस त्रिवेणी घाट पर अंग्रेजों को पुल से डुबाया गया था, उसी स्थान पर वारणी मेला लगता है)।●

बेरोजगारी और मंहगाई का झूठा ढ़ोल पीटते हैं राहुल : सिंटू सिंह

● अमित कुमार

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अक्सर कहा जाता रहा है कि देश में 2014 के बाद से बेरोजगारी और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजग सरकार भेल और रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। बीते कुछ माह पहले तेलंगाना में मेडक जिले के पेद्दापुर गांव में एक सभा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वह जब भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवाओं से मिले, वे बेरोजगारी की बात करते हैं। आप सभी को समझना चाहिए कि देश में बेरोजगारी क्यों है? आपने देखा होगा कि देश में 2014 से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। साथ ही कहा कि किसान, छोटे और मध्यम कारोबारी बड़े व्यापारिक घरानों की तुलना में लोगों को अधिक रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के साथ ही टैक्स की लूट एवं बेरोजगारी की सुनामी आ गई है। बीजेपी राज में एलपीजी सिलिंडर की कीमतें 157 प्रतिशत बढ़ी, रिकॉर्ड-तोड़ महंगा पेट्रोल, और बेरोजगारी की सुनामी आई। राहुल ने मंहगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया था। राहुल ने कहा था कि देश में आर्थिक मंदी साफ नजर आ रही है, लेकिन नीतिगत दिवालियेपन की शिकार सरकार को यह नहीं दिख रहा और इसे लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि देश में आज प्रति व्यक्ति आय 2 साल पहले की तुलना में कम हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि देश में हर परिवार महंगाई और नौकरियां जाने की मार झेल रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय दो साल पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 94,270 रुपये से घटकर 91,481 रुपये हो गई है। लेकिन सरकार को यह नजर नहीं आ रहा।

पार्टी अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान के साथ सिंटू सिंह

गौरतलब हो कि राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बेगूसराय जिले से कद्दावर नेता सह समाजसेवी एवं हमेशा अपनी क्रांतिकारी आवाज को बुलंद करने को लेकर चर्चाओं में बने रहने वाले सिंटू कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी हमेशा महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, की दुहाई देते हैं। लेकिन वह अपना दौड़ भूल जाते हैं। इन्हीं यूपीए मनमोहन सिंह 2004 से 2014 के शासनकाल में महंगाई दर देश में 8.01% थी लेकिन आज की महंगाई दर एनडीए नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 5.01% महंगाई दर है। यही यूपीए की सरकार में भारत दुनिया का 10वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज 2023 में मोदी जी के शासनकाल में दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं (3750 अरब डॉलर) के साथ अर्थव्यवस्था भारत बन गई है।, दुनिया में यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, और ब्राजील, जैसे देश को पीछे छोड़ा है, आज दुनिया की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था में बढ़ने वाला भारत देश है, शायद मोदी जी इसी विश्वास के साथ कहते हैं। तीसरे टर्म में दुनिया के सबसे बड़े तीसरे अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और आज इस बात को दुनिया भी मानती है की, 2027 तक यह संभव है। और आज यही कारण है कि भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद होते जा रहा है। और दुनिया के लोग भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर करने को तैयार हैं। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय जीडीपी देश का 2 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन आज 2023 की बात करें तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर बढ़कर हो

सिंटू सिंह

गया, आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है, हमारा देश निर्यात नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और यह सिर्फ 5 वर्षों में देखने को मिला, राहुल गांधी जी कहते हैं। बेरोजगारी चरम पर है। उन्हें पता होना चाहिए लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो भारत का नया मिडिल क्लास बन गया है।, और आज यही डर कांग्रेस के राहुल गांधी व पूरे इंडिया गठबंधन को सता रही है।, वही लोजपा (रामविलास) नेता सिंटू सिंह ने कहा कि आज मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बजट की बात करें तो 15.59 लाख करोड़ था, मोदी जी के कार्यकाल में चल रहे वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़ कर 45.3 लाख करोड़ हो गया है।, यानी 2014 के बाद से 189 गुना ज्यादा बजट बढ़ गई है खर्चा बढ़ गई है।,और ऐसा इसलिए है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, जैसे रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, खेल स्टेडियम, देश में नए निर्माण हो रहे हैं, 2014 तक मनमोहन जी के सरकार में 12.4% लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किए गए, वही नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 43.9% लाख करोड रुपए खर्च किए गए, यह खर्च कहां हो रहा है। अगर इसके आंकड़े को देखते हैं, तो 2014 में देश के अंदर 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज मोदी जी के शासनकाल में वर्ष 2023 तक में बढ़कर 693 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं।, 2014 में एम्स केवल 6 थे जो अब बढ़कर 24 हो गए, 2014 से पहले देश में 727 यूनिवर्सिटी थे, जो अब बढ़कर 1472 यूनिवर्सिटी हो गया है।

2014 में 16 आईआईटी यूनिवर्सिटी थे, लेकिन आज 2023 में 23 आईआईटी यूनिवर्सिटी हो गए हैं।, 2014 तक बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट देश में हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद आज 2023 की बात करें तो बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़कर 4.7 लाख मेगावाट किया गया है, 2014 में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे लोगों के पास, लेकिन आज 2023 में 31 करोड लोगों के पास गैस कनेक्शन पहुंच गए हैं।, सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 में 91287 किलोमीटर थी, लेकिन 2022 में बढ़कर 1.44 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 2014 में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी,जो 2023 में बढ़कर 148 एयरपोर्ट की संख्या हो गई है।, इस पर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं बोलते हैं।, इस पर चूपी साध लेते हैं।, वही श्री सिंह ने कहा; कि आज भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है।, आज भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है, 2014 से पहले हमारे देश में 100 से कम स्टार अप्स थे लेकिन आज इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। और आज यही कारण है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया, स्टार्टअप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं।, लेकिन इस पर यूपीए गठबंधन के महान नेता राहुल गांधी जी मैन धारण कर लेते हैं। बदलाव तभी होगा जब आप देश के नीचे पायदान पर बैठे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, व गरीबों को पिछड़ों को मुख्य धारा से जुड़ेंगे और देश की यह कमी मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझ रहें हैं। और यही कारण है। कि धीरे-धीरे हमारा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में अग्रसर है। तुम मेरे पीछे लगे रहो हम देश को आगे ले जाने में लगे रहेंगे। ●

बंद मकान से युवक का शव बरामद

● **बेंकटेश कुमार**

सुशासन कही जाने वाली सरकार में थाना के महज एक किलोमीटर की दूरी पर एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। बिहार सरकार दंभ ठोकती है कि मेरे शासन में कानुन का राज है, लेकिन यह हत्या सरकार, शासन, प्रशासन की पोल खोल देती है। जी हाँ, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत महमतपुर गाँव में तब अफरा-तफरी मच जाती है, जब एक बंद मकान में एक युवक की लाश बरामद होती है। जानकारी के मुताबिक मृतक अंशु कुमार, पिता केशव मिस्त्री, मखदुमपुर बस स्टैण्ड का निवासी था। मृतक अपने घर से तकरीबन एक बजे अपने घर से निकलता तो जरूर है पर वह वापस जिंदा नहीं लौटता है, लौटता है तो उसका केवल मृतक शरीर। उसके घर में उस समय केवल उसकी पत्नि थी, बताते चले कि उसका अपना कोई औलाद भी नहीं था।

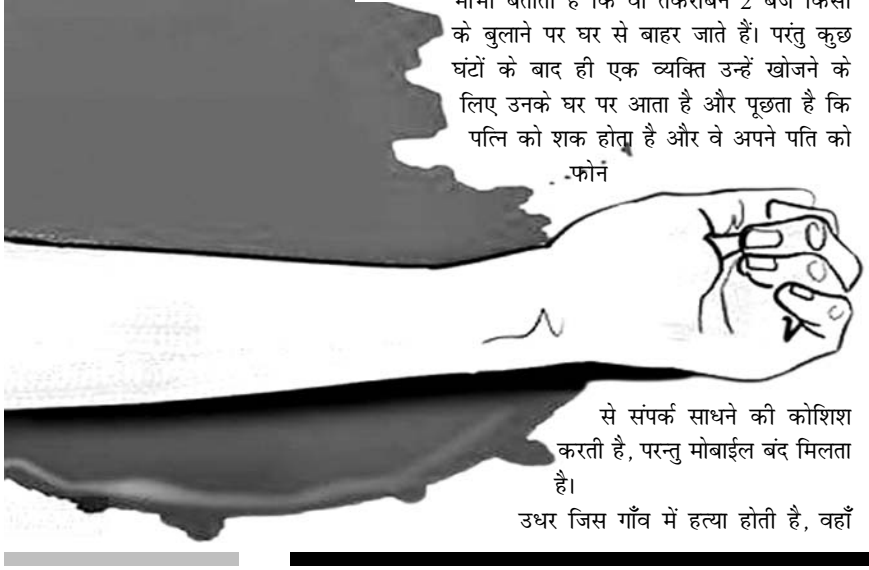

जब मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके घर गया तो मेरी बात मृतक के बड़े भाई, साले एवं उसकी भाभी से हुई, जो बाहर झारखंड में रहते थे। उन्होंने बताया कि हमलोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, जब पता चला तो आनन-फानन हमलोग घर पहुँचे। उनकी भाभी बताती है कि वो तकरीबन 2 बजे किसी के बुलाने पर घर से बाहर जाते हैं। परंतु कुछ घंटों के बाद ही एक व्यक्ति उन्हें खोजने के लिए उनके घर पर आता है और पूछता है कि पत्नि को शक होता है और वे अपने पति को फोन से संपर्क साधने की कोशिश करती है, परन्तु मोबाईल बंद मिलता है।

उधर जिस गाँव में हत्या होती है, वहाँ के स्थानीय लोग मृतक की हत्या के कुछ घंटों पहले ही पुलिस की 112 नम्बर डायल कर जानकारी देते हैं कि एक बंद मकान में किसी के मारने-पिटने की आवाज आती है, हालांकि 112 नम्बर की पुलिस वहाँ जाती भी है, परंतु वह मकान बंद मिलता है। पुलिस वापस चली जाती है। जब मृतक की पत्नि पुनः थाने में जाती है, तो पुलिस दल-बल के साथ जाती है और मृतक का शव उस बंद मकान से बरामद करती है। जब मैं थाना-प्रभारी से जानने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है तथाकथित के द्वारा यह भी पता चलता है कि हत्या के पीछे कुछ पैसा का लेन-देन भी रहा है। पुलिस जॉच में जुटी है। पुलिस आरोपित तीन व्यक्ति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बताते चले कि तीनों अपराधी पुलिस के सामने कबुल भी किया है कि हत्या हमलोगों ने की है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मृतक नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से पैसा लिया था। नौकरी नहीं लगने पर लोगों ने लगातार मृतक से पैसे की मॉग कर रहे थे।

कारण कुछ भी हो परंतु आरोपित को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए कानुन है, न्यायालय बना हुआ है।●

पुल क्षतिग्रस्त

बरनार कॉजवे देखने पहुँचे नीतीश कुमार

सुशासन काल में बना पुल-पुलिया और सड़क सुशासन काल में ही ध्वस्त होते देखा जा सकता है। जमुई में विकास का जो इमारत देखा जा रहा था उस इमारत पर बालू माफिया, कमीशन खोरी और जिला प्रशासन की कुदृष्टी लग गई है। मुख्यमंत्री जी जिस जनता ने आपको सर ऑखों पर बैठाया था कहीं उसी जनता के कोपभाजन के शिकार न होना पड़े आपको। जमुई से हमारे जिला ब्यूरो अजय कुमार की रिर्पोटः-

● **अजय कुमार**

सोनो को चरकापत्थर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल टूट गया। शायद यह जमुई जिला में पड़ने वाला सबसे लंबा पुल रहा होगा। यह पुल निश्चित रूप से चकाई के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे सुमित सिंह के प्रथम विधायकी काल में बना था। उस समय सुमित चकाई से झामुमों से जीत कर आये थे और शायद मैं प्रथम व्यक्ति होगा जो बरनार जलाशय परियोजना और बरनार पुल के विषय में सुमित से पूछा था और आज करीब 15 वर्षों बाद यह पुल बनकर तैयार और पुल धरासायी भी हो गया। टुटे पुल को देखने बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी पहुॅचे और जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया पर क्या लाखों लोगों को जोड़ने वाला यह पुल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा?

कभी नक्सलियों के आगोस में रहने वाला सोनो-चरकापत्थर थाना क्षेत्र को जोड़ने वाला इसी पुल के कारण इन लाखों लोगों को नक्सलियों के आतंक से निजात मिल पाया था। यह पुल उस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 15 वर्षों पूर्व चरकापत्थर जाने से पहले पुलिस सौ बार सोंचती थी। कई बार तो नक्सल घटनाएं घट जाने के घंटों बाद क्या अगले दिन तक पुलिस नहीं पहुॅच पाती थी। हमारा भी घर चरकापत्थर थाना क्षेत्र का महेश्वरी गॉव में पड़ता है। राजपूतों और पंडितों का यह गॉव सोनो से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है और हम खुद सैंकड़ो बार अपना गॉव महेश्वरी पैदल या फिर

बैलगाड़ी से सफर किया था। आप सोंच सकते हैं कि यह क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा। आज इन क्षेत्रों में पुल-पुलिया और सड़कों का जाल बिछ चुका है। नक्सल घटनाओं के लिए जाना जाने वाला चरकापत्थर थाना क्षेत्र आज विकास की नई गाथा लिख रही है। यह सारा कुछ इसी पुल के निर्माण के बाद हो पाया था या नहीं तो इस नक्सल प्रभावित जंगलों और पहाड़ों से घिरा क्षेत्र से न तो नक्सलवाद समाप्त हो पाता और न ही यहॉ के लोगों में शिक्षा हो पाती। आज प्रखंड के हर पंचायतों में हाई स्कुल बन चुका है और मैट्रिक तक की पढ़ाई अपने पंचायत में ही बच्चियों को मिल जा रही है। यही नहीं कभी पूरे पंचायत में कोई लड़की मेट्रीक पास कर लेती थी तो उसे गॉव का सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी लड़की माना जाता था।

आज जब जिले में पुल-पुलिया और सड़कों का जाल बिछ चुका है तो कई सड़क और पुल-पुलिया छतिग्रस्त हो चुकी है और फिर भारी और बड़े वाहनों के आवागमन को जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। वैसे भी कई सड़क है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त होकर पूर्व के भांती हो चुके हैं। 15 वर्षों पूर्व हम कई वैसे समाचार लिख चुके हैं जिसमें हम जिक्र करते थे कि सड़क है या गडढ़ा यह पता भी नहीं होता था या फिर गर्भवती महिलाएं का बच्चा रास्ते में ही हो जाए वैसे गडढ़े वाले न्यूज भी आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकता है।

2010 के बाद बना बरनार कॉजवे ठीक-ठाक चल रहा था। कई बरसात झेल चुका यह पुल 24 सितम्बर 2023 का बरसात नहीं झेल सका और पुल का कई पीलर भरभरा कर धस गया। इस पुल के टुटने के पिछे का

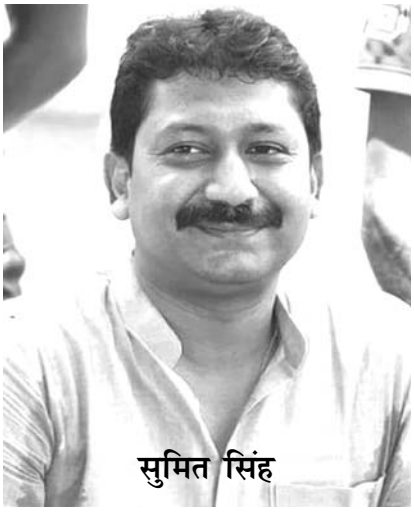

सुमित सिंह

कारण निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा और नियमों को ताक पर रख कर बालू का उठाव होना रहा है। स्थानीय ग्रामिणों ने बालू का बेतरतीव ठंग से उठाव का बिरोध भी किया था पर इस मामले में कई ग्रामिणों को जेल तक की हवा खानी पड़ी थी जिसके फलस्वरूप स्थानीय नागरिक शांत हो गये और बालू का उठाव होता रहा। पुल के समीप गडढ़े बन जाने के कारण 2023 का बरसात पुल सहन नहीं कर सका और पुल धस गया।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनो-चुरहेत के बीच बने पुल के लिए स्थानीय नागरिक बिरोध किये थे। दर्जनों घाटों पर स्थानीय नागरिक बिरोध कर चुके हैं पर पता नहीं हर आंदोलन को प्रशासन और बालू माफियाओं के द्वारा कुचलने का काम किया जाता रहा है। वैसे बिहार में इन दिनों बालू माफिया और दारू माफिया का नाम कुछ ज्यादा चलन में देखने को मिल रहा है। शराब बंदी और बालू बंदी के पूर्व बालू-माफिया और दारू माफिया जैसे शब्द चलन में नहीं हुआ करता था। नितिश कुमार के सुशासन राज में एक और नाम प्रचलन में है और वह है कमीशनखोरी। हमें यह कहने में कहीं से अतिश्योक्ति नहीं होगी की बालू माफिया और कमीशन खोरी का भेंट जमुई के कई पुल-पुलिया और सड़क चढ़ गया है और जल्द ही सरकार इस पर रोक लगाने की पहल नहीं करती है तो जमुई के कई घाटों में बने पुल और सड़क टूट कर नागरिकों के लिए काल बनकर सामने आएगा। पता नहीं स्थानीय प्रशासन से लेकर विधायक-मंत्री और जनप्रतिनिधि तक का वरदहस्त इन बालू माफियाओं को कैसे प्राप्त हो जाता है जिस कारण से चार फीट बालू उठाव के जगह पर 40 फीट बालू का उठाव कर लिया जाता है और वह भी प्रशासन के नाक के नीचे। हजारों ट्रक बालू का उठाव प्रतिदिन होने के कारण नीतिश राज के विकास का प्रयाय बन चुका पुल-पुलिया और सड़क उजड़ते जा रहा है। जमुई-गिधौर रोड से लेकर चुरहेत से विजैया जैसे दर्जनो रोड आज कबार होने के कगार पर पहुँच गया है। जमुई-सोनो के बीच बने रोड में ही नरियाना और मांगोबंदर पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई वर्षो से भारी वाहनों का परिचालन बंद पड़ा हुआ है। जमुई से चाकाई के बीच ही देख लेंगे तो दर्जनों बालू का पहाड़ देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी सैंकड़ों जमुई बासियों का मौत चोरी के बालू ढुलाई करते अनियंत्रित ट्रैक्टर चालकों के ठोकर के कारण और रोड में गिरे बालू में फिसलने के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री जी विकास के जो इमारत जमुई में आपके शासनकाल में लिखे गये थे वे सारे इमारत एक-एक कर ध्वस्त होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये सारे पुल-पुलिया और सड़क आपके शासनकाल में ही बना और आपके शासनकाल में ही ध्वस्त होते देखा जा सकता है।

यह अच्छी बात है कि बिहार के मुखिया नितिश कुमार चुरहेत पुल के टुटने के बाद अपने प्रजा का सुध लेने सोनो-चुरहेत के बीच बने क्षतिग्रस्त पुल को देखने 27 सितम्बर को पहुँचे और एक माह के अन्दर पुल बनाने का आश्वासन दे दिया पर क्या इंजिनियर मुख्यमंत्री जी सोनो-जमुई के बीच बने दो क्षतिग्रस्त पुल को भी आपको देखना चाहिए था कि आखिरकार इंजिनियर के किस गलती के कारण नरियाना और मांगोबंदर पुल पर भारी वाहनों के आवागमन बंद किया गया है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन चुरहेत-सोनो पुल ध्वस्त हुआ था उसी दिन खैरा को जन्मस्थान से जोड़ने वाला एक और पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। मुख्यमंत्री जी आप करीब आधा दर्जन बार जन्मस्थान आ चुके हैं और भगवान महावीर के जन्मस्थली से आपका पुराना नाता रहा है पर जमुई आने के वावजूद आपने खैरा-जन्मस्थान को जोड़ने वाला गोदहा पुल को देखने नहीं पहुँचे। मुख्यमंत्री जी यह पुल-पुलिया और सड़क का निर्माण जनता के टेक्स के पैसे से बना है इसे याद रखियेगा। बालू माफियागिरी, शराबमाफियागिरी, कमीशनखोरी और प्रशासन की मनमानी का हिसाब कहीं जनता ने मांगना शुरू कर दिया तो आज तक जिस जनता ने आपको सर-ऑखों पर बैठा रखा है वही जनता को ताकत का अंदाजा दिलाने में देर नहीं करेगी। हमने चुरहेत समेत करीब दर्जन भर पंचायतों की जनता का आक्रोस देखा है इस बुनियाद पर इतना

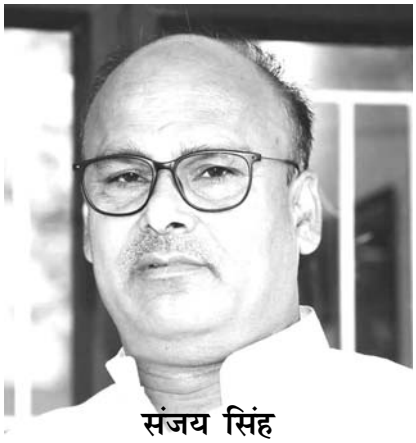

संजय सिंह

लिखने की हिम्मत आ रही है हमें, नहीं तो कौन नहीं जानता है कि सच बोलने की सजा मनीष कष्यप जैसे पत्रकार झेल रहे हैं। अच्छी बात है कि पुल टुटने के बाद मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख कर सूचना देने का काम जदयू नेता संजय सिंह ने किया था और मुख्यमंत्री जी को बुलाने का काम चकाई के निर्दलीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह ने किया था पर पुल टुटने की जिम्मेवारी भी तो चकाई विधायक और मंत्री सुमित सिंह को ही लेनी चाहिए थी पर पुल टुटने के बाद तो मानो एक मयान से दो तलवारें निकल कर एक-दूसरे पर खिंच लिया गया हो। मुख्यमंत्री को बुलाने का श्रेय लेने के लिए पूर्व एमएलसी संजय सिंह और मंत्री सुमित सिंह आमने-सामने देखे गये। दोनो जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं। सुमित मुख्यमंत्री के करीबी तो संजय सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी रहे हैं। सुमित संजय सिंह को फतींगा, बैल जैसे उपाधी से अलंकृत किये तो संजय सिंह मंत्री सुमित सिंह को लूच्चा जैसे शब्दों से पुरस्कृत करने का काम किया है। यही श्रेय लेने का काम तब होता जब क्षेत्र की जनता बालू उठाव के विरोध स्वरूप आंदोलन कर रहे थे और पुलिस उस आंदोलनकारी को कुचलने का काम कर रही थी।

मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और जिला प्रशासन जी अभी भी देर नहीं हुआ है इन बालू माफियाओं, दारू माफियाओं और कमीशनखोरों से बचा कर जमुई के दर्जनो पुल-पुलिया और सड़क को बचा लिजिए क्योंकि यह सारे विकास के दजवाजे आपके शासनकाल के ही उपज हैं और आप सक्षम हैं इसे रोकने में जरूरत है निर्भिकता के साथ पूरे मनोयोग से इन माफियाओं के फन कुचलने की। ●

आनंद बाजपेयी जन्मजात धोखेबाज

● प्रो० रामजीवन साहु

आनंद बाजपेयी जन्मजात धोखेबाज का जन्म लखीसराय जिला के कजरा गांव में हुआ है। इनके पिताजी का नाम श्री जयराम साहु और माताजी का नाम स्मृतिशेष रजिया देवी है।

आनंद बाजपेयी को जन्मजात धोखेबाज इसलिए कहा गया है कि उनका उपनाम बाजपेयी है जो मुख्य रूप से ब्राह्मण ही इस उपनाम का प्रयोग करते हैं परंतु ये ब्राह्मण नहीं बल्कि यह कानू हैं। उनके क्रियाकलाप के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नौकरी में आने के बाद असामाजिक लोगों से अधिक संपर्क बढ़ गया। जमुई में जब कार्यरत हुए तो इन्हें लगा कि अपनी शक्ति और अधिक बढ़ानी चाहिए इसके लिए नक्सली प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए वे जमुई नगर परिषद अंतर्गत हरनाहा वार्ड संख्या 8 में इन्होंने एक जमीन खरीदे। इसी बीच यहाँ के कानू समाज ने बताये कि जमुई नगर परिषद अंतर्गत जयशंकर नगर वार्ड संख्या 24 में छात्रावास का जमीन है। फिर क्या था उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा! उन्होंने अपना पैसा खर्च कर वह भवन तैयार किये। ये भवन बनवाये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मुख्य द्वार के किवाड़ के एक पल्लाघ पर उनके माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती रजिया देवी और किवाड़ के दूसरे पल्ला पर उनके पिताजी का नाम श्री जयराम साहु लिखा हुआ है। जमुई कानू समाज ने लगभग सवा करोड रुपए खर्च किया परंतु किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। वे कम से कम डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, तभी तो उनके माता-पिता जी का नाम लिखा हुआ है। एक बार सिटी चैनल के पत्रकार ने इनके द्वारा प्रशिक्षण देते हुए फोटो भी लिया है और प्रसारित किया गया है। ये जमुई कानू समाज को तीन गुटों में विभाजित कर रखे हैं।

दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के पावन जन्मदिन

पर आनंद बाजपेयी अपना खेल शुरू कर दिए। अपने पिताजी जो डंडा के सहारे चलते हैं उस विकलांग व्यक्ति को कजरा से चार पहिए वाली गाड़ी से लाकर इस भवन में प्रवेश करवा दिए। उनको लगा स्वर्ग के द्वार आज के बाद 100 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा इसलिए पिताजी को ले आए। श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता जो राजद के व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष और जद(यू) जमुई जिला के अत्यंत पिछड़ी जाति के जिला अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार साह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। यह कार्यक्रम इनके सहमति के बिना बना दिया गया। सनातन धर्म के अनुसार पितृ पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, फिर भी इन्होंने यह नीति अपनाई कि चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तेते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हड़बड़ बियाह कनपटी सिंदूर। मुझे लगता है कि अगर वे दोनों व्यक्ति आते तो मेरे विकलांग पिताजी को लोग यह सोचकर प्रवेश नहीं करने देते की विकलांग व्यक्ति को पहला दिन प्रवेश नहीं करना चाहिए। इनका प्रवेश करना अशुभ होगा। शायद इसीलिए यह सोचा गया होगा कि ऐसा व्यक्ति को अशुभ दिन में प्रवेश कराना अशुभ नहीं होगा।

अत: कान्य कुब्ज वैश्य हलुवाई छात्रावास-सह- धर्मशाला समिति जमुई इसे असंवैधानिक मानता है कि और इसकी निंदा घोर निंदा करती है। साथ हीं कानून के जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

कजरा पहले तो मुंगेर जिला में था वहां भी 50 वर्ष पूर्व कानू समाज का भवन है उसे भवन के विकास के लिए आनंद बाजपेयी क्यों नहीं सहयोग किया। वहाँ इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता इसीलिए उनको छोड़ दिए। जमुई जिला में उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगी इसलिए यहां उन्होंने मनमाना खर्च किए लेकिन आश्चर्य की बात है यह भी है कि इस भवन में अभी भी कई खिड़कियां लगनी बाकी है फिर भी प्रवेश कर गए। तुलसीदास जी ने भी ठीक ही कहे हैं कि ''सुर नर मुनि की यही सब रीति। स्वारथ लागी कर ही प्रीति।।''●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

आई.जी. विकास वैभव की एक मुहिम

लेट्स इंस्पायर बिहार

युवाओं को करे प्रेरित

● राकेश रौशन

बिहार प्रशासन में एक ऐसा कर्मवीर योद्धा हैं, जो अपने मेहनत और बुद्धि के बदौलत आज के युवाओं को नई दिशा में ले जानें को लेकर संकल्पित है। ये वो योद्धा है जो ठान लेता है, उसे पुरा कर के हीं दम लेता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2003 बैच के आइपीएस अधिकारी विकास वैभव की। जो आज के युवाओ का प्रेरणास्रोत और उसके दिलों की धड़कन हैं। वैभव को सबसे लोकप्रिय पुलिस में से एक माना जाता है। बिहार में अधिकारी और जनता द्वारा इसकी अत्यधिक सराहना की जाती है। वह अपने पेशेवर पुलिसिंग और सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए महान हैं। इसी महानता को लेकर उन्हें आईआईटी कानपुर द्वारा प्रतिष्ठित सत्येंद्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अडिग पेशेवर निष्ठा के लिए 2019 में दुबे मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। यह वही विकास वैभव हैं जिनके खौफ से बड़े-बड़े दुर्दान्त अपराधी की पैंट गीली हो जाया करती थी। आज वही विकास वैभव युवको को सही दिशा में लाने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं।

'लेट्स इंस्पायर बिहार' अभियान के तहत आइपीएस विकास वैभव रविवार को हिसुआ स्थित सम्राट अशोक भवन पहुंचे। जहाँ आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदोपरान्त आईजी विकाश वैभव ने युवाओं को

संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को प्रेरित करें और विकसित बिहार बनाएं। हम सबों को आत्म चिंतन कर अपने पूर्वर्जों और धरोहरों के बारे में सोचने की जरूरत है। युवा शक्ति अपनी उर्जा को संघर्ष में नहीं बल्कि सेवा और सहयोग में लगाएं। जाति-धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे को सहयोग और जागरूक कर के हीं हम समाज और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा, समता और उद्यमिता के लिए बिहार को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है, तभी अपनी शक्ति का एहसास होगा।

गृह विभाग के विशेष सचिव सह आइजी विकास वैभव ने रविवार को हिसुआ के सम्राट अशोक भवन में 'लेट्स इंस्पायर बिहार' मुहिम की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य अपने बिहार के गौरव के बारे में नई पीढ़ी को बताना है। उन्हें अपने क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को बताते हुए उसकी तरफ अग्रसर करना है। बिहार के प्राचीन धरोहर को विकसित कर बिहार से जुड़ने को लेकर विकास वैभव ने संकल्प लिया तथा वहाँ मौजूद लोगों को भी संकल्प दिलाया। उन्होंने बदलते बिहार की कल्पना को धरातल पर उतारने व संवारने के लिए युवाओं से आह्वान किया।

विकास वैभव ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो प्राचीन इतिहास रचे थे। उसे आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक चिंतन के साथ साथ अच्छे कार्य में योगदान नहीं होगा, तब तक हम अपने बिहार को बदलते बिहार में तब्दील नहीं कर पायेंगे। इसलिए सपना को साकार करने के लिए आइये मिलकर प्रेरित करें बिहार... के सोच को अपनाना होगा। तभी हम सभी बिहार के गौरवशाली प्राचीन इतिहास को बचाते हुए विकसित बिहार बना सकेंगे। आइजी ने युवा शक्ति से आह्वान करते हुए कहा कि 17 वीं शताब्दी में तकनीकी की कमी थी फिर भी बिहार विकसित था, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में संचार तंत्र के अलावे पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है फिर भी बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है।

विकास वैभव का गर्मजोशी के साथ स्वागत हिसुआ वासियों ने अंग वस्त्र, फूल, माला, बुके व स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट कन्या इण्टर विद्यालय के छात्रा श्वेता सत्यार्थी, डौली कुमारी, अस्मिता आनंद, तन्मय राज द्वारा प्रस्तुत संगीत पर उपस्थित लोग झूम उठे। संगीत कार्यक्रम के दौरान संगीत शिक्षिका सह निर्देशिका निशा कुमारी भी मौजूद थी। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक विश्वजीत कुमार,तथा सहयोगी सौरभ कुमार, तरूण कुमार, दीपक प्रिंस,लव कुमार भास्कर, मोनु कुमार

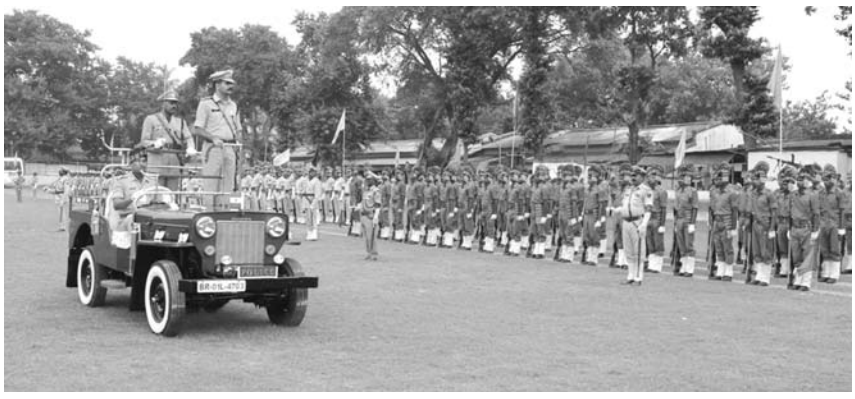

रौशन कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

☞ **कौन हैं विकास वैभव :-** बिहार का वैभव हैं विकास वैभव। भारतीय पुलिस सेवा में 2003 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड, बिहार सरकार में सेवारत है। एनआईटी, कानपुर के पूर्व छात्र (1997-2001) रह चुके हैं। वैभव को सबसे लोकप्रिय पुलिस में से एक माना जाता है। बिहार में अधिकारी और जनता द्वारा इसकी अत्यधिक सराहना की जाती है। वह अपनी पेशेवर पुलिसिंग और सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए महान हैं। वह अपने लिए प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन में अटल सत्यनिष्ठा और दृढ़ ईमानदारी व्यावसायिकता और कानून का उचित पालन, बिना किसी डर या पक्षपात के। निरंतर सर्वोच्च पारदर्शिता के साथ सत्य और न्याय के लोकाचार को बनाए रखने के लिए काम करना सार्वजनिक हित के लिए कई अवसरों पर असाधारण धैर्य और उत्साह की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी खिंचाव या दबाव से विचलित हुए बिना, वह हमेशा इसे बनाए रखने में सफल रहा है के कुछ वर्गों द्वारा दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास के खिलाफ साहसी रुख अपनाएं प्रभावशाली वर्ग। बिहार में बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा काफी प्रिय और व्यापक रूप से सम्मानित वही, उन्हें अक्सर बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, भले ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो कई मौकों पर सच्चाई के साथ खड़े रहे. फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति बरकरार रखी है संयम और निस्वार्थ भाव से बड़े पैमाने पर समाज के हित में योगदान दे रहे हैं सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन. उन्हें आईआईटी कानपुर द्वारा प्रतिष्ठित सत्येन्द्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी अडिग पेशेवर निष्ठा के लिए 2019 में दुबे मेमोरियल अवार्ड।

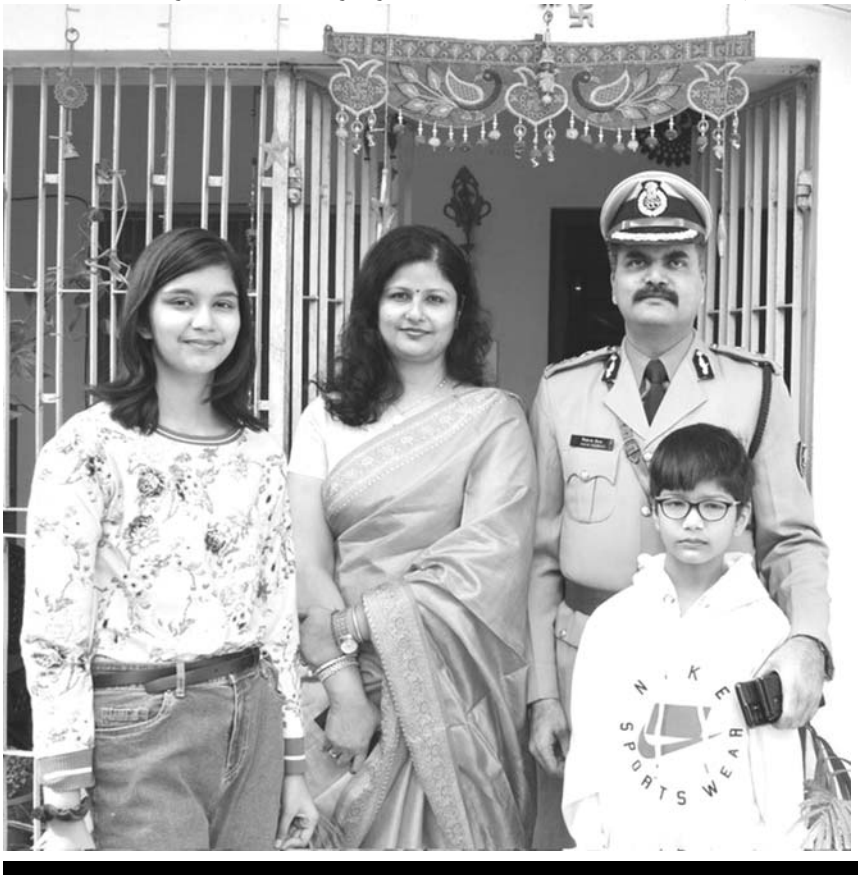

बिहार के बेगुसराय जिले के बिहट के रहने वाले वैभव का जन्म 21 नवंबर, 1979 को हुआ था दरभंगा. उनके पिता श्री..बीआईटी, सिंदरी के केमिकल इंजीनियर जगदीश सिंह ने साथ काम किया 1980 से 2013 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। उनकी माँ, श्रीमती रंजना सिंह, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से शिक्षण में स्नातक की डिग्री के साथ एक गृहिणी हैं वैभव की प्रारंभिक शिक्षा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से प्राप्त की केन्द्रीय विद्यालय, गुवाहाटी (प्रथम, 1985 से 1986), सेंट सहित भारत भर में विभिन्न स्कूल। पॉल स्कूल, बेगुसराय (दूसरी से आठवीं, 1986 से 1993), केन्द्रीय विद्यालय, बैरागढ़, भोपाल (9वीं, 1993 से 1994), केन्द्रीय विद्यालय, नोएडा (10वीं, 1994 से 1995) और सरदार पटेल विद्यालय, न्यू दिल्ली (1वीं से

12वीं, 1995 से 1997)। उनकी छोटी बहन जयात्री सिंह नोएडा में बैंकर के पद पर कार्यरत हैं और उनके छोटे भाई विराज सिंह 2015 में भारतीय रेलवे खाता सेवा में शामिल हुए। 15 उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त गृहिणी रूपांगी वैभव से शादी की 17 तारीख को बिहार के समस्तीपुर जिले के केवटा की रहने वालीं पटना वीमेंस कॉलेज से फरवरी, 2005. उनके परिवार में बेटी प्रत्यक्षा वैभव (19 जुलाई, 2007) शामिल हैं और बेटा याज्ञवल्क्य वैभव (16 जुलाई, 2012), दोनों पटना में पढ़ रहे हैं। एलटी, कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद (1997 से 2001), वैभव समाज की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ 2003 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उन्होंने उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, सदर के रूप में कार्य किया है। औरंगाबाद (18 सितंबर, 2005 से 5 दिसंबर, 2005), उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, दानापुर, पटना (5 दिसंबर, 2005 से 1 मार्च, 2006), सिटी एसपी, पटना (1 मार्च, 2006 से) 23 दिसंबर, 2006), एसपी, बगहा, पश्चिम चंपारण (2 दिसंबर, 2006 से 2 अगस्त, 2008), एसपी, रोहतास (4 अगस्त, 2008 से 13 फरवरी, 201), एसएसपी, दरभंगा (15 फरवरी, 2011) 28 नवंबर, 2011 तक), एसपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नई दिल्ली (5 दिसंबर, 2011 तक) 31 मई, 2015), एसएसपी, पटना (23 जून, 2015 से 28 अगस्त, 2015 और 12 सितंबर, 2015 से) 3 दिसंबर, 2015), एसपी, पूर्णिया (29 अगस्त, 2015 से 12 सितंबर, 2015), एआईजी, प्रशिक्षण, पुलिस हकर्स, बिहार (4 दिसंबर, 2015 से 30 अप्रैल, 2017), डीआइजी, भागलपुर (2 मई, 2017 से 3 मई) जनवरी, 2020), डीआइजी, मुंगेर (2 अगस्त, 2017 से 8 मार्च, 2018), डीआइजी, एटीएस, बिहार (6 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी, 2021 तक) और गृह विभाग, सरकार में विशेष सचिव बिहार (1 जनवरी 2021 से 19 अक्टूबर 2022)। आईजी, होम गार्ड (20 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023) वर्तमान बिहार राज्य योजना बोर्ड के सलाहकार के रूप में पोस्टिंग (17 जुलाई 2023 से अब तक)। वैभव को उन सभी क्षेत्रों में एक कठिन कार्य मास्टर के रूप में जाना जाता है जहां उन्हें भीड़ के साथ तैनात किया गया है अक्सर उनके स्थानांतरण पर अनायास ही भड़क उठती थी। एक युवा एसपी के रूप में उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है कुख्यात ख्याति अर्जित कर चुके बिहार के बगहा पुलिस जिले में अपराध पर नियंत्रण दशकों से 'मिनी-चंबल' के रूप में और रोहतास जिले में माओवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए भी, जहां उन्होंने प्रभावी समुदाय उन्मुख पुलिसिंग के साथ-साथ पुलिस संचालन का संचालन किया ऐतिहासिक रोहतास किले की स्वतंत्रता वस्तुतः बहाल हो गई, जो तब की चपेट में था माओवादियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर भारतीय तिरंगे को फहराया स्वतंत्रता, 26 जनवरी, 2009 को। उन्होंने राष्ट्रीय जांच में भी काम किया है एजेंसी (एनआईए), जहां उन्होंने भारतीयों की गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जांच की कुख्यात

यासीन भटकल और 2013 के बोधगया विस्फोट सहित मुजाहिदीन। झड़पें शुरुआती दिनों से ही ऊंचे और शक्तिशाली लोग वैभव के करियर का हिस्सा रहे हैं और उन्हें पथभ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए याद किया जाता है और जाना जाता है कानून का गलत पक्ष. बिना किसी डर या पक्षपात के पथभ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई सबसे अधिक थी उन्हें हर जगह बड़े पैमाने पर आम लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने जनता की शिकायतों के लिए चौबीसों घंटे सेवा की है और हमेशा उपलब्ध रहे हैं जिलों के एस.पी. भागलपुर और मुंगेर रेंज के डीआइजी के रूप में उन्होंने नियमित रूप से संचालन किया जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जनता दरबार और पुलिस-पब्लिक बैठकें। 16 बगहा की जनता उनके कार्यों के प्रति आश्चर्यजनक रूप से समर्पित और सम्मानित है समरकोला गांव में, जो कभी अपराध के लिए कुख्यात था, वर्षों बाद उनके नाम पर एक चौराहा बनाया गया सितंबर, 2017, जिले में शांति स्थापित करने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए। अपने पेशेवर काम के अलावा, वैभव एक शौकीन यात्री हैं और उन्होंने 200 से अधिक यात्राएँ की हैं विरासत स्थल और अपने प्रसिद्ध ब्लॉग पर इतिहास के उपेक्षित पहलुओं पर ब्लॉगिंग करते रहे हैं जिसका शीर्षक 'खामोश पन्ने' है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फॉलो किए जाने के कारण उन्होंने अनुभव भी साझा किए हैं अपने ब्लॉग 'कॉप इन बिहार' पर फील्ड पुलिसिंग करते हैं और नियमित रूप से स्कूलों में युवाओं को संबोधित करते हैं कॉलेज उन्हें बेहतर भविष्य के लिए समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।ष मार्च, 2021 में, वैभव ने ष्लेट्स इंस्पायर बिहारष लॉन्च किया, जो एक स्वैच्छिक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पहल जिसका उद्देश्य शिक्षा के विषयों को बढ़ावा देना और उन पर काम करना है, समतावाद और उद्यमिता की स्थापना में योगदान देने के लिए बिहार का बेहतर भविष्य. इसका लक्ष्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है, जिनके पास... स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान देने का विकल्प चुना गया। प्रेरणा बिहार की शानदार विरासत से निकलती है, जो सबसे प्राचीन काल से है ने तत्कालीन समकालीन विश्व में अपनी छाप छोड़ी थी, इसके पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है पहल। जैसा कि कोई गर्व से बिहार के अतीत को याद करता है, ज्ञान की भूमि के रूप में, सेना की भूमि के रूप में समतावादी राजनीतिक परंपराओं के साथ और उद्यमिता की भूमि के रूप में, पहल हो सकती है वर्तमान पीढ़ी को उन कारणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है जो कभी थे इतना गौरव दिलाया और साथ ही पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर भी मंथन किया भूमि के प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया में समय, जिसने एक बार पूरे देश का नेतृत्व किया था इसकी सीमाएँ आज की तुलना में अधिक व्यापक हैं। इस प्रकार यह पहल व्यापक सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण से सीखने की आवश्यकता को बढ़ावा देती है ऐसे महान पूर्वजों का, जो ऐसी दूरदर्शिता और ऊर्जा के साथ तालमेल के कारण ही ऐसा कर सके ऐसे समय में बहुत कुछ हासिल करें जब सड़क, साधन जैसे संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। परिवहन और संचार निराशाजनक थे और प्रौद्योगिकी अभी भी उतनी विकसित नहीं थी आज का दिन। ऐसी समझ के साथ ही भविष्य के निर्माण में योगदान देने का उत्साह पैदा होता है भीतर से उभरेगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि संचयी ऊर्जा हो वांछित परिणामों के लिए उचित दिशा में निर्देशित किया गया। ●

नालंदा और नवादा जिला साइबर फ्रॉड मामले में बन रहा अव्वल

● मनीष कमलिया

साइबर अपराध के मामले में झारखंड के जामताड़ा का पूरे देश में इतना नाम है कि इसपर वेब सीरीज तक बन चुकी है।सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जिले नालन्दा भी साइबर अपराध का जन्मदाता कहा जाय तो कोई गलत नही होगा।एक समय था जब नालन्दा विश्वविद्यालय में दस हजार से अधिक छात्र विदेशों से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बिहार का नाम किसी क्षेत्र के लिए आता है तो नालन्दा का नाम अवश्य जुड़ जाता है।क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जिला नालन्दा होने के साथ साथ बिहार के सभी जिलों से सबसे ज्यादा विकास भी नालन्दा का हुआ है।दूसरे तरफ अगर हम साइबर अपराध का आंकड़ा और इस धंधे में जुड़े लोग और गावँ की गणना करें तो नालन्दा के साथ सीमावर्ती जिला नवादा भी साइबर अपराध में अव्वल है। नवादा जिला का अधिकाशत: गावँ में यह धंधा विभिन्न तरीकों से चलाए जा रहे हैं। जिस गति से यह धंधा बढ़ रहा है उस गति से न तो पुलिस का दविश है और न ही ठोस कार्रवाई। यहां साइबर अपराधी भोले-भाले लोगों को फंसाने को लेकर तरह- तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पैसे के लेन-देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही से साइबर अपराधी आपके खाते से रुपये उड़ा लेते है। हालांकि इसे रोकने के लिए जिले में साइबर थाना नौ जून 2023 को स्थापित किया गया है। अब तक लगभग 45 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये जा चुके हैं परंतु लगभग मामला बैंक खाते से अवैध तरीके से निकालने को लेकर आया है। क्योंकि साइबर अपराध दूसरे राज्यों को निशाना बनाते है।

★ अपनी गाढ़ी कमाई करना चाहते है सुरक्षित तो जान लें ये बातें, वराना पछतायेंगे आप :-

☞ **व्यवसायिक कंपनियों से डाटा खरीदकर :-** नामचीन निजी व्यवसायिक कंपनियों से डाटा को खरीद कर टेलीकॉम कंपनियों का कस्टमर केयर बन बात करता है और भोले- भाले लोगों की मानसिकता को समझने के उपरांत उसे तरह-तरह के अत्यंत लुभावने ऑफर जैसे गाड़ी रुपए महंगे मोबाइल आदि लालच देकर अपने जाल में फंसाता है। जिससे आमतौर पर लोग इसका शिकार हो जाते हैं।

☞ **नामचीन कम्पनी का फेंक डोमिन खरीदकर ठगने का खेल बदस्तूर जारी :-** एक फेक कंपनी खोलकर जीएसटी, पैन कार्ड, कर्मचारियों का आधार, आईडी कार्ड आदि लेकर सभी प्रक्रिया को पूरा कर डोमेन एवं होस्टिंग खरीद कर आईटी डेवलपर्स से वेबसाइट डिजाइन कर एक कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करता है। जो विभिन्न कंपनियों का हो सकता है। इसकी शाखा बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होती है।

☞ **टॉवर, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप के नाम पर ठगी :-** सबसे पहले साइबर अपराधी लोगों का डाटा कलेक्ट करता है। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करता है। वेबसाइट के माध्यम से सोशल साइट पर विज्ञापन डालता है, जो लोगों के एंड्रॉयड पर आसानी से दिखता है। लोग लुभावने विज्ञापन देखकर आकर्षित होते हुए लिंक खोलते हैं। लिंक ओपन होते ही लोगों को नाम, पता सहित अन्य डाटा फिल करने को कहा जाता है। डाटा फिल कर सबमिट करते ही लोगों का पूरा डिटेल साइबर अपराधियों तक पहुंच जाता है।

☞ **अच्छी कमाई का प्रलोभन :-** डाटा प्राप्त होते ही साइबर अपराधी लोगों को फोन कॉल के जरिए टॉवर, गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप लगाने की प्रक्रिया को बताते हैं। इसमें महीने में अच्छी कमाई का प्रलोभन देते हैं। जो लोग तैयार हो जाते हैं, इसके बाद लोगों से उनकी ओरिजनल डोकोमेंट व्हाट्सएप के जरिये मांग जाता है। उसी उपरांत उनको फर्जी तरीके से बनाए कंपनी की ओर से अप्रूवल लेटर दिया जाता है। फिर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10,500 से 20,500 रुपए तक वसूलते हैं। इसके बाद एनओसी, आईटीआर, एग्रीमेंट, ट्रांसपोरेशन चार्ज आदि के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं।

☞ **लोन के नाम पर ठगी :-** साइबर अपराधी लोगों के मोबाइल पर विभिन्न कंपनियों द्वारा लोन दिए जाने का मैसेज ईमेल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप व फेसबुक मैसेंजर के जरिए भेजते हैं। फिर लोगों को कॉल कर लोन देने से संबंधित बात करते हैं। लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें लोन के बारे में समझाते हैं। इच्छुक व्यक्ति से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य डिटेल व्हाट्सएप के जरिए मंगवाते हैं। तत्पश्चात, उनसे रजिस्ट्रेशन व प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में एक तय रकम की मांग करते हैं। लोगों को इस तरह से समझाया जाता है कि प्रोसेसिंग चार्ज डालते ही उनके खाते में लोन की रकम क्रेडिट हो जाएगा। ग्राहक उनके झांसे में आकर मांगे गए रकम को साइबर अपराधी द्वारा दिए खाता नंबर अथवा फोन पे नंबर पर भेज देते हैं। इस तरह से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं।

पैनल का भी होता है इस्तेमाल :- मैसेज भेजने के काम के लिए मैसेज पैनल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक साथ कई लोगों के पास मैसेज भेजने का काम करता है। मैसेज ऐसे

होता है कि एसबीआई, पीएनबी, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप जैसे तमाम कंपनियों के नाम से भेजा जाता है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए और वे आसानी से जाल में फंस जाए।

☞ **साइबर क्राइम के लिए सिम कार्ड का उपयोग :-** अपराधी क्राइम के लिए सिम कार्ड भी खरीदते हैं। इसके लिए एक अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो धोखे से किसी और के कागजात को लेकर एक्टिव कर लिया जाता है और अपराधियों को ऊंचे कीमतों पर बेच दिया जाता है। इसके लिए कंपनियों के हिसाब से 1800 रुपये तक ले लिए जाते हैं।ऐसे कुछ सिम लोकल में और कुछ महाराष्ट्र एवं बंगाल से अधिक मात्रा में एवं आसानी से मिल जाती है।

☞ **बैंक खाता खोलवाने की प्रक्रिया :-** साइबर अपराधी पैसे के लेन-देन के लिए एक बैंक खाता भी रखते हैं। खाता खोलने के लिए आधार एवं पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी गरीब को रुपये-पैसे देकर तैयार करते हैं और बैंक में खाता खुलवाकर इस काम को अंजाम देते हैं।

☞ **साइबर अपराध प्रभावित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की कट रही चांदी :-** जिले के साइबर अपराध प्रभावित थाना क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की चांदी कट रही है। पिछले दस बर्षो का रिकार्ड के अनुसार विभिन्न थाने में पदस्थापित थानाध्यक्षों एवं एसडीपीओ के सम्पति की जांच आर्थिक अपराध इकाई से किया जाय तो ऐसे दर्जनों पुलिस अधिकारी जांच के घेरे में आ सकते हैं लेकिन विभाग या सरकार ऐसा करने से भी गुरेज करेगी क्योंकि जांच होगी तो इसका दायरा स्वत: बढ़ता चला जायेगा और सरकार एवं विभाग की किरकिरी भी हो जाएगी। बहरहाल, नवादा जिले में दूसरे प्रदेशों से पुलिस कब किस गावँ में जांच करने पहुंच जाएगी ऐसा कुछ नही कहा जा सकता है।●

शिक्षिका पुत्री बनी पटना यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट

● मिथिलेश कुमार

जिले के प्रसिद्ध होम्यो चिकित्सा डॉक्टर सुधीर कुमार की पुत्री सौम्या सुरभि पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक परीक्षा में टॉप कर गोल्ड मेडलिस्ट बनी। गोल्ड मेडलिस्ट बनने पर सौम्या सुरभि को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सौम्या सुरभि की माता संगीता सिन्हा राजकीय इंटर विद्यालय नवादा में गृहविज्ञान की शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 107 वां स्थापना दिवस पर यूनिवर्सिटी प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जहां सौम्या सुरभि को पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रो. रासबिहारी सिंह नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति के. सी. सिन्हा की उपस्थिति में प्रमाण-पत्र के साथ गोल्ड मेडल भी दिया गया। इस मौके पर इसके मम्मी-पापा भी उपस्थित थे। सौम्या सुरभि ने पटना यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विषय की छात्रा थी। डा सुधीर कुमार के आनंदपूरा रोड के अपना कॉलोनी स्थित आवास 'सुधीता' पहुंचकर कुशवाहा सेवा समिति के संरक्षक बसंत प्रसाद, उपाध्यक्ष यमुना प्रसाद, समाजसेवी राजेशवर प्रसाद राजेश, डा राजकिशोर प्रसाद, पूर्व मुखिया राजेन्द्र प्रसाद, सतेन्द्र प्रसाद उर्फ साहा जी, डा मनोज कुमार, सुधीर कुमार, रंजन कपूर, डा.विनीता प्रिया आदि ने माता- पिता को मिठाई खिलाकर पुत्री की कामयाबी के लिए बधाई देते हुए सौम्या सुरभि को जीवन में हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए शुभकामनाएं दिया। साथ ही इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि सौम्या सुरभि ने न सिर्फ परिवार बल्कि जिले का मन भी बढ़ाया है।

☞ **क्या कहती है सौम्या सुरभि :-** गोल्ड मेडल पाकर मैं काफी खुशी महसूस कर रही हूं। मुझे यकीन हो गया है कि अगर पूरी लगन के साथ परिश्रम किया जाय तो न सिर्फ बुलंदियों को छुआ जा सकता है। बल्कि इससे परिवार और समाज के सदस्यों को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। मैं अपनी सफलता का श्रेय माता- पिता को देना चाहती हूं। ●

नवादा जिले की सांस्कृतिक विरासत

● राजीव नयन

मागधीय संस्कृति और सभ्यता का उद्भव और विस्तार का बोध कराता है, नवादा जिले की पहाड़ियाँ और विकसित क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के साथ यहाँ, का धरातल उच्च पाषाण युग 12020 वर्ष पूर्व आर्य एवं श्याम वर्ण का विभिन्न क्षेत्रों में सौर धर्म, शाक्त, धर्म, शैव धर्म तथा वैष्णव धर्म के विभिन्न धर्मावलंबियों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर अमिट छाप छोड़ा हैं, पुराणों और वेदों तथा इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण संलेख है, आदि काल में मगध में देव, दैत्य, दानव, भल्ल, वसु, सिद्ध मरूद गण, पिशाच, यक्ष, नाग, मानव, किरात, आदि का निवास था। देव संस्कृति के पोषक देव, गंधर्व, यक्ष, मानव और दैत्य संस्कृति का पोषक दैत्य, दानव, पिशाच, राक्षस थे, पुरातन काल में 19 जातियाँ थी-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण को मग, मगध, मानष तथा मंदग कहा जाता था, राजा पृथु ने ब्रहमेष्टी यज्ञ से उत्पन्न मागध ने मगध साम्राज्य की नींव डाली और गया में अपनी राजधानी बनाया था, बाद में राजा वसु ने मगध का राजधानी राजगीर बना कर प्रजा और अपने क्षेत्र का विकास किया, छठे मन्वन्तर में चाक्षुस मनु की पत्नी वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ से 10 पुत्रों में कुत्स ने अपने माता नडवला के नाम पर नगर बसाया, जिसे नौआ बाद आधुनिक काल में नवादा के नाम से ख्याति प्राप्त है। राजा कुत्स ने कुत्स नगर की स्थापना की जिसे कौवाकोल के नाम से जाना जाता है, नवादा जिले के 12 विभिन्न पहाड़ियों पर भिन्न-भिन्न राजाओं द्वारा स्थापित धरोहर है, धुर्वा शाही पर्वत 2202 फीट ऊँचाई, महावर पर्वत 1832 फीट ऊँचाई, मुरगरा पर्वत 1340 फीट, थारी पहाड़ी 1189 फीट, गीधा पहाड़ी 938 फीट, चरकही पहाड़ी 1010 फीट, श्रृंगी पहाड़ी 1850 फीट, इको हिल 20 फिर ऊँची और 20 वर्गफीट क्षेत्र में फैला है का पत्थर मानवीय आवाज प्रदर्शित करता है। माहवर पर्वत की 1832 फीट ऊँचाई का ककोलत श्रृंखला के 160 फीट की ऊँचाई से ठंडे पानी का जलप्रपात होते हैं, लोमष पहाड़ी की ऊँचाई 250 फीट ऊँची है वहीं मछेंद्र झरना, पचम्बा पहाड़ी बसौनी, चटकरी, डबौर, सपही, और सिगार भूगर्भ में महत्वपूर्ण लोहयुक्त खनिज फैला है। 951 वर्गमील क्षेत्र में फैला नवादा जिला का दर्जा 26 जनवरी 1973 ई. को प्राप्त हुआ, इसके पूर्व 1845 ई. में अनुमंडल की स्थापना हुई थी, 1911 से 1918 ई. में नवदा राजस्व थाना में 663 ग्राम पर हिसुआ, वारसलीगज, गोविंदपुर थाने, पकरीबरावां राजस्व थाना क्षेत्र में 141 गाँव में पकरीवरावां, कौआ कोल तथा रजौली राजस्व

थाने के 295 गाँव में रजौली थाने को मिलाकर नवादा अनुमंडल की स्थापना हुई है, जिले में जर्रा, नरहट, पचरूखी, रोह, समाय परगाने थे। 1808696 आबादी वाले 2492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला नवादा जिले में 1099 गाँवों, 14 प्रखंड, 187 पंचायत तथा 5 विधानसभा क्षेत्र, 159 मध्य विद्यालय, 749 प्राथमिक, 60 उच्च एवं 9 महाविद्यालय तथा मैसकौर और नारहट पठारी युक्त क्षेत्र है। नवादा के उत्तर नालंदा, दक्षिण में कोडरमा, झारखंड, पूरब में शेखपुरा तथा पश्चिम में गया जिले की सीमाओं से घीरा है। मागधीय परंपरा का नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विरासत में बिखरी पड़ी है। (अपसंड), अपसढ़ में सेन वंशीय राजा आदित्य सेन द्वारा स्थापित भगवान बराह की मूर्ति एवं उनकी माता श्रीमती पार्वती ने अपसढ़ से 03 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु की मूर्ति तथा मंदिर और धार्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना दरियापुर पार्वत पर्वत पर एवं अपसढ़ में तलाब का निर्माण एवं गुप्त वंश के राजा हर्ष गुप्त द्वारा कई मंदिर का निर्माण कराया गया था, यहाँ गुप्त वंश के राजाओं में कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जिविल गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त था माध व गुप्त ने अपसढ़ को आध्यात्मिक केन्द्र स्थपित किया था, इसकी चर्चा जेनरल कनिंघम ने 1850 ई. में अपने भ्रमण के बाद 1863 ई. में चर्चा अपनी पुस्तक अनियललेजी आफ द लेटर गुप्तास में की है, चीनी यात्री हवेंसंग ने भगवान् बुद्ध ने पर्वत को पार्वती का घर में रहने और

अवलोकितेश्वर की मूर्ति तथा मंदिर की आराधना की एवं मठ में विश्राम करने की व्याख्यान किया है। हर्ष पर्वत पर कश्यप ऋषि का निर्वाण भगवान बुद्ध के चार दिवसीय आवसीय रहने के दौरान हुआ था, राजा हर्ष कोल ने स्तूप एवं सोमनाथ मंदिर का निर्माण तथा भगवान् शिवलिंग की स्थापना की, इसकी चर्चा एम.ए. स्टेन ने इंडियन अंटिक्युरी पुस्तक में की है।

कुर्किहार में 10 वीं सदी बोद्धिसत्व का प्रमुख केन्द्र स्थापित था। यहाँ की मूर्तियाँ ग्रीको बुद्धिस्ट कला जिसे गांधार शैली में स्थापित है। भगवती मंदिर एवं भगवान् बुद्ध का चिन्तन आध्यात्मिक स्थल रजौली से 18 मील की दूरी पर स्थित है। रजौली प्रखंड के क्षेत्रों में सप्त ऋषियों के नाम पर्वत है। अकबरपुर से 8 किलोमीटर उत्तर नानक पंथ मठ है और लोमष गिरि, दुर्वासा गिरि समुद्रतल से 2202 फीट की ऊँचाई है साथ ही श्रृंगी ऋषि के नाम से समर्पित श्रृंगीगिरी है। बौरी में गौर पलक वीर लोरिक का जन्म स्थल है। क्षेत्र में लोरीक के नाम पर लोरिकायन गीत श्रद्धा के गाते हैं। नवादा थाने के सोबिया पर एक मुखी शिवलिंग, माता पार्वती और तीन मंदिर सौभ नदी के किनारे स्थापित है। यह स्थल 300 वर्ष पूर्व शैव धर्म का स्थल था, वारसलीगंज और रजौली में यूनियन बोर्ड का

गठन 1926 ई. में किया गया था। कोवाकोल प्रखंड का क्षेत्र पुरातात्विक एवं प्राचीन कोल संस्कृति से भरा पड़ा है। कौआकोल प्रखंड का क्षेत्र 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला तथा समुद्रतल से 305 फीट ऊँचाई पर बसा 48 गाँवों में 2011 के जनगणना के अनुसार 143439 आबादी में 72416 पुरूष और 71023 महिला निवास करते हैं। प्राचीन काल में कौआकोल को काम्यक वन कहा जाता था। 1860 ई. में प्रथम सेटलमेंट मिस्टर रीडे ने 52 गाँवों को मिला कौआकोल महल की स्थापना की और घटवाली टेनुरे अर्थात विकास की राज बनाया था। श्रृंगी ऋषि गिरी में निर्मात गुफा 16 फीट लबाई, 11 फीट चौड़ाई, 8 फीट ऊँचाई युक्त गोलनुमा गुफा है, जिसे सीतामढ़ी गुफा के नाम से जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमारी को कुष्ठ हो जाने के कारण गुफा में रहने के बाद गुफा के मुख्य द्वार पत्थर के चट्टानों से बंद कर ली थी और सूर्य आराधना में जुट गई थी, तदुपरांत काशी राज के राजकुमार ने अपनी कुष्ट निवारण के लिए पत्थर के चट्टानों को हटाने के बाद गुफा में प्रवेश किया था। गुफा में पड़ी कुष्ठ रोगी से युक्त राजकुमारी और राजकुमार से संपर्क होने के बाद दोनों मिलकर तालाब में डुबकी लगाई, तलाब में डुबकी लगाने के बाद राजकुमारी और राजकुमार को कुष्ठ से मुक्ति मिल गई और दोनों ने विवाह कर रहने लगे इन्हीं से कोल वंश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, बौद्ध ग्रंथों में कोल को कोली, कोल्ली, कोलिय, कोल, नाग, नायक कहा गया है। राजा कोल ने नगर का निर्माण कौआकोल के रूप में किया था। कोल का अंतिम शासक हर्ष कोल और पवन, पल्लव, केली, सर्प और सागर से युद्ध हुआ लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने कोल वंश को पवित्र किया था। कोल वंश के लेट पुत्र और तिवर पुत्री हुई, त्रेता युग में जनकनंदिनी सीता अपने पुत्र लव और कुश अपने सैनिकों के साथ रही थी और गुफा में रहने के कारण गुफा का नाम सीतामढ़ी के नाम से विख्यात है। कौआकोल से 4.5 किलोमीटर पश्चिम मछेंद्र जलप्रपात है। यह स्थल ऋषि दत्तात्रेय के शिष्य योग के ज्ञाता मछेंद्र ने नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, इन्होंने 8वीं सदी में तंत्र योग सिद्ध का ज्ञान गोरखनाथ को दिया था और योग दर्शन का रूप लेकर

गोरखनाथ सिद्ध हुए, वसौनि, बेलम, चटकारी, डुबौर, सपही और सिंगार पहाड़ी लौहयुग्त पचम्बा पहाड़ी से ख्याति प्राप्त है। जहाँ लौह अयस्क भरपूर मात्रा में है। सुंग पहाड़ का प्राचीन नाम श्रृंगीगिरि में कोहवरावा पहाड़ी में जोगिया मदन गुफा है जहाँ सतयुग में इक्ष्वाकु वंश की राज कुमारी और काशी के राजकुमार के साथ समागम हुआ था। बाद में कोल राजा ने गुफा का कोहवर गृह में चित्रकारी का रूप दे कर शादी में कोहबर संस्कृति का रूप दिया है। आज भी वर और कन्या के लिए चित्रकारी कर मागधीय संस्कृति प्रकट है। यहाँ मनिक संप्रदाय का प्रारंभिक क्षेत्र है। गुनिया जी स्थल में भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी का जन्म स्थल और कर्मभूमि है, द्वापर युग की हड़िया सूर्य मंदिर एवं मूर्ति स्थापित है। सोखोदेवरा में लोकनायक

जयप्रकाश नारायण ने 1942 की क्रांति की शुरूआत और 1952 में भूदान आंदोलन का प्रारंभ तथा सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। काम्यक वन में दुर्वासा ऋषि के नाम पर धूर्वाशाही पर्वत, दूर्वा पर्वत समुद्रतल से 2202 फीट की ऊँचाई पर है। यहाँ के त्रेता युग का राजा निगस ने अपने घमंड के कारण ऋषियों एवं जनता त्राहिमाम हो गए थे। दुर्वासा ऋषि के शाप से सर्प योनि में दुर्वापर्वत राजा नीगास विचरने लगे। दुर्वा पर्वत की श्रृंखला ककोलत पर रह कर सर्प योनि से मुक्ति के लिए दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की जिससे जल प्रपात का रूप धारण कर आम लोगों की शीतलता प्रदान करने लगा। फलत: ककोलत जलप्रपात के नाम से विख्यात है। इस जलप्रपात में स्नान एवं भगवान शिव तथा निगास की उपासना से सर्प योनि से मुक्ति ओर सर्प दंस से छुटकारा मिलता है। द्वापर युग में पांडों ने राजा कोल को सर्प योनि से मुक्ति दिलाई। ककोलत जल प्रपात 160 फीट की ऊँचाई से भूमि पर गिरता है, यह जल प्रपात का जल मीठा और काफी शीतल है। बिहार का ककोलत जलप्रपात ठंडा युक्त और शीतल है। वहीं राजगीर का जल गर्म के लिए प्रसिद्ध है। बोलता पहाड़ी जिसे इको हिल कौआकोल थाने से 500 गज की दूरी पर अवस्थित हे। 20 वगफीट में फैला पहाड़ी के पत्थर से पत्थर टकराने पर इंसान की आवाज निकलती है। यह बोलता पहाड़ी प्रसिद्ध है। शुंगा पहाड़ी की तलहटी रूपे में दैत्य राज शुंभ को बध माता शुभंकारी ने की थी, जिसे माता चामुंडा के रूप में प्रसिद्ध है। रूपमयी चामुंडा की स्थापना शुंग वंश के राजा ने मूर्ति चामुंडा देवी की मूर्ति तथा मंदिर निर्माण कराया था, प्राचीन मंदिर प्राकृतिक आपदा के कारण समाप्त हो गई थी, परन्तु ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ, यह स्थल मौर्य, गुप्त, शुंग, सेन काल में प्रसिद्ध था। जय मगध जय नवादा जय बिहार।●